HVS/L6/3

हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

20 मार्च, 1995

खण्ड 1, अंक 9

अधिकृत विवरण

Haryana Vidhan Sabha Secretariat * Chandigarh * LIBRARY

विषय सूची

सोमवार, 20 मार्च, 1995

	पृष्ठ संख्या
शोक प्रस्ताव	(9)1
तारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(9)1
नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गये तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर	(9)23
अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(9)24
ध्यानाकर्षण प्रस्तावों/नियम-84 के अधीन प्रस्तावों की सूचनाएं	(9)29
प्रो0 छतरपाल सिंह के निलम्बन को रद्द करने सम्बन्धी मामला उठाना	(9)30
ध्यानाकर्षण प्रस्तावों/नियम 84 के अधीन प्रस्तावों की सूचनाएं (पुनरारम्भ)	(9)31
प्रो0 छतरपाल सिंह के निलम्बन को रद्द करने सम्बन्धी मामला उठाना (पुनरारम्भ)	(9)31
श्री करण सिंह दलाल, एम0 एल0 ए0 द्वारा श्री रामरत्न, एम0 एल0 ए0 को धमकी देने तथा उनके विरुद्ध कार्यवाही करने सम्बन्धी मामला	(9)31

मूल्य :

174

	पृष्ठ संख्या
प्रो0 छतरपाल सिंह के निलम्बन को रद्द करने सम्बन्धी मामला उठाना (पुनरारम्भ)	(9)32
वैयक्तिक स्पष्टीकरण—	
श्री कर्ण सिंह दलाल द्वारा	(9)36
ध्यानाकर्षण प्रस्ताव—	
जिला भिवानी में उठान सिंचाई योजना की खराब मशीनों को बदलने सम्बन्धी	(9)36
वक्तव्य—	
सिंचाई मन्त्री द्वारा उक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव सम्बन्धी	(9)37
वर्ष 1995-96 के बजट पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)	(9)39
वैयक्तिक स्पष्टीकरण—	
श्री राजेन्द्र सिंह बिसला द्वारा	(9)61
वर्ष 1995-96 के बजट पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)	(9)62
बैठक का समय बढ़ाना	(9)86
वर्ष 1995-96 के बजट पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)	(9)86
बैठक का समय बढ़ाना	(9)89
वर्ष 1995-96 के बजट पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)	(9)89

ERRATA

TO

Haryana Vidhan Sabha debates Vol. 1, No. 9, dated the 20th March, 1995.

Haryana Vidhan Sabha Secretariat * Chandigarh LIBRARY

Read	For	Page	Line
पत्ते	पत्त	3	1
बी0	ो0	7	14
होंगे	ोगों	7	16
महोदय	महोध्य	18	1
कार्य	काय	30	8
ये	य	32	1
कोशिश	कांशश	48	21
भेज	भज	55	16
लाठी	लाटी	62	3
सम्बन्धित	संधंधित	65	5
बैठते	बठते	67	1
मुंह	मंह	67	23
ईंट	इट	67	27
शिक्षा	ाक्षा	68	3
रहा	रही	79	15
स्लैब	सलब	80	25
तीन परसैंट	तीन	80	30
पेहवा	पहेवा	81, 84	35, 25
छिन	छिन्न	90	23
आरोप	अरोप	91	6

हरियाणा विधान सभा

सोमवार, 20 मार्च, 1995

हरियाणा विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर-1, चण्डीगढ़ में 14.00 बजे हुई। अध्यक्ष (चौधरी ईश्वर सिंह) ने अध्यक्षता की।

शोक प्रस्ताव

मुख्य मन्त्री (चौधरी भजन लाल) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी इजाजत से एक शोक प्रस्ताव रखना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, श्री हरगोविन्द मक्कड़ एक प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्त्ता थे। वे हरियाणा विधान सभा के सदस्य तथा हरियाणा विकास निगम के अध्यक्ष श्री अमीर चन्द मक्कड़ के पिता थे। उनका गत 17 मार्च, 1995 को निधन हो गया। श्री हरगोविन्द मक्कड़ एक सामाजिक कार्यकर्त्ता थे और वे समाज के हर कार्यक्रम में समाज के उत्थान के लिए बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेते थे।

यह सदन दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

श्री अध्यक्ष : आप सबसे प्रार्थना है कि उनकी आत्मा की शांति के लिए आप दो मिनट का मौन धारण करने के लिए खड़े हो जाएं।

(At this stage the House stood in silence for 2 minutes as a ,mark of respect to the memory of deceased)

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

श्री अध्यक्ष : आनरेबल मैम्बर्ज, अब सवाल होंगे।

Repair of Road

@***1047. Shri Bharath Singh :** Will the Minister for P.W.D. (B&R) be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to repair the damaged road from Balu to Kassan ; and

(b) if so, the time by which the said road is likely to be repaired ?

@Put by Sh. Zile Singh Jakhar.

लोक निर्माण मंत्री (चौधरी अमर सिंह) :

(क) बालू से कसान सड़क पर पैच कार्य (मरम्मत) कर दिया गया है ।

(ख) उपरोक्त (क) अनुसार प्रश्न नहीं उठता ।

चौधरी जिले सिंह जाखड़ : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने अपने जवाब में कहा है कि सड़क की रिपेयर कर दी गई है । सवाल देखने से तो ऐसा लगता है कि इस सड़क की रिपेयर नहीं की गई क्योंकि अगर रिपेयर की गई होती तो माननीय सदस्य इस सवाल को पूछते ही नहीं । क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि इस सड़क पर कितना पैच वर्क हुआ है और उस पर कितना पैसा लगा है ?

चौधरी अमर सिंह : इस सड़क की लम्बाई 5.90 कि0 मी0 है । यह सड़क 1971 में बनी थी और इसके पैच वर्क पर 7 लाख 50 हजार रुपये खर्च हुआ है । 4/94 से 1/95 के बीच में इसकी मुरम्मत की गई है । इसकी सरफेसिंग पर 8 लाख 79 हजार रुपया खर्च आया है । इस सड़क पर 4/4/94 से 1/1/95 तक कुल 20 लाख 20 हजार रुपया मुरम्मत आदि पर खर्च किया गया है ।

प्रो0 राम बिलास शर्मा : क्या मंत्री महोदय टैक्नीकली तौर पर अपने अनुभव के आधार पर बताएंगे कि पैच वर्क में और रिपेयर में क्या अन्तर होता है ?

चौधरी अमर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से अपने सदस्य साथी को बताना चाहूंगा कि जब सड़क टूट जाती है तो पहले पैच वर्क का ही काम किया जाता है यानि जो खड्डे होते हैं, उनको भरा जाता है और फिर बाद में यदि पूरी सड़क की मुरम्मत की जाती है तो उसे रिपेयर कहते हैं । यानि पैच वर्क के बाद ही रिपेयर के समय पूरी सड़क की तारकोलिंग आदि की जाती है ।

प्रो0 छतर सिंह चौहान : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने बताया है कि हमने इतने का पैच वर्क का काम किया है । मैं बताना चाहूंगा कि पैच वर्क के नाम से ये उन खड्डों में दो रोड़ी और चार आक के पत्ते डाल देते हैं जिससे कोई लाभ नहीं होता । खड्डे वहां बराबर बने रहते हैं । मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि इन्होंने भिवानी जिले में बवानी खेड़ा के अन्दर कितने पैसों का पैच वर्क का काम किया है । क्योंकि पैच वर्क के नाम पर काम करते कुछ नहीं और पैसा इधर-उधर कर देते हैं और कागजों में पैच वर्क और रिपेयर दिखा दी जाती है । कृपया मंत्री महोदय बताएं कि भिवानी जिले में कितने पैसे से रिपेयर आदि की गई है ?

चौधरी अमर सिंह : स्पीकर सर, मेरे लायक दोस्त खूब अच्छी तरह से जानते हैं और हाउस के बाहर इस बात को मानते भी हैं कि पूरे हरियाणा में 21,579 किलोमीटर सड़कें हैं तथा 6,547 गांव हरियाणा में सड़कों से जुड़े हुए हैं और

इसमें 28-2-1995 तक पैच वर्क पूरा करा दिया गया है । जहां तक आक के पत्ते डालने वाली बात कही है तो मैं इनको बताना चाहूंगा कि न तो कहीं आक के पत्ते डाले जाते हैं और न नीम के पत्ते डाले जाते हैं । ऐसी कोई बात नहीं । हर जिले में हर डिवीजन में मोबाईल वैन बनी हुई है । मशीनों से रोड़ी मिक्सचर बना कर बाकायदा एक-एक दिन में 10-10 या 15-15 किलोमीटर रोड का पैच वर्क और मुरम्मत कार्य पूरा हुआ है ।

श्री अध्यक्ष : एक बात मैं भी आपसे पूछ लेता हूं कि क्या कहीं सड़कों पर कच्ची मिट्टी डाल कर भी खड्डों को भरा जाता है ?

चौधरी अमर सिंह : अध्यक्ष महोदय, ऐसी कोई बात नहीं है । कल मैं आपके ही हल्के में था । आपके हरियाणा की रोड्ज़ इतनी चमचमा रही हैं कि जिसका कोई अन्दाज़ा नहीं है । जिस प्रकार से आपके हल्के की रोड्ज़ चमचमा रही हैं, तकरीबन उसी तरह से पूरे हरियाणा में ही हर जगह की सड़कें चमचमा रही हैं । यहां पर मैं यह बताना चाहूंगा कि कहीं पर भी कोई खड्डा मिट्टी से नहीं भरा जाता है । उसमें रोड़ी भरी जाती है । बाकायदा दुरमुट से उसकी कुटाई की जाती है । तब उस पर लुक वगैरह डालते हैं। (विघ्न)

प्रो0 छत्तर सिंह चौहान : अध्यक्ष महोदय, अभी मन्त्री महोदय ने बताया कि आपके हल्के की सड़कें चमचमा रही हैं । आपके हल्के के नजदीक के गांव जुण्डला में पिछले 4 साल से कोई कार्य नहीं हुआ । इसी प्रकार से मुण्डाल से जीन्द जो सड़क आती है, उस पर 3-3 फुट खड्डे पड़े हुए हैं । उस सड़क पर कोई पैच वर्क नहीं हुआ है । मन्त्री जी को पहले कुछ कम अनुभव था । अब शायद और अधिक अनुभव दिलाने के लिए उनको मंत्री बनाया गया है ताकि वे कागजी आंकड़े बनाने में कुशल हो सकें । अध्यक्ष महोदय, मैं यह बताना चाहूंगा कि वास्तव में कोई पैच वर्क नहीं हुआ है । हो सकता है यह काम कागजों पर हुआ हो, लेकिन असल ज़मीन पर ऐसा कुछ नहीं हुआ ।

चौधरी अमर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरे ख्याल से माननीय दोस्त कभी मुण्ढाल से जीन्द गए नहीं हैं । यह सड़क बिल्कुल ठीक है । इनको तो दुख केवल इस बात का है कि अमर सिंह मिनिस्टर कैसे बन गया ? हम और मुख्य मन्त्री तो इनको चेयरमैन बनाना चाहते थे । अध्यक्ष महोदय, मैं अपने लायक दोस्त को बताना चाहूंगा कि जुण्डला, मुण्ढाल, भिवानी और जीन्द की सड़कों की मुरम्मत पूरे तौर पर कर दी गई है और पैच वर्क भी पूरा हो गया है । अब सड़क पर कोई खड्डा नहीं है ।

चौधरी भरत सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहूंगा कि बालू से कसान तक सड़क की रिपेयर कब तक हो जाएगी ? अध्यक्ष महोदय, मन्त्री जी यह कह रहे हैं कि सारी स्टेट के अन्दर पैच वर्क कम्पलीट हो गया है । अभी आपने कच्ची मिट्टी से खड्डे भरने की बात भी कही ।

[चौधरी भरथ सिंह]

कथूरा की ऐसी सड़क टूटी हुई है कि उस पर एक-एक फुट के गढ्ढे पड़े हुए हैं और उस पर कोई पैच वर्क या रिपेयर वर्क नहीं हुआ है । आपके माध्यम से मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि इसकी रिपेयर कब तक करवा देंगे ? रिपेयर के नाम पर काला रंग सड़कों पर पोत देते हैं और ज्यों ही रिपेयर वर्क खत्म होता है, काला रंग भी साफ हो जाता है ।

चौधरी अमर सिंह : अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मैं अपने आदरणीय साथी को बताना चाहूंगा कि काला-काला जो सड़क पर डाला जाता है वह काला रंग नहीं बल्कि असली तारकोल होता है । असली तारकोल में रोड़ी मिला कर पैच वर्क किया जाता है । मेरे आनरेबल साथी ने जो जिक्र किया है, वहां पर पैच वर्क ऑलरेडी हो चुका है ।

श्री मनी राम कसावास : अध्यक्ष महोदय, मुझे साढ़े-तीन साल के अर्से में कभी भी बोलने का मौका नहीं मिला । मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि मेरे हल्के में जितनी भी सड़कें हैं, उनकी हालत खस्ता है । उन पर कभी भी रिपेयर होती मैंने नहीं देखी । जितनी भी वहां सड़कें हैं, वे सब टूटी पड़ी हैं । यहां तक कि मार्किट कमेटी की जो रोड्ज़ हैं, उनकी भी मुरम्मत बिल्कुल नहीं की जा रही है । अध्यक्ष महोदय, कोई भी सड़क ऐसी नहीं है, जिस पर मुरम्मत हुई हो । क्या मन्त्री महोदय इस बारे में कुछ रोशनी डालेंगे ?

चौधरी अमर सिंह : अध्यक्ष महोदय, आनरेबल मैम्बर ने कहा है कि इनके हल्के में मार्किट कमेटी की एक सड़क बनी थी और उसकी मुरम्मत नहीं हुई है । तो अध्यक्ष महोदय, इसके इलावा भी कई रोड्ज़ हैं, उन सबकी मुरम्मत हो गई है । अगर ये किसी स्पैसिफिक रोड के बारे में कह रहे हैं तो उसका नाम दे दें, हम उसकी रिपेयर करवा देंगे ।

श्री जय पाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि मेरे हल्के में रेत की खाने हैं जिस वजह से वहां पर बहुत ज्यादा ट्रक चलते हैं और वहां पर कोई भी सड़क ठीक नहीं है । अध्यक्ष महोदय, जब जसवन्त सिंह चौहान जी की मृत्यु हुई थी, तो मैं भी वहां पर गया था और मुख्य मंत्री जी भी गए थे । वहां के रास्ते बहुत खराब थे । तब इन्होंने आश्वासन दिया था कि इस सड़क को जल्दी से बना देंगे और उस के लिए 28 लाख रुपए तक देने की इन्होंने घोषणा भी की थी । दूसरे लक्मी प्याऊ से जमुनापुर तक भी सड़क खराब पड़ी हुई है । वहां पर कोई पटरी नहीं है । जब वहां स्कूल के लड़के-लड़कियां पैदल चलते हैं तो उन्हें बहुत मुश्किल आती है । इन्होंने जो 28 लाख की घोषणा की थी, वह पैसा भी अभी तक नहीं पहुंचा है साथ में ये यह भी बताएं कि ये इन सड़कों को कब तक ठीक करवाएंगे ?

मुख्य मन्त्री (चौधरी भजन लाल) : अध्यक्ष महोदय, ये ठीक कह रहे हैं कि जब जसवन्त सिंह चौहान की मृत्यु हुई थी, तो मैं वहां पर गया था और मैंने उस सड़क को बनवाने का आश्वासन दिया था। अध्यक्ष महोदय, हमने वह सड़क जसवन्त सिंह जी के नाम से बनवा दी है और अगर वह अभी खराब है, तो उसको भी ठीक करवा देंगे।

— — — —

Appointment of S.S. Masters against vacant Posts of J.B.T. Teachers

@*1056. Shri Suraj Bhan Kajal : Will the Minister for Education be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to appoint S.S. Masters against the vacant posts of J.B.T. Teachers in the State ?

Education Minister (Shri Phool Chand Mullana) : No. However, according to the Haryana Primary Education (Group-C) District Cadre Service Rules, 1994, in case of non-availability of Junior Basic Trained teachers, candidates having higher qualifications, such as B.A. B.Ed. or B.Sc. B.Ed. or its equivalent qualifications may be considered for the posts of J.B.T. teachers.

श्री बलवन्त सिंह मायना : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने अपने जवाब में बताया कि जे0 बी0 टी0 टीचर न मिलने की दशा में एस0 एस0 मास्टर्ज से ये पद भरने पर विचार करेंगे। मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि ये रिक्त स्थान कब तक सरकार भर देगी ?

श्री फूल चन्द मुलाना : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य तो वहम में पड़ गए। मैंने इस सवाल का जवाब 'नहीं' में दिया है। ये एस0 एस0 मास्टर्ज के बारे में कह रहे हैं जबकि हमने एस0 एस0 मास्टर्ज को इन पोस्ट्स को भरने के लिये नहीं रखा है। हमने तो यह कहा है कि जे0 बी0 टी0 टीचर न मिलने की दशा में बी0 ए0, बी0 एड0 या बी0 एस0 सी0, बी0 एड0 उम्मीदवारों को रखने के बारे में विचार किया जा सकता है। एस0 एस0 मास्टर्ज की तो अलग कैटेगरी है। जहां तक इन्होंने यह पूछा कि जे0 बी0 टी0 के रिक्त स्थान कब तक भर दिए जाएंगे, तो अध्यक्ष महोदय, हमने यह निर्णय इसलिए लिया क्योंकि जे0 बी0 टी0 टीचरों की सारे प्रान्त में कमी है। पिछली बार भी हमने एस0 एस0 एस0 बोर्ड को करीब 3,088 पोस्टें भरने के लिए लिखा था जिसमें से हमें केवल 941 टीचर ही जे0 बी0 टी0 के मिल पाए थे। इसीलिए मुख्य मंत्री जी ने आदेश दिया था कि जे0 बी0 टी0 टीचर की जगह बी0 एड0 रख लिए जाएं। अब हमने एस0 एस0 एस0 बोर्ड को 5,160 वैकेंसिज की मांग भेजी है और बोर्ड ने इंटरव्यू भी लेने शुरू कर दिए हैं। इसलिए अध्यक्ष महोदय, अगले सत्र में जे0 बी0 टी0 टीचर्ज की सारी कमी पूरी कर दी जाएगी।

@ Put by Sh. Balwant Singh Maina

प्रो० छत्तर सिंह चौहान : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जे० बी० टी० टीचर की पोस्टों के अगेन्सट जो यह ट्रेंड लोग लगा रहे हैं, तो उनको ये कौन सा ग्रेड देंगे ? क्या उनको बी० ए०, बी० एड० या बी० एस० सी०, बी० एड० वाला ग्रेड दिया जाएगा ? अध्यक्ष महोदय, कई साल पहले हाईकोर्ट भी इस बारे में अपना फैसला दे चुकी है कि चाहे कोई बी० ए०, बी० एड० लगा हो या मास्टर लगा हो और यदि वह पांचवीं क्लास को भी पढ़ाता है तो भी उसको ग्रेड बी० एड० का ही देना पड़ेगा । क्या सरकार उनको कोर्ट के आर्डर के मुताबिक बी० ए०, बी० एड० का ग्रेड देगी या जे० बी० टी० का ग्रेड देगी ? अगर उनको जे० बी० टी० का ग्रेड दिया गया तो वे लोग फिर कोर्ट में चले जाएंगे क्योंकि कोर्ट ने पहले ही उनके हक में अपनी रूलिंग दी हुई है । इसके अलावा क्या हरियाणा स्टेट में जे० बी० टी० टीचर्ज का नितान्त अभाव है और अगर इनका अभाव है तो फिर सरकार जे० बी० टी० इंस्टीच्यूशंज को और बढ़ाकर इन टीचर्ज की कमी को क्यों नहीं पूरा करती ?

श्री फूल चन्द मुलाना : अध्यक्ष महोदय, छत्तर सिंह जी ने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है । हमने जो जे० बी० टी० की पोस्टों पर बी० ए०, बी० एड० या बी० एस० सी०, बी० एड० लोगों को रखने के लिए ऑप्शन दे रखी है, उनसे बाकायदा तौर पर अंडरटेकिंग ली है कि वे जे० बी० टी० का ही ग्रेड लेंगे । इसलिए उनके द्वारा कोर्ट में जाने का क्वैश्चन ही नहीं है । इसलिए ये जे० बी० टी० की सारी पोस्टें भर ली जाएंगी । जहां तक इन्होंने कहा कि जे० बी० टी० टीचरों की कमी को पूरा करने के लिए क्यों नहीं जे० बी० टी० इंस्टीच्यूशंज बढ़ाए जाते, तो अध्यक्ष महोदय, अभी भी हमारे प्रान्त के अन्दर कई जे० बी० टी० सैन्टर्ज चल रहे हैं और जिनमें दाखिला भी हर साल होता है । इस बार भी इनका जो रिजल्ट निकला है, उसमें से दो हजार जे० बी० टी० हमें उपलब्ध हो जाएंगे और अगले साल भी इतने ही और लोग ट्रेनिंग लेकर हमारे पास आ जाएंगे ।

श्री अजमत खां : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने कहा कि हर साल इनके पास दो हजार लोग ट्रेनिंग लेकर आते रहेंगे । अध्यक्ष महोदय, सरकार को क्या पता नहीं है कि स्टेट में जे० बी० टी० टीचर्ज की कमी है और अगर इनको पता था कि इनकी स्टेट में कमी थी तो इन्होंने पहले से ही क्यों नहीं ज्यादा स्कूल इनके लिए खोले ? क्या आज इसी कमी की वजह से बी० ए०, बी० एड० या बी० एस० सी०, बी० एड० पढ़े लोग जे० बी० टी० की जगहों पर लेने पड़ रहे हैं । इनका जो बैकलाग चल रहा है तो क्या सरकार इस बैकलाग को पूरा करने के लिए जे० बी० टी० के और सैन्टर्ज खोलकर और जे० बी० टी० टीचर पैदा करेगी ?

श्री फूल चन्द मुलाना : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने यह सवाल पूछा कि जे० बी० टी० के टीचर्ज की क्यों कमी रही है ? अध्यक्ष महोदय, नयी एजुकेशन पोलिसी के तहत भारत सरकार ने यह निर्णय लिया है कि सरकारी तौर पर हर जिले में एक डी० एड०

सैंटर यानि डिप्लोमा इन ऐजुकेशन का ट्रैनिंग सैन्टर जिसको जे0 बी0 टी0 भी कहते हैं, खोला जाए । अध्यक्ष महोदय, इसकी फार्मेलिटिज ही पूरी करने में काफी समय लग गया लेकिन अब वे केसिज तैयार हो गए हैं। अब हर जिले में एक तो इस तरह का सैंटर होगा ही । इसके अलावा और भी जहां-जहां जे0 बी0 टी0 सैंटर चल रहे हैं, वहां से हमारे पास बच्चों की इतनी तादाद आएगी कि हर साल करीब दो हजार बच्चे ट्रैनिंग लेकर हमारे पास आते रहेंगे ।

श्री कृष्ण लाल : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि 1991 में अप-टू-डेट कितने जे0 बी0 टी0 टीचर के अगेंस्ट बी0 एड0 टीचर रखे हैं, उनका जिलेवार पूरे प्रदेश का ब्यौरा दें ?

श्री फूल चन्द मुलाना : अध्यक्ष महोदय, मैम्बर साहब सवाल समझ नहीं पाए । अभी तक जे0 बी0 टी0 के अगेंस्ट कोई बी0 एड0 टीचर नहीं रखा गया, लेकिन अब इस बार से हमारी यह प्रक्रिया मुख्य मंत्री जी ने कैबिनेट से एप्रूव करवा के शुरू की है ताकि जे0 बी0 टी0 का अभाव न रहे और अब जो बी0 एड0 रखेंगे, उनको हम बी0 एड0 भी धीरे-धीरे लगाते जाएंगे ।

श्री अध्यक्ष : जिन बी0 एड0 को जे0 बी0 टी0 की जगह रखेंगे, क्या वे पक्के होंगे ?

श्री फूल चन्द मुलाना : अध्यक्ष महोदय, वे पक्के होंगे । बोर्ड के माध्यम से रख रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष : और जब बी0 एड0 की वैकैन्सी होगी क्या उनको प्रमोट कर देंगे ?

श्री फूल चन्द मुलाना : अध्यक्ष जी, आप तो बहुत पुराने एजुकेशनिस्ट हैं । बी0 एड0 के हमारे यहां बहुत कालेजिज हैं और आज भी मैं यदि आपको पूरी इन्फर-मेशन दूं । (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : मेरा सवाल यह है कि जिनको जे0 बी0 टी0 की जगह लगाएंगे जब बी0 एड0 की वैकैंसीज होंगी तभी उनमें उनको प्रमोट करेंगे ?

श्री फूल चन्द मुलाना : बिल्कुल करेंगे, यह तो फिक्स है स्पीकर सर ।

मुख्य मन्त्री (चौधरी भजन लाल) : अध्यक्ष महोदय, जे0 बी0 टी0 टीचर की कमी के कारण यह फैसला लिया गया है । दूसरे बी0 एड0 टीचर बेकार फिरते हैं। उनकी आवश्यकता नहीं है उन्होंने खुद आकर कहा कि हमें आप जे0 बी0 टी0 की पोस्ट पर लगा दो ताकि हमारा कुछ गुजारा चले । इसी बात को लेकर कैबिनेट ने फैसला लिया और जब भी कोई बी0 एड0 की पोस्ट निकलेगी, उसमें भी वे एप्लाई

[चौधरी भजन लाल]

कर सकेंगे । उसमें वे एपीयर हो सकते हैं । कायदे के मुताबिक तो उनको प्रमोशन मिलेगी ही, वह नंबर पर मिलेगी । लेकिन अगर कोई पोस्ट निकलती है तो वे उसमें भी ऐप्लाई कर सकते हैं । उसमें कोई बैन नहीं होगा ।

प्रो० सम्पत सिंह : स्पीकर सर, आपने जो सवाल पूछा था, उसमें बात कुछ अधूरी रह गई । माननीय मंत्री जी ने कहा कि उनसे हम अंडरटेकिंग ले रहे हैं । स्पीकर सर, अंडरटेकिंग चाहे ले लें, लेकिन एक बार जिस एम्पलाई ने जे0 बी0 टी0 लगकर बी0 एड0 की हो, चाहे जे0 बी0 टी0 की पोस्ट के अगेंस्ट बी0 एड0 लगा हो, चाहे आलरेडी बी0एड0 कर चुका हो, बाद में जे0 बी0टी0 की पोस्ट के अगेंस्ट लगा हो जैसे गवर्नमैंट अब ले रही है, वह ग्रेड के लिए गवर्नमैंट को बाध्य कर सकता है और कोर्ट के यह आर्डर हैं । एक बार बी0 ए0, बी0 एड0 आदमी जे0 बी0 टी0 या किसी पोस्ट के अगेंस्ट लग गया उसे आपको बी0 एड0 का ग्रेड देना ही पड़ेगा । (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : क्वैशचन पूछिए ।

प्रो0 सम्पत सिंह : स्पीकर सर, मैं सवाल ही पूछ रहा हूं कि क्या अंडरटेकिंग से काम चल जाएगा ? क्या उनको बी0 ए0, बी0 एड0 का ग्रेड नहीं देना पड़ेगा ? प्रमोशन अलग चीज है । ग्रेड अलग चीज है । क्या उनको बी0 एड0 का ग्रेड नहीं देना पड़ेगा ? जो पोस्टें अवेलेबल होती हैं, ज्यों-ज्यों पोस्ट आती रहती हैं, क्या ग्रेड उनके हिसाब से नहीं मिलता है ?

श्री फूल चन्द मुलाना : स्पीकर सर, चौधरी सम्पत सिंह जी ने जो सवाल पूछा है उस बारे मैं बता देता हूं कि प्रमोशन का हमारा जे0 बी0 टी0 से बी0 एड0 का कोटा है । जे0 बी0 टी0 से बी0 एड0 प्रमोट होते रहेंगे लेकिन अब हमको ग्रेड बी0 एड0 का नहीं देना पड़ेगा क्योंकि हमने शर्तें ऐसी बनाई हैं । रूल्ज में अमैंडमैंट करके बोर्ड को एडवरटाईजमैंट भेजी हैं। उनको बी0 एड0 का ग्रेड नहीं देंगे, जे0 बी0 टी0 का देंगे । बाद में जो बी0 एड0 की पोस्ट पर प्रमोट हो जाएंगे उनको बी0 एड0 का ग्रेड देंगे ।

Recruitment made in Haryana Education Board

*1108. **Shri Ram Bhajan Aggarwal :** Will the Education Minister be pleased to state the categorywise number of persons appointed on regular/temporary basis in Haryana Education Board during the year 1994-95, togetherwith the criteria adopted for the said appointments ?

Education Minister (Shri Phool Chand Mullana) : Information is laid on the Table of the House.

INFORMATION

During 1994-95, 58(Fifty Eight) persons have been appointed so far. Out of these, 50 employees have been appointed through Employment Exchange/State Sainik Board, Haryana, Four Employees have been appointed on compassionate grounds being members of the families of the Board's deceased employees. One Ex-Employee after his premature retirement has been taken back in service due to his family circumstances. The employees whose names were sponsored by the Employement Exchange/State Sainik Board were appointed after prescribed test and interview.

One Director for Open School for a period of two years has been appointed on the recommendations of State Government. Two consultants have been engaged who are retired Deputy Secretaries of this Board.

No temporary/adhoc appointments have been made during the said period.

Category-wise No. of persons appointed during the year 1994-95 is given as under :—

Sr.No.	Posts	Appointment
1.	Clerks	42
2.	Security Employees	8
3.	Peon	3
4.	Cook-cum-Attendant	1
5.	Proof Reader	1
6.	Director	1
7.	Consultants	2

श्री राम भजन अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि एजुकेशन बोर्ड में जो 58 का स्टाफ रखा है, उनमें से शिडयूल्ड कास्ट कितने हैं ? क्या शिडयूल्ड कास्ट को उनकी पूरी रिप्रेजेन्टेशन दी है ? क्या एड-हाक बेसिज पर नहीं रखे ? डेली वेजिज पर कितने आदमी रखे हैं ? उनका रखने का क्या क्राइटेरिया है ?

श्री फूल चन्द मुलाना : अध्यक्ष महोदय, एजुकेशन बोर्ड में स्टाफ की स्ट्रैन्थ 1,280 की है । माननीय सदस्य ने जो सवाल पूछा है । उनकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि पिछले दिनों हमने 42 क्लर्क रखे हैं, 8 सिक्योरिटी एम्पलाईज, 3 पीअन्ज, 1 कुक-कम-अटैंडैंट, एक प्रूफ रीडर, एक डायरैक्टर और दो कंसल्टैंटस रखे हैं ।

[श्री फूल चन्द मुलाना]

सरकार की नीति के अनुसार रिजर्वेशन का पूरा ध्यान रखा जाता है। इसके बाद इन्होंने यह पूछा कि डेली वेजिज पर कितने आदमी रखे गये हैं? मैं इन को बताना चाहता हूं कि काफी सारी वेकेन्सीज एजुकेशन बोर्ड में इस तरह की होती हैं। पिछली बार हमने कुछ आदमी एम्पलायमैंट एक्सचेन्ज के माध्यम से और कुछ सोल्जर बोर्ड की रिकमैंडेशन से लगाए हैं। यह भी पूछा है कि डेली वेजिज पर क्यों लगाए? तो मैं उन को यह बताना चाहता हूं कि कुछ पोस्टें बोर्ड में खाली थीं। लोगों से काम लेने के लिये लगातार हर महीने इस तरह की भर्ती होती रहती है। अप्रैल 1994 से आज तक की फिगर्ज मेरे पास हैं। इनमें से किसी को भी 180 दिनों से ज्यादा नहीं रखा जाता। जिस विभाग में, जैसे-जैसे जरूरत होती है, जैसे-जैसे काम होता है, वैसे-वैसे ही रखते रहते हैं और डी०सी० के रेट पर रखा जाता है। मैं बता भी देता हूं कि मार्च, 1995 में भिवानी में 122 और पंचकूला में 36 लगाये गये जिनका टोटल 158 बनता है, जोकि डेली वेजिज पर रखे हुए हैं। पिछले साल की फिगर्ज भी अगर माननीय सदस्य जानना चाहें, तो मेरे पास वह भी अवेलेबल हैं। मैं वह भी बता सकता हूं।

साथी लहरी सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदय ने अपने जवाब में अभी कहा कि अनुसूचित जाति के लोगों का भी पूरा ध्यान रखा जाता है। क्या मन्त्री जी बताएंगे कि यह जो 1,280 का स्टाफ इन्होंने बताया, उसमें शिड्यूल्ड कास्ट की क्या पोजीशन है? कितने अनुसूचित जाति के हैं? और अब जो 58 की लिस्ट इन्होंने अपने जवाब में दी है, उनमें कितने अनुसूचित जाति से रखे गये हैं? यह बात भी क्लीयर करें।

श्री फूल चन्द मुलाना : अध्यक्ष महोदय, इनसे ज्यादा अनुसूचित जाति के लोगों का फिकर मुझे है और अब इनको यह जानकर खुशी होगी कि इस बारे में सरकार पूरा ध्यान रखती है और हमने रिजर्वेशन का जितना बैकलाग था, वह सारा पूरा कर दिया है। परमोशन का भी बैक लाग पूरा कर दिया है।

साथी लहरी सिंह : स्पीकर सर, मेरे सवाल का पूरा जवाब नहीं आया है। इन्होंने अलग फिगर्ज नहीं दी हैं। मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि इनमें कितने हरिजन क्लर्क, कितने सहायक और कितने आफिसर्ज व कुक आदि के पदों पर लगाए गये हैं? उनकी सही संख्या बताने का कष्ट करें।

श्री फूल चन्द मुलाना : अध्यक्ष महोदय, मेरा माननीय साथी से कहना यह है कि यह सवाल पहले नहीं पूछा गया था। अगर वे इसके लिये अलग से नोटिस देंगे तो मैं सारी सूचना उनको फिगर्ज सहित बतला दूंगा।

Cases of Murder/Theft/Dacoity etc. registered in Faridabad District

*1074. **Shri Karan Singh Dalal :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the number of cases of Murder, Theft/Dacoity registered in each Police Station of District Faridabad during the period from Ist January, 1994 to March, 1995 ; and

(b) the number of cases, out of those as referred to in part (a) above the accused have not been arrested so far ?

मुख्य मन्त्री (चौधरी भजन लाल) : सूचना सदन के पटल पर रखी जाती है ।

भाग (क) तारांकित विधान सभा प्रश्न संख्या 1074 के उत्तर की विवरण तालिका

थानों का नाम	शीर्षकों में दर्ज हुए मुकदमों की कुल संख्या					
	हत्या		चोरी		डकैती	
	1994	1995 (28-2-95 तक)	1994	1995 (28-2-95 तक)	1994	1995 (28-2-95 तक)
सैन्ट्रल फरीदाबाद	7	1	162	24	4	—
एन0 आई0 टी0 फरीदाबाद	13	—	75	13	—	—
शहर बल्लबगढ़	1	—	44	10	—	—
सदर बल्लबगढ़	8	1	27	2	—	—
शहर पलवल	5	—	38	5	1	—
सदर पलवल	5	1	41	7	—	1
हथीन	5	1	25	2	—	—
होडल	3	—	22	1	5	—
हसनपुर	4	2	6	—	—	—
छायंसा	2	1	30	6	3	—
मुजेसर	3	1	26	10	—	—
कोतवाली	1	—	71	16	1	—
ओल्ड फरीदाबाद	3	2	25	5	1	—
सराय ख्वाजा	—	—	16	6	1	—
योग	60	10	608	107	16	1

[चौधरी भजन लाल]

उपरोक्त भाग (क) में दर्शाये गये

भाग (ख) शीर्षकों के अधीन मुकदमों की संख्या जिनमें दोषी गिरफ्तार नहीं हुए

थानों के नाम	हत्या		चोरी		डकैती	
	1994	1995 (28-2-95 तक)	1994	1995 (28-2-95 तक)	1994	1995 (28-2-95 तक)
सैन्ट्रल फरीदाबाद	4	1	96	20	1	—
एन0 आई0 टी0 फरीदाबाद	2	—	29	10	—	—
शहर बल्लबगढ़	—	—	8	8	—	—
सदर बल्लबगढ़	—	1	12	1	—	—
शहर पलवल	1	—	8	4	—	—
सदर पलवल	—	—	28	5	—	1
हथीन	1	—	14	1	—	—
होडल	1	—	11	1	—	—
हसनपुर	—	—	4	—	—	—
छायंसा	—	1	15	4	—	—
मुजेसर	—	—	7	7	—	—
कोतवाली	1	—	32	10	—	—
ओल्ड फरीदाबाद	1	1	10	3	—	—
सराय ख्वाजा	—	—	4	4	—	—
कुल योग	11	4	278	78	1	1

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मुख्य मन्त्री महोदय ने जो सूचना सदन के पटल पर रखी है उसमें उन्होंने अलग अलग फिगर्ज दी हैं कि 1994-95 में कुल हत्याएं 70, चोरियां क्रमशः 608 व 107 और डकैतियां क्रमशः 16 व 1 हुई हैं। मैं आपके माध्यम से उन से यह जानना चाहता हूं कि जिला फरीदाबाद में ही यह सारे जुर्म क्यों हुए हैं ? कहीं इसका कारण यह तो नहीं है कि वहां पलवल व फरीदाबाद में दो बिश्नोई डी0 एस0 पीज0 तैनात हैं और वे इन वारदातों को रोकने में नाकाम रहे हैं (शोर)

श्री अध्यक्ष : कर्ण सिंह जी, आप पर्सनल कोई बात न कहें। (शोर) क्वेश्चन की फार्म में ही पूछिए। (शोर)

चौधरी भजन लाल : कहने दो, कहने दो इन्हें स्पीकर साहब। (शोर)

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, जब सी0 एम0 साहब को इस बारे में कोई एतराज नहीं है तो किसी को क्या एतराज हो सकता है (शोर) तो मैं कह रहा था कि कहीं इस का कारण यह तो नहीं है कि वहां पलवल व फरीदाबाद में दो बिश्नोई डी0 एस0 पीज0 तैनात हैं और वे इन वारदातों को रोकने में नाकाम क्यों रहे हैं। (शोर)

श्री अध्यक्ष : कर्ण सिंह जी, आप क्वेश्चन की फार्म में पूछिये।

श्री कर्ण सिंह दलाल : मैं आपके द्वारा मुख्य मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि ये उन अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही करेंगे, जो अभी तक मुलजिमों को पकड़ नहीं सके ? दूसरे, क्या ये जानते हैं कि जो इन्होंने फरीदाबाद जिला के केस बताए हैं, उनमें से 9 आदमी अभी तक पकड़े नहीं गए हैं। तो मैं जानना चाहता हूं कि फरीदाबाद में बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था को देखते हुए अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही करेंगे।

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, यह बात तो ठीक है कि फरीदाबाद में क्राईम कुछ ज्यादा है। क्यों ज्यादा है ? आप जानते हैं कि वह एक बड़ी भारी औद्योगिक नगरी है। फरीदाबाद सारे देश में उद्योग के हिसाब से दसवें नम्बर पर है। वहां पर बहुत आबादी है। उसके एक तरफ तो राजस्थान लगता है और एक तरफ यू0 पी0 लगता है। यू0 पी0 साईड के कुछ लोग वहां पर वारदात करके भाग जाते हैं ऐसे कई वाक्यात हुए भी हैं। इस बारे में एक आल इंडिया सर्वे भी हुआ है कि कौन-कौन से पुलिस स्टेशनों में क्राईम ज्यादा है। मेरे पास सारा रिकार्ड

[चौधरी भजन लाल]

है । कोई भी प्रदेश ऐसा नहीं है जिसमें 5, 7 या 10 जिलों में क्राईम नहीं होते । हरियाणा में केवल फरीदाबाद जिले में क्राईम ज्यादा है । हमने इनकी रोक थाम के लिए पूरी कोशिश की है । इन्होंने कहा कि वहां पर दो डी0 एस0 पी0 बिश्नोई हैं । ये भी मेरे वक्त में भर्ती नहीं हुए बल्कि ये मेरे से पहले के भर्ती किए हुए हैं । तो उन्होंने कहीं तो लगना ही है । यह कोई बात नहीं है कि वहां पर बिश्नोई लगे हुए हैं इसलिए चोरी और डकैती वहां पर ज्यादा है । मेरे लिए तो ऐसे ही जाट हैं, ऐसे ही हरिजन हैं और ऐसे ही ब्राह्मण हैं । मेरे लिए तो 36 बिरादरी भाई के समान हैं । जो अधिकारी काम नहीं करते हैं, हम उनके खिलाफ एकशन लेते हैं । दलाल साहब भी वहीं बसते हैं और आपके भाई बन्धु भी मेरे पास आते हैं । वहां पर केवल 5–6 केसिज में ही मुलजिम पकड़े नहीं गए लेकिन मैं यह कह सकता हूं कि हमारी तरफ से यह कोशिश रही है कि किसी किस्म का भी कोई अपराधी हो वह पकड़ा जाए। इस जिले में 141 अपराधी थे जिन में से 123 को गिरफ्तार किया गया । इसी तरह से डकैती में 76 में से 71 अपराधियों को पकड़ा गया । पांच बाकी हैं । इस तरह से डकैती के पांच केस हैं । इनमें से अभी कोई आदमी पकड़ा नहीं गया । जहां तक माल बरामदगी का संबंध है, सारे मुल्क में इसकी परसैंटेज 26 है लेकिन हरियाणा में 74 परसैंट से ज्यादा रिकवरी हुई है ।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा मुख्य मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि इन्होंने कहा कि इतनी रिकवरी की गई है । हौडल में एक केस हुआ है, जिसकी एफ0 आई0 आर0 नं0 192 दिनांक 2–8–94 है । इसमें हौडल में छोटे लाल खाती के घर में डकैती पड़ी और दो हत्याएं हुई । मैं जानना चाहता हूं कि इस केस में जो मुलजिम पकड़े गए हैं, क्या वे सच्चे हैं ? मुख्य मन्त्री जी अपने तौर पर जानकारी ले कर बताएं कि जो दो आदमी पकड़े गए हैं, वे झूठे पकड़े गए हैं या सच्चे ? इस बारे में पिछली बार भी मैंने सवाल उठाया था तो इन्होंने कहा था कि इसका जवाब मैं बाद में दे दूंगा । उस समय इस बात को ले कर बड़ा हंगामा हुआ था । क्या मुख्य मंत्री जी जानते हैं कि एफ0 आई0 आर0 नं0 418 दिनांक 13–9–94 के जो मुलजिम हैं, वे अभी तक पकड़े नहीं गए हैं । क्या मुख्य मंत्री जी जानते हैं कि इनकी अपनी पार्टी के ही पलवल के जो श्री श्रीराम वर्मा अध्यक्ष हैं, उनके यहां एक दिन में तीन हत्याएं हुई थीं ? आज 6 महीने हो गए । उस केस में आज तक असली मुलजिम नहीं पकड़े गए हैं । इसी तरीके से न्यू कालोनी पलवल में एक हैपी नाम के लड़के की हत्या हुई । उसका एफ0 आई0 आर0 नं0 305 दिनांक 20–6–94 है और तभी का केस दर्ज है । आपके डी0 एस0 पी0 बिश्नोई ने उस केस की दफा 302 को बदल कर 304ए कर दिया है। उस लड़के के बारे में आज तक यह पता नहीं लगा कि आया उसने आत्म हत्या की या उसको किसी ने कत्ल किया । इसी तरह से एक जसबीर सिंह आर0 एस0 जे0 पी0 का अध्यक्ष था, उसकी हत्या हुई ।

श्री अध्यक्ष : दलाल साहब, आप क्वैशचन पूछें ।

श्री कर्ण सिंह दलाल : स्पीकर साहब, हमारे फरीदाबाद जिले में एस0 पी0 और डी0 एस0 पी0 की मिली भगत से जुर्म हो रहे हैं । वे पिछले चार साल से मेरे पीछे पड़े हुए हैं । मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या आम आदमी की सुरक्षा के लिए कोई प्रबन्ध किया जाएगा और क्या यह आश्वासन देंगे कि जो वहां पर डकैतियां, चोरियां और हत्याएं कर रहे हैं, उनके खिलाफ कोई कार्यवाही होगी ?

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, जब किसी मुलजिम को पकड़ लेते हैं, तो कह देते हैं कि वह असली मुलजिम नहीं है । अभी माननीय सदस्य ने कहा है कि वह असली मुलजिम नहीं है । पुलिस जिस किसी केस में किसी आदमी को पकड़ती है, तो पहले उसके बारे में पूरी जांच करती है और पूरी तफतीश करती है और उसके बारे में बात सच्ची होती है, तो उसको पकड़ती है । या फिर आप बता दें कि उस केस में सच्चा मुलजिम कौन है । उसको जांच करके पकड़ लिया जाएगा । आप उसका नाम लिख कर भेज दें ।

श्री कर्ण सिंह दलाल : स्पीकर साहब, जो असली मुलजिम है, मैंने उसका नाम ग्रिवेंसिज कमेटी के सामने बताया था और उस समय गुप्ता जी वहां मौजूद थे । आप इनसे पूछ लें ।

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, एक बात इन्होंने यह कही कि डी0 एस0 पी0 ने दफा 302 के केस को बदल कर 304 ए में कर दिया । केस वही बदला जाता है, जिसमें एक्सीडेंट से मौत हो जाए । हो सकता है जांच में उस केस में उसकी एक्सीडेंट से मौत का होना पाया गया हो । इसलिए उस केस को बदल कर 304 ए कर दिया गया हो । यदि आपको उसके बारे में कोई सन्देह है, तो आप हमें लिख कर भिजवा दें । हम उस केस की बाकायदा दोबारा जांच करवाएंगे ।

श्री राजेन्द्र सिंह बिसला : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो सवाल पूछा था, उसकी सारी इन्फर्मेशन सदन के पटल पर रख दी गई है । लेकिन यह बड़े खेद की बात है कि किसी अधिकारी बिरादरी के बारे में बात यहां पर करना बहुत अशोभनीय बात है । हमारे जिले में हमारे मुख्य मंत्री जी ने बहुत बढ़िया अधिकारी तैनात किए हुए हैं । इन्होंने बिश्नोई की बात कर दी । मैं कहता हूं कि वहां पर हर बिरादरी के अधिकारी तैनात हैं । वहां पर महेन्द्र सिंह मलिक डी0 एस0 पी0 लगे हुए हैं । मैं कहता हूं कि यहां पर जाट, ब्राह्मण, हरिजन और बैकवर्ड यानि सभी बिरादरी के अधिकारी तैनात हैं । इनको इस तरह की अशोभनीय बात नहीं करनी चाहिए थी । ये किसी अधिकारी की ईमानदारी और बेईमानी के बारे में पूछ सकते हैं लेकिन किसी आफिसर की बिरादरी का नहीं पूछना चाहिए ।

श्री अध्यक्ष : बिसला जी, आप क्वैश्चन पूछें।

श्री राजेन्द्र सिंह बिसला : अध्यक्ष महोदय, मैं जो सप्लीमैन्टरी पूछने जा रहा हूं, उसको आप एप्रिशिएट करेंगे। अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मुख्य मंत्री महोदय ने बताया है कि जब दिल्ली, यू0 पी0 और राजस्थान की फोर्स का दबाव उन पर पड़ता है तो कुछ लोग फरीदाबाद के पास इन राज्यों का बोर्डर होने की वजह से यहां पर आते हैं। (विघ्न) फरीदाबाद जिले में श्री के0 के0 मिश्रा जी के नेतृत्व में बहुत अच्छी पुलिस की टीम है। वे रात के दो-दो बजे तक सड़कों पर घूमते मिलेंगे। अध्यक्ष महोदय मैंने पहले भी निवेदन किया था और अब भी मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि फरीदाबाद जिले में क्यों न दिल्ली पुलिस सिस्टम वाला पैट्रन लागू कर दिया जाये जिसके तहत दफा 107 आदि धाराओं से संबंधित एस0 पी0 को सजा देने की पावर है। इसलिए मैं चाहता हूं कि यहां पर वहीं सिस्टम लागू कर दिया जाये।

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, पहले की अपेक्षा हमने पुलिस स्ट्रैंथ बढ़ाई है और वहां पर जो 2-3 पुलिस चौकियां हैं, उनको भी थाने में बदला जायेगा। गश्त भी पहले की अपेक्षा बढ़ा दी गई है। गाड़ियां भी वहां पर अधिक दी गई हैं। हमारी तरफ से पूरी कोशिश होगी कि वहां पर वारदात में कोई वृद्धि न हो। उसके लिए बाकायदा कदम उठाये जा रहे हैं और बराबर चौकसी बरती जा रही है।

Replacement of Defective Transformers

*1089. **Ch. Zile Singh Jakhar** : Will the Minister for Power be pleased to state the total number of Transformers replaced by new one during the period from March, 1994 to-date in Kosli-Sub Division and the amount spent therefor ?

बिजली मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह) : पहली मार्च, 1994 से 28 फरवरी, 1995 तक 68 क्षतिग्रस्त ट्रांसफार्मर नये ट्रांसफार्मरों से बदले गए हैं, जिन पर 16,55,750 रुपये खर्च आया है।

चौधरी जिले सिंह जाखड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा कि जो 68 ट्रांसफार्मर्ज बदले गए हैं, ये आया नए बदले गए हैं या रिपेयर करके बदले गए हैं ? इन्होंने जो 16,55,750 लाख रुपये खर्च के दिखाए हैं, इसमें नये ट्रांसफार्मर्ज का कितना पैसा है और रिपेयर वाले ट्रांसफार्मर्ज का कितना पैसा है ?

श्री वीरेन्द्र सिंह : 16,55,750 रुपया सिर्फ नये ट्रांसफार्मर्ज का ही है और ये 68 के 68 नए ट्रांसफार्मर्ज हैं। रिपेयर वाले इससे अलग 119 हैं।

चौधरी जिले सिंह जाखड़ : जो रिपेयर वाले ट्रांसफार्मर्ज हैं उन पर रिपेयर का कितना खर्चा है।

श्री बीरेन्द्र सिंह : इन पर 5 लाख 91 हजार रुपया रिपेयर का खर्च आया है।

चौधरी जिले सिंह जाखड़ : क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि इन ट्रांसफार्मर्ज पर ट्रांसपोर्टेशन का कितना खर्चा आया है। (विघ्न) ट्रांसपोर्टेशन का मेरा मतलब यह है कि जहां से ये उठाये गए और जहां पर ये लगाए गए वहां तक ले जाने पर कितना खर्च आया है ?

श्री बीरेन्द्र सिंह : ऐसा है स्पीकर सर, अगर मैं यह कहूं कि रिप्लेसमैंट के लिये टोटल ट्रांसफार्मर्ज बोर्ड द्वारा साईट पर ले जाये जाते हैं या पहुंचाए जाते हैं तो यह गलत बात होगी, इसलिए मैं यह नहीं कहूंगा। स्पीकर सर, कई दफा अरजैंसी इतनी ज्यादा होती है और बोर्ड के पास अपने व्हीकल्ज इतने नहीं होते कि सभी जगह वे ट्रांसफार्मर्ज ले जा सकें (विघ्न)

चौधरी जिले सिंह जाखड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि सारे के सारे ट्रांसफार्मर्ज किसान अपने ट्रैक्टरों पर या अपनी दूसरी गाड़ियों पर या किराये की गाड़ियों में ले कर जाते हैं। बोर्ड के द्वारा एक भी ट्रांसफार्मर नहीं ले जाया जाता। इसका क्या कारण है ? (विघ्न)

श्री बीरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, इनका यह कहने का तरीका ठीक नहीं है। ये अपनी बात का खुद ही जवाब दे रहे हैं। कम से कम मुझे जवाब देने दें। उसके बाद अगर कुछ पूछना है तो जरूर पूछें परन्तु मेरा जवाब अभी पूरा नहीं हुआ और ये बीच में खड़े हो गये हैं। इनकी पूरी तसल्ली मैं करवाऊंगा। अध्यक्ष महोदय, कई दफा ऐसी अरजैंसी होती है कि किसान खुद व्हीकल ले कर आते हैं और मर्जी से ट्रांसफार्मर्ज ले जाते हैं क्योंकि बोर्ड के पास इतने व्हीकल्ज उपलब्ध नहीं है कि वह हर जगह एकदम अपना व्हीकल दे सके ऐसी स्थिति में किसान खुद आकर करते हैं। नार्मली बोर्ड खुद ट्रांसफार्मर को लिफ्ट करके साईट पर भेजता है और किसान से कोई पैसा वसूल नहीं करता।

श्री धर्म पाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि विभिन्न वर्कशाप्स में कितने ट्रांसफार्मर्ज जले हुए पड़े हैं और उनकी तादाद कितनी है ?

श्री बीरेन्द्र सिंह : स्पीकर सर, इस समय जो ट्रांसफार्मर्ज वेरियस वर्कशाप में पड़े हुए हैं, उनकी कुल तादाद 21,459 है।

श्री अध्यक्ष : बिजली बोर्ड के पास कुल कितने ट्रांसफार्मर्ज हैं और जो अण्डर रिपेयर है, उनकी परसैंटेज कितनी है ?

श्री वीरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, यदि आपकी इजाजत हो तो आप मुझे दो मिनट का समय दे दीजिए मैं सदन की तसल्ली के लिये पूरी डिटेल सदन में बता देता हूं कि टोटल ट्रांसफार्मर्ज कितने हैं, कितने इन्स्टाल्ड हैं, कितने वर्कशाप में हैं, कितने प्राईवेट फर्मज के पास हैं। स्पीकर सर, हरियाणा बिजली बोर्ड के पास कुल 1,18,929 ट्रांसफार्मज हैं जिनमें से 88,545 इन्स्टाल्ड हैं, 21,459 वर्कशाप में हैं। अगर कोई ट्रांसफार्मर्ज खराब या डैमेज हो जाए तो उसको रिपलेस करने के लिये हमारे पास स्टोर में 1700 ट्रांसफार्मर्ज हैं। जिन ट्रांसफार्मर्ज की रिपेयर का प्राईवेट फर्मज को आर्डर किया हुआ है, उनकी संख्या 13,700 है और जो रिपेयर हो कर हमारे पास आ चुके हैं, उनकी संख्या 5,662 है।

प्रो० राम बिलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि ट्रांसफार्मर्ज रिपलेस करने के लिये क्या बोर्ड की कोई हिदायतें हैं या कोई नीति है कि ट्रांसफार्मर बदलने में मिनिमम 4 दिन, 8 दिन या 15 दिन से ज्यादा नहीं लगने चाहियें ? अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री जी से यह जानकारी चाहूंगा कि नार्मली ट्रांसफार्मर कितने दिनों में रिपलेस कर दिया जाता है, क्या इस बारे में कोई बोर्ड की नीति है ?

श्री वीरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, ट्रांसफार्मर तो तभी बदला जाता है, जब उसके डैमेज होने की इत्तलाह महकमे को मिले। जहां इत्तलाह होती है, वहीं ट्रांसफार्मर को बदल देते हैं। स्पीकर सर, आमतौर पर विद इन ए वीक ट्रांसफार्मर बदल दिया जाता है।

श्रीमती चन्द्रावती : अध्यक्ष महोदय, मेरे पास रिकार्ड है कि 25-25 दिन तक ट्रांसफार्मर्ज बदले नहीं जाते हैं। वे ट्रांसफार्मर्ज भी तब बदले जाते हैं जब हम इस बारे में कहते हैं या शिकायत करते हैं, जब कि उनको इन ट्रांसफार्मर्ज को सुओ-मोटो ही बदलना चाहिये। न तो इनका कोई असिस्टैंट लाईनमैन होता है और न ही कोई लाईनमैन मिलता है जब कि वहां दो असिस्टैंट लाईनमैन और एक लाईनमेन होने चाहियें। होना यह चाहिये कि ट्रांसफार्मर खराब होने पर सुओ-मोटो बदल दिया जाना चाहिये। जब बदलने की कम्पलेंट ले कर जाते हैं तो कहते हैं कि ट्रांसफार्मर बी०ई०एल० के पास पड़ा हुआ है। कल बदलेंगे, परसों बदलेंगे और इस तरह महीना निकल जाता है। किसी ने मुझे बताया कि ट्रांसफार्मर जे०ई० बदलेगा। स्पीकर सर, मेरा कहना सिर्फ यह है कि ट्रांसफार्मर चाहे कोई भी बदले सुओ-मोटो 10-15 दिनों में जरुर बदल दिया जाना चाहिये। जहां तक मैं समझती हूं इसमें महकमे की भी जो कुछ गलती है, वह नहीं होनी चाहिये। इनके अपने लाईनमैन हैं। उनकी इत्तलाह पर ट्रांसफार्मर सुओ-मोटो ही बदल दिये जाने चाहियें।

श्री वीरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, जब सुओ-मोटो ट्रांसफार्मर खराब ही नहीं हुआ है, तो उसको कैसे बदलेंगे।

श्रीमती चन्द्रावती : आपके लाईनमैन क्या करते हैं ? इस बारे में उनको तो पता होना चाहिये।

श्री वीरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, इत्तलाह देना तो पार्टी का काम है और बहन जी सुओ-मोटो तो अलग बात है। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, इन्होंने जो कहा है कि 25 दिन भी लग जाते हैं तो बहन जी कोई स्पैसिफिक केस बताएं। वे मुझे भी बता सकती हैं, मुख्यमंत्री जी को, चीफ इन्जीनियर को भी बता सकती हैं। मेरे नोटिस में ऐसी कोई बात नहीं है।

प्रो0 सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने अभी सात दिन वाली बात कही है। तो क्या इनके पास इस बात का रिकार्ड है कि ट्रांसफार्मर किस तारीख को खराब हुआ और किस तारीख को बदला गया है। क्या आप उस अफसर के खिलाफ कार्यवाही करेंगे जिसने सात दिन में वह ट्रांसफार्मर नहीं लगाया है।

श्री वीरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, यदि यह पाया गया कि वह ट्रांसफार्मर सात दिन में बदला जा सकता था और नहीं बदला गया, तब हम अवश्य कार्यवाही कर सकते हैं।

Rape Committed on a Female Patient

***1099. Shri Dhir Pal Singh :** Will the Chief Minister be pleased to state whether any incident of rape with a female patient by a Doctor in the Medical College, Rohtak during the month of June, 1994 has come in the notice of the Government ; if so, the action taken in this regard ?

मुख्य मन्त्री (चौधरी भजन लाल) : वैसे, अध्यक्ष महोदय, धीर पाल जी बहुत ही लायक मैम्बर हैं। इन्होंने तो जून का पूछा था और मैंने जवाब देना था 'नहीं'। लेकिन मैं इसमें सुधार लाता हूं। यह वाक्या जून का नहीं था, बल्कि 18 जुलाई का था। इसमें एक डाक्टर शामिल था और उसके खिलाफ केस दर्ज हो गया है। यह केस 21-7-94 को दर्ज हुआ है।

श्री धीर पाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, मुख्य मन्त्री जी ने यह स्वीकार किया है कि 18 जुलाई को यह हादसा हुआ है। मैं इनसे यह आश्वासन चाहता हूं कि भविष्य में मैडिकल कालेज जैसी संस्थाओं में इस तरह के हादसे न हों, जिससे लोगों का मनोबल न गिरे, इस बारे में इन्होंने कौन-कौन से कदम उठाए हैं ?

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, उस केस में फौरन ही कार्यवाही करके डाक्टर को गिरफ्तार किया गया है। उसको सस्पैंड किया गया है और अब यह केस कोर्ट में है।

श्री धीर पाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इस बारे में सरकार कोई ऐसा कदम उठा रही है, जिससे भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों।

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, अगर कोई भी गलत काम करता है तो सरकार उस बारे में कार्यवाही करती है। सरकार की तरफ से कोई डिले भी नहीं होती है। डाक्टर का बहुत ही सम्मानित ओहदा है। अगर वह ही ऐसा करने लग जाए तो बाकी क्या करेंगे। हम इस बारे में सख्त से सख्त कार्यवाही करेंगे।

Upgradation of Government Girls Middle School, Madlauda.

***1136. Shri Krishan Lal :** Will the Minister for Education be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to upgrade the Government Middle School for girls, Madlauda District Panipat; if so, the time by which it is likely to be upgraded ?

Education Minister (Shri Phool Chand Mullana) : Yes, there is a proposal under consideration to upgrade the school as and when the funds are available.

श्री कृष्ण लाल : अध्यक्ष महोदय, क्या मन्त्री जी के नालेज में यह बात है कि 14 जनवरी, 1993 को हमारे वित्त मंत्री साहब मेरे गांव में जाकर इस स्कूल को अपग्रेड करने की घोषणा करके आए थे और इसी तरह से पांच फरवरी, 1995 को मुख्य मंत्री जी भी इस स्कूल को अपग्रेड करने की घोषणा करके आए थे ? ये वहां के लोगों को आश्वासन देकर आए थे कि अप्रैल में क्लासिज शुरू हो जाएंगी। अध्यक्ष महोदय, अगर इनकी यह बात सच है तो कब तक उस स्कूल को अपग्रेड करके वहां क्लासिज शुरू कर दी जाएंगी ?

श्री फूल चन्द मुलाना : स्पीकर सर, कृष्ण लाल जी ने ठीक ही कहा है कि मुख्य मंत्री जी वहां गए थे। इनकी यह बात अंडर कंसीड्रेशन है कि इस स्कूल को अपग्रेड कर दिया जाएगा। लेकिन मडलौडा में पहले से ही एक हाई स्कूल है जिसमें लड़कों के साथ-साथ लड़कियां भी पढ़ती हैं। इस बार जब भी स्कूलों को अपग्रेड किया जाएगा, तभी इस स्कूल को भी अपग्रेड कर दिया जाएगा।

श्री कृष्ण लाल : स्पीकर सर, मडलौडा ब्लाक हैड क्वार्टर है। वहां के सरकारी हाई स्कूल में लड़कियां नहीं पढ़तीं। मिडिल स्कूल तो अलग है। लोगों ने उस स्कूल की बिल्डिंग भी बना रखी है। मंत्री जी हमें बता दें कि उस स्कूल को अपग्रेड करके वहां कब तक क्लासिज शुरू करा दी जाएंगी ?

श्री फूल चन्द मुलाना : स्पीकर सर, जब कभी भी अगली बार स्कूलों को अपग्रेड किया जाएगा, तभी इस स्कूल को अपग्रेड करके लड़कियों की नवीं क्लास शुरू कर दी जाएगी।

साथी लहरी सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आदरणीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि स्कूलों को अपग्रेड करने का काईटेरिया क्या है ? क्या ब्लाक स्तर पर एक प्लस टू स्कूल होना चाहिये या हैड क्वार्टर स्तर पर यह स्कूल होना चाहिये ? मंत्री जी बताएं कि एक ब्लाक में कम से कम कितने स्कूल होंगे ?

श्री फूल चन्द मुलाना : स्पीकर सर, स्कूल अपग्रेड करने का काईटेरिया यह है कि प्राईमरी से मिडिल तक अपग्रेड करने के लिये उस स्कूल में बिल्डिंग में कम से कम आठ कमरे, एक आफिस रूम, एक साइंस क्लास रूम, एक स्टोर रूम तथा जमीन कम से कम तीन एकड़ हों और उस स्कूल में पांचवीं क्लास तक 150 स्टुडैंट्स होने चाहिएं। इसके अलावा उस स्कूल के नजदीक तीन किलोमीटर की परिधि में और कोई दूसरा स्कूल नहीं होना चाहिये तथा उस गांव की आबादी 500 या इससे ज्यादा होनी चाहिए। इसी प्रकार से आठवीं क्लास से दसवीं क्लास तक स्कूल अपग्रेड करने के लिये दस क्लास रूम, एक आफिस रूम, एक स्टोर रूम, दो साइंस रूम, एक स्टाफ रूम और जमीन कम से कम पांच एकड़ तथा उस स्कूल में 250 स्टुडैंट्स होने चाहियें। इसके अलावा उस स्कूल के नजदीक पांच किलोमीटर की परिधि में और कोई स्कूल नहीं होना चाहिये जो कि हाई स्कूल हो तथा उस गांव की पौपुलेशन कम से कम एक हजार होनी चाहिये। इसी तरह दस जमा दो स्कूल के लिये 14 क्लास रूम, एक आफिस रूम, दो स्टोर रूम, तीन लैबोरेटरी रूम्ज, एक हाल, बाउंड्रीवाल, स्टाफ रूम और कम से कम 6 एकड़ जमीन होनी चाहियें और आठ किलोमीटर की परिधि तक कोई दूसरा प्लस टू स्कूल नहीं होना चाहिए तथा वहां की आबादी पांच हजार होनी चाहियें। इसके अलावा भी माननीय मुख्य मंत्री जी इस समस्या से भली भांति अवगत हैं कि लड़कियों की शिक्षा का प्रांत में प्रसार बहुत आवश्यक है इसलिये जहां-कहीं भी वे लड़कियों की शिक्षा के लिये स्कूल को अपग्रेड करना आवश्यक समझते हैं, वहां स्कूल को अपग्रेड कर दिया जाता है।

तारांकित प्रश्न संख्या 1115

यह प्रश्न पूछा नहीं गया क्योंकि इस समय माननीय सदस्य श्री अमर सिंह ढांडे सदन में उपस्थित नहीं थे।

Schools in Mewat Area

*1144. **Shri Azmat Khan :** Will the Minister for Education be pleased to state—

(a) the number of Primary, Middle, High and 10+2 Schools in Mewat area in which Urdu is taught ; and

(b) the number of Schools out of those as referred to in part (a) above are without Urdu teachers.

Education Minister (Shri Phool Chand Mullana) :

(a) Number of schools where Urdu is taught in Mewat area is as under :—

(i) Primary Schools (includes primary schools, attached with middle/ High Schools)	55
(ii) Middle Schools	12
(iii) High Schools	23
(iv) Senior Secondary Schools	4
	94

(b) Number of Schools out of (a) above where Urdu teachers are not available.

(i) Primary Schools	6
(ii) Middle Schools	6
(iii) High Schools	6
(iv) Senior Secondary Schools	1
	19

श्री अजमत खां : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जिन जगहों पर स्कूलों में उर्दू टीचर्ज की डिमांड होगी, क्या उनमें उर्दू के लिये पोस्टें मंजूर करेंगे और जहां पोस्टें मंजूर हैं, वहां आज भी जगहें खाली हैं, उन पर कब तक उर्दू टीचर लगा दिए जाएंगे ?

15.00 बजे

श्री फूल चन्द मुलाना : स्पीकर सर, मेवात एरिया में लगभग 94 स्कूल हैं, जहां उर्दू पढ़ाई जाती है और जहां कहीं भी बच्चे उर्दू पढ़ने वाले हैं, न केवल मिडल हाई स्कूल बल्कि सीनियर सैकण्डरी स्कूलों में भी लैक्चरर्ज का प्रावधान किया हुआ है। मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिये बताना चाहूंगा कि इन के गांव मलाई में सीनियर सैकण्डरी स्कूल है, वहां हमने उर्दू की पोस्ट मंजूर की हुई है और लैक्चरर के आदेश कर दिए हैं उसने ज्वाईन नहीं किया। ज्यों ही लैक्चरर अवेलेबल होगा, लैक्चरर लगा देंगे। मास्टर जी खुद भी शिक्षा जगत से हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि फिरोजपुर में 125 बच्चों को उर्दू टीचर्ज की ट्रेनिंग देते हैं। लेकिन इस बार केवल 79 सिलैक्ट ही पाए हैं जिनमें

से 77 ने ज्वायन कर लिया है। एक किसी केस के सिलसिले में जेल में है और एक किसी और वजह से ज्वायन नहीं कर पाया। माननीय सदस्य उर्दू ट्रैनिंग के लिये बच्चों की संख्या में वृद्धि कराएं ताकि उर्दू के अध्यापकों की कमी को हम जल्दी से जल्दी पूरा कर सकें।

Case of Kidnapping/Bribery

*1176. **Ch. Om Parkash Beri :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether any case of Kidnapping/bribery against the official of Delhi Police has been registered in Loharu Police Station during the year 1994 ; and

(b) if so, the action taken thereon ?

मुख्य मन्त्री (चौधरी भजन लाल) :

(क) जी हां।

(ख) एक मुकद्दमा नं० 278 दिनांक 23-11-94 धाराधीन 365/34 भा:द:स: और 7/13/49/88 पी०सी० एक्ट थाना लोहारू में दर्ज किया गया है। तीन अपहृत व्यक्तियों को दिल्ली से वापिस लाया जा चुका है। रिश्वत की राशि पूर्णतया बरामद कर ली गई है। इस मुकद्दमा में दिल्ली पुलिस के एक उप निरीक्षक, एक मुख्य सिपाही तथा एक सिपाही सहित 5 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। धारा 365/34 भा:द:स: तथा 7/13/49/88 पी०सी० एक्ट के अन्तर्गत चालान तैयार किया गया है।

Mr. Speaker : Now the question hour is over.

नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गये तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

Construction of Roads

*1148. **Shri Satbir Singh Kadian :** Will the Minister for P.W.D. (B&R) be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct a road from village Pardhana to Shahpur village in District Panipat ; if so, the time by which it is likely to be constructed ?

लोक निर्माण मन्त्री (चौधरी अमर सिंह) : परढाना से जवाहरा तक सड़क निर्माण करके, इसको शाहपुर से जोड़ने का प्रस्ताव सरकार के पास है धन की उपलब्धी अनुसार यह सड़क शीघ्र ही बना दी जाएगी।

Completion of Roads

*1183. **Sathi Lehri Singh :** Will the Minister for Agriculture be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to construct the following incomplete roads:—

(i) From Village Mehra to Kharkali ;

(ii) From Village Khurdban to Dhanora ;

(iii) From Kanjnu to Alahar ;

(iv) From Ram Nagar to Patak Majra ; and

(v) From Kalwa to Sunarian.

(b) if so, the time by which the above said roads are likely to be constructed ?

Agriculture Minister (Sh. Harpal Singh) :

(a) &(b)

(i), (ii) & (iv) : The roads from Village Mehra to Kharkali, Khurdban to Dhanora and Ram Nagar to Patak Majra require special repairs and will be undertaken by the Haryana State Agricultural Marketing Board during the year 1995-96.

(iii) The road from Village Kanjnu to Alahar has been completed except a portion of 200′ length about which there are stay orders of the Court. This road will be got completed after the stay is vacated by the Court.

(v) The road from Kalwa to Sunarian has been completed except 500′ length. There was stay order about this which has been vacated and the road is likely to be completed by June, 1995.

अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर

Reservation in Sports Department

1248. **Sathi Lehri Singh :** Will the Minister of State for Sports be pleased to state—

(a) the postwise number of officers/officials working in the Sports Department at present ;

(b) the number of persons out of those as referred to in part (a) above belonging to Scheduled Castes ; and

(c) whether there is any short fall in the reservation of Scheduled Castes in the afore-said posts ; if so, the time by which it is likely to be wiped off ?

खेल राज्य मंत्री (श्री राजेश कुमार शर्मा) :

(क) तथा (ख) आदरणीय सदस्य द्वारा उपरोक्त (क) तथा (ख) के बारे में मांगी गई सूचना अनुलग्नक "क" पर प्रस्तुत है।

(ग) जी हां, महोदय, अनुसूचित जातियों से रखे जाने वाले प्रशिक्षकों तथा कनिष्ठ प्रशिक्षकों के संबंध में रिक्तियां हैं तथा विभाग इन रिक्तियों को भरने के लिये प्रयत्नशील है।

अनुलग्नक "क"

खेल एवं युवा कल्याण विभाग हरियाणा में इस समय कार्य कर रहे अधिकारियों/कर्मचारियों का विवरण व उसमें से कार्यरत अनुसूचित जाति से संबंध रखने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों का विवरण निम्न प्रकार है :—

क्र0	पद का नाम	विभाग में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों का पदवार ब्यौरा	अनुसूचित जाति से सम्बन्ध रखने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों का हिस्सा	अनुसूचित जाति से सम्बन्ध रखने वाले कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी	कमी
1	2	3	4	5	6
1.	निदेशक	1	—	—	—
2.	संयुक्त निदेशक/उपनिदेशक (प्रशासन)	1	—	—	—
3.	उपनिदेशक (खेलें)	4	—	—	—
4.	उपनिदेशक (खेलें)	4	—	—	—
5.	प्रौक्टर	1	—	—	—
6.	उपनिदेशक (योगा)	1	—	—	—

[श्री राजेश कुमार शर्मा]

1	2	3	4	5	6
7.	उपनिदेशक (युवा)	1	—	—	—
8.	सहायक निदेशक (योगा)	1	—	—	—
9.	जिला खेल एवं युवा कल्याण अधिकारी	17	—	—	—
10.	प्रशिक्षक (खेलें)	170	34	11	23
11.	कनिष्ठ प्रशिक्षक (खेलें)	127	25	2	23
12.	प्रशिक्षक (योगा)	13	2	1	1
13.	कनिष्ठ प्रशिक्षक (योगा)	10	2	2	—
14.	वरिष्ठ कला अध्यापक	22	4	4	—
15.	कनिष्ठ कला अध्यापक	16	3	3	—
16.	स्थापना अधिकारी	1	—	—	—
17.	बजट एवं योजना अधिकारी	1	—	—	—
18.	सहायक जिला न्यायवादी	1	—	—	—
19.	अनुभाग अधिकारी (लेखा)	1	—	—	—
20.	अधीक्षक	3	—	—	—
21.	उपाधीक्षक/मुख्यलिपिक (3+16)	19	4	4	—
22.	पी0ए0	1	—	—	—
23.	वरिष्ठ आशुलिपिक	2	—	—	—
24.	कनिष्ठ आशुलिपिक	2	—	—	—
25.	आशु टंकक	21	4	4	—
26.	लाईब्रेरियन	1	—	—	—

1	2	3	4	5	6
27.	सहायक	39	8	8	—
28.	स्टोरकीपर	17	3	3	—
29.	लिपिक	43	9	9	—
30.	चालक	3	—	—	—
31.	गैसटेटनर आपरेटर	1	—	—	—
32.	दफतरी	1	—	—	—
33.	रैस्टोरर	1	—	—	—
34.	कैमरामैन कम मूवी प्रोजैक्टर आपरेटर	—	—	—	—
35.	सहायक कैमरामैन कम मूवी प्रोजैक्टर आपरेटर	1	—	—	—
36.	इलैक्ट्रिशियन	—	—	—	—
37.	जमादार	1	—	—	—
38.	सेवादार	56	11	11	—
39.	ग्राऊंडमैन	30	6	6	—
40.	चौकीदार	17	3	3	—
41.	स्वीपर	2	2	2	—
42.	माली	7	1	1	—
43.	रसोईया	2	—	—	—
44.	रसोईया सहायक	2	—	—	—

Opening of 10+2 System School in Babain

249. **Sathi Lehri Singh :** Will the Minister for Education be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to open 10+2 system School in Babain district Kurukshetra during the year 1995-96 ?

शिक्षा मन्त्री (श्री फूल चन्द मुलाना) : जी हां, अन्य विद्यालयों के साथ इसे भी मैरिट के आधार पर विचार लिया जायेगा बशर्ते कि राजकीय विद्यालयों को स्तरोन्नत करने हेतु राशि उपलब्ध हुई ।

Government Schools in District Kurukshetra and Yamunanagar

250. **Sathi Lehri Singh :** Will the Minister for Education be pleased to state—

(a) the names of Government, Primary, Middle and 10+2 Schools in district Yamunanagar and Kurukshetra, separately as at present ; and

(b) whether the number of teachers working in the Schools referred to in part (a) above are in accordance with the strength of students therein ; if so, the details thereof ?

Mr. Speaker : Extension has been sought for giving reply to this question which has been granted. The communication received from the Minister is as under :—

Interim Reply

श्री फूल चन्द मुलाना

शिक्षा मन्त्री,
हरियाणा, चण्डीगढ़ ।
दिनांक 16-3-1995

विषय :—अतारांकित विधान सभा प्रश्न नं0 250 जो दिनांक 20-3-95 को उत्तर देने के लिए लगा है ।

आदरणीय चौधरी जी,

उपरोक्त वर्णित अतारांकित प्रश्न नं0 250 का सम्बन्ध जिला यमुनानगर एवं कुरुक्षेत्र में स्थित राजकीय प्राथमिक, माध्यमिक तथा वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों व उनमें छात्र संख्या अनुसार अध्यापकों की नियुक्ति किये जाने बारे विस्तृत सूचना से है । यह सूचना सरकार के स्तर पर उपलब्ध नहीं है और इसे एकत्रित करने में काफी समय लगेगा । सरकार को यह सूचना सम्बन्धित जिलों से प्राप्त करने में लगभग एक मास का समय लग जाएगा । इन परिस्थितियों में इस प्रश्न का उत्तर दिनांक 20-3-95 को

दिया जाना सम्भव नहीं है। अतः मेरा आपसे अनुरोध है कि इस प्रश्न का उत्तर देने के लिये सरकार को 30 दिन का समय देने की कृपा करें।

सधन्यवाद।

भवदीय,

ह0/-
(फूल चन्द मुलाना)

श्री ईश्वर सिंह,
अध्यक्ष
हरियाणा विधान सभा,
चण्डीगढ़।"

Repair of Link Roads

251. Sathi Lehri Singh : Will the Minister for P.W.D.(B&R) be pleased to state—

(a) the total number of link roads in the Radaur Circle of Yamunanagar District ; and

(b) whether the roads as referred to in part (a) above are in damaged condition ; if so, the time by which these roads are likely to be repaired/constructed ?

लोक निर्माण मंत्री (चौधरी अमर सिंह) :

(क) तथा (ख) जिला यमुनानगर के रादौर सर्कल (निर्वाचन क्षेत्र) में 68 नं0 सड़कें हैं इनमें से 9 नं0 सड़कें क्षतिग्रस्त हालत में हैं, इनकी 30-4-95 तक मरम्मत कर दी जाएगी।

ध्यानाकर्षण प्रस्तावों/नियम 84 के अधीन प्रस्तावों की सूचनाएं

प्रो0 सम्पत सिंह : स्पीकर सर, हमने भी एक काल अटैंशन मोशन आज से 5-6 दिन पहले दी थी कि हरियाणा में फाईनैंशियल क्राईसिज की वजह से किसान को जो दो करोड़ रुपये का मुआवजा देना था, वह ये नहीं दे पाएंगे। इसी वजह से डी0सी0 की कोठी, रैस्ट हाउस और ऐक्सीयन के दफ्तरों की नीलामी हो रही है।

श्री अध्यक्ष : यह गवर्नमेंट को कमैंट्स के लिये भेजा हुआ है। आप बैठ जाइए।

श्री कृष्ण लाल : अध्यक्ष महोदय, 10 तारीख को हमने काल अटैंशन मोशन दिया था कि 29 दिसम्बर को कवाड़ी गांव के हरिजनों के खिलाफ (विघ्न)।

श्री अध्यक्ष : आप बैठ जाइए। यह मोशन डिस अलाऊ कर दिया गया है।

चौधरी ओम प्रकाश बेरी : स्पीकर साहब, जो किसानों को कम्पन्सेशन देने के बारे में था उस बारे तो आपने बता दिया है कि वह मोशन सरकार के पास कमैंट्स के लिये भेज दिया है। (शोर) स्पीकर सर, इसके इलावा और भी मोशन्ज हैं, 10 मार्च को जीन्द में, 11 को हिसार में और उससे पहले कुरुक्षेत्र में हरियाणा विकास पार्टी की महिला कार्यकर्त्रियों के ऊपर, जोकि शराब के ठेकों की नीलामी के विरोध में प्रदर्शन कर रही थीं, पुलिस ने लाठी चार्ज किया (शोर)।

श्री अध्यक्ष : बेरी साहब, आप बैठिये, वह मोशन डिस-अलाऊ कर दिया गया है।

प्रो0 छतर पाल सिंह के निलम्बन को रद्द करने सम्बन्धी मामला उठाना

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मैं इस शून्य काल के जरिये आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि भाई छतरपाल सिंह आपके चैम्बर में मौन व्रत रखे बैठे हैं और मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि माननीय मैम्बर को यहां सदन में अपने मन की बात कहने का मौका नहीं मिल रहा है। आखिर उसके साथ सरकार की या आपकी क्या लड़ाई है? क्यों नहीं उसे अपनी बात कहने का मौका दिया जाता? * * * * * * * * * * * *

श्री अध्यक्ष : कर्ण सिंह जी आप बैठिए (शोर)।

श्री कर्णसिंह दलाल : स्पीकर साहब, मैं यह कहना चाह रहा था कि * * * * * * * * * * *

श्री अध्यक्ष : जो कुछ कर्ण सिंह जी मेरी इजाजत के बिना कह रहे हैं, वह रिकार्ड न किया जाए। (शोर)

श्री राम रत्न : स्पीकर साहब, मैं भी कुछ कहना चाहता हूं (शोर)।

श्री अध्यक्ष : रामरत्न जी, आप बैठिए, आपको बोलने का समय मिलेगा। (शोर)

---

*चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

ध्यानाकर्षण प्रस्तावों/नियम 84 के अधीन प्रस्तावों की सूचनाएं (पुनरारम्भ)

चौधरी ओम प्रकाश बेरी : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक मोशन यमुना ऐग्रीमैन्ट के बारे में था और दूसरा एस०वाई०एल० प्रोजैक्ट के बारे में था। दोनों ही इशू ऐसे हैं जोकि हरियाणा की जनता के हितों से जुड़े हुए हैं। हरियाणा के लोग इससे बहुत चिंतित हैं। इस बारे में आप बताएं (व्यवधान व शोर)

Mr. Speaker : Your these motions are under rule 84 and these are under consideration.

प्रो० छतर पाल सिंह के निलम्बन को रद्द करने सम्बन्धी मामला उठाना (पुनरारम्भ)

चौधरी ओमप्रकाश बेरी : दूसरी बात अध्यक्ष महोदय, जो भाई कर्ण सिंह दलाल ने कह दी, वही मैंने भी कहनी थी कि आज आठ दस दिन बीत चुके हैं कि हमारे इस सदन के एक माननीय सदस्य प्रोफैसर छतर पाल सिंह जी हाउस से बाहर बैठे हैं। इस बारे में मेरी आप से, इस हाउस से व लीडर आफ दी हाउस से यह प्रार्थना है कि आप और वे अपने निर्णय पर पुनर्विचार करें और उन्हें इस हाउस में दोबारा बुलाएं ताकि वे अपनी व अपने हल्के के लोगों की बात यहां पर कह सकें। इस तरह की जिद्द मुख्य मन्त्री महोदय को नहीं करनी चाहिये न ही इसे अपना प्रैस्टिज इशू ही बनाना चाहिये। आखिर वह एक इलैक्टिड रिप्रजैंटेटिव हैं। उनको बुलाकर उन से बात अवश्य करनी चाहिये। मेरी यह हम्बल रिक्वैस्ट है।

श्री कर्ण सिंह दलाल एम०एल०ए० द्वारा श्री राम रतन एम०एल०ए० को धमकी देने तथा उनके विरुद्ध कार्यवाही करने सम्बन्धी मामला

श्री राम रत्न : अध्यक्ष महोदय, मैंने 15 मार्च, 1995 को आपको एक ऐप्लीकेशन दी थी कि मुझे कर्ण सिंह दलाल से जान का खतरा है (शोर) आपके एम०एल०ए० हौस्टल के अन्दर अगर एक विधायक के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार होगा तो बाहर के लोगों का क्या हाल होगा? आप उस हौस्टल के इंचार्ज हैं और आपकी रहनुमाई में अगर एक विधायक के साथ ऐसा व्यवहार होगा तो यह कोई अच्छी परम्परा नहीं होगी। आप मेरी शिकायत पर गौर करें और दोषी को इसके लिये सजा दें। ऐसे विधायक को जो दूसरे विधायकों के साथ इस तरह का व्यवहार करता है, उसको सुबह

[श्री राम रत्न]

से बाहर कर देना चाहिये। फिर यहां ये लोग हरिजनों के साथ सद्-व्यवहार की बात करते हैं। इनके ऐसे व्यवहार के कारण मेरे दिमाग को गहरी चोट लगी है और उसी दिन से, डर के मारे मैं अपने दिमाग का संतुलन खो बैठा हूं न ही उस दिन से मैं यहां पर कुछ बोल सका हूं। यह बहुत सीरियस मामला है। इसके साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा कि कर्ण सिंह दलाल ने अभी फरीदाबाद के एरिया के अन्दर जुल्म की बात कही और यह कहा कि वहां पर दो बिशनोई डी०एस०पी०ज० के कारण वारदातों में बढ़ौतरी हुई है। इनको इस तरह की बेतुकी और निराधार बातें यहां पर नहीं कहनी चाहिये। आपको इनके खिलाफ ऐक्शन लेना चाहिये ताकि ये इस तरह के इलजाम दूसरों पर न लगा सकें। मैं मुख्य मंत्री महोदय से यह प्रार्थना करूंगा कि वे यह बताएं कि इस समय दलाल के ऊपर कितने ऐसे केसिज चल रहे हैं (शोर)।

श्री अध्यक्ष : राम रत्न जी, आप बैठिए। इस तरह की दूसरी कोई बात न करें। राम रत्न जी ने अभी जो बात कही है उस बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि राम रत्न जी और दलाल साहब अलग से मुझ से मिल लें।

In the book 'Practice and Procedure of Parliament' by Kaul & Shakdhar, it is written :—

> "Complaints against members of the House regarding their conduct in private life which has no relation to their conduct as members of Parliament are neither treated as petitions nor placed as representations before the Committee on Petitions. Such complaints are dealt with by the Speaker personally after obtaining, where necessary, facts from the members concerned."

प्रो० छतर पाल सिंह के निलम्बन को रद्द करने सम्बन्धी मामला उठाना (पुनरारम्भ)

प्रो० सम्पत सिंह ; स्पीकर साहब, जैसे अभी हमारे माननीय सदस्य ने जिक्र किया। मुझे तो मालूम नहीं कि इस बारे में रूल्ज में क्या है? This is a very serious matter. जहां तक एक सदस्य के मौन धारण की बात है तो स्पीकर साहब, मुख्य मंत्री जी बैठे हैं और ट्रैजरी बैंचिज के सदस्य भी बैठे हैं। होली के बाद तो इस तरह की छोटी-मोटी बातें खत्म हो जाती हैं। अब हम सारे होली मना कर आए हैं। इसलिये इन्हें फिराख दिली से उस बात को खत्म करना चाहिये। प्रो० छतर पाल सिंह की सस्पैंशन रिवोक करने के लिये गवर्नमैंट की तरफ से प्रस्ताव आ जाए और जो बात हो गई, उसको भुला दिया जाए। हमने आराम से गुलाल खेला और अच्छी होली मनाई

है इसलिये अब नए सिरे से शुरुआत की जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा। आपने राम रत्न जी के केस में बहुत बढ़िया निर्णय दिया कि वे दोनों आपके कमरे में आ जाएं। अभी राम रत्न जी ने कहा कि वे अपना दिमाग खो बैठे हैं। जो दिमाग की डोर है, वह उनके पास नहीं है। इसलिये वह उनको वापिस दें ताकि वे अपने हल्के की बात कह सकें।

चौधरी बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, अभी सदन में लीडर आफ दि अपोजीशन ने, श्री ओम प्रकाश बेरी तथा दलाल साहब ने आपसे सबमिट किया कि प्रो0 छत्तर पाल सिंह को निकालने की बात पुरानी हो गई है। इस बारे में हम पहले भी आपसे प्रार्थना कर चुके हैं कि उसकी सस्पैंशन को रिवोक किया जाए। मैं समझता हूं कि कोई वजह नहीं है कि उसको सदन से बाहर इतने दिन रखा जाए। इसलिये उसको सदन में आने की इजाजत दी जाए। जो प्रस्ताव उस दिन पास हुआ था, उसको रिवोक किया जाए। इससे सदन की मर्यादा बढ़ेगी। आज वे आपके चैम्बर में मौन धारण करके बैठे हैं। मैं कहता हूं कि आप इस पर गहराई से विचार करें क्योंकि जिस रोज छत्तर पाल सिंह को निकाला गया था, उस रोज पहले रूल 104 के तहत आपको उसे नेम करना चाहिये था। आपने उसको नेम नहीं किया और ये सीधे रूल 121 के तहत रैजोल्यूशन ले आए। मैं समझता हूं कि वह प्रॉपर बात नहीं थी। अच्छी बात यह है कि आप उसकी सस्पैंशन को रिवोक कर दें।

प्रो0 राम बिलास शर्मा : स्पीकर साहब, आपने राम रत्न जी के केस में बहुत बढ़िया निर्णय लिया है। यह सदन हरियाणा की परम्पराओं का एक महान सदन है। किसी सदस्य की तरफ से राजनैतिक छींटा कशी के लिये इसको थाना बना लिया जाए, तो यह अच्छी बात नहीं है। जब दलाल साहब बोलने के लिय खड़े होते हैं, चाहे क्वैश्चन आवर में हो या बजट पर बोलने के लिये हो, तो बीच में राम रत्न जी खड़े हो जाते हैं। तो विपक्ष के सदस्य के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं होना चाहिये। आपने उनके मामले के बारे में जो बात कही, वह बहुत अच्छी थी। उसी बात के तहत मैं कहना चाहता हूं कि छत्तर पाल सिंह वाली बात को भी प्रैस्टिज न बनाया जाए। नेहरा साहब, अभी तो रोडी हल्के में होली का रंग मल कर आए हैं इसलिये ये भी बदले बदले नजर आते हैं। मेरा ख्याल है कि नेहरा जी भी अब यह सलाह नहीं देंगे कि छत्तरपाल जी को सदन से बाहर ही रखा जाए। यदि उनको सदन में बुला लिया जाए, तो उससे सदन की गरिमा बढ़ेगी और चेयर की भी गरिमा बढ़ेगी। स्पीकर साहब, मैं चाहता हूं कि प्रो0 छत्तर पाल सिंह की सस्पैंशन को आप रिवोक करें और उनको सदन में आने की इजाजत दें। हमने उनसे अलग से बात की है। उनके मन में आपके प्रति ऐसी कोई बात नहीं है। उनके मन में आपके प्रति किसी तरह के निरादर की बात नहीं है। उनकी आपके प्रति पूरी श्रद्धा है। आप उनको सदन में आने की इजाजत दें ताकि वे अपनी पोजीशन क्लीयर कर सकें। मेरी आपसे यही सबमिशन है कि उनको सदन में आने की इजाजत दें।

सिंचाई मन्त्री (चौधरी जगदीश नेहरा) : स्पीकर साहब, अपोजीशन के लीडर, प्रो0 राम बिलास शर्मा और कर्ण सिंह दलाल ने कहा कि आप प्रो0 छतर पाल सिंह की सस्पैंशन को रिवोक करें। चौधरी बंसी लाल जी ने भी कहा। स्पीकर साहब, माननीय सदस्य प्रो0 छतर पाल सिंह का जो कंडक्ट था, वह ठीक नहीं था और वह सभी माननीय सदस्यों ने देखा भी था। उनका 15 तारीख को जो कंडक्ट था, वह ठीक नहीं था। मैं इन्हीं से जानना चाहता हूं कि 15 तारीख को उनका जो कंडक्ट था, क्या वह ठीक था। जैसे उन्होंने पोस्टर लगाये हुए थे, उनके बारे में आपने अखबारों में पढ़ा होगा। एक मैम्बर ऐसी-ऐसी बातें लिखे, जिसका कोई आधार नहीं है। फिर ऐसे मैम्बर के बारे में यह कहें कि उसकी सस्पैंशन वापिस होनी चाहिये, यह बात ठीक नहीं है। स्पीकर साहब, वे तीन दिन सदन में रहे और लगातार एक-एक दो-दो घंटे पीछे खड़े रहे। क्या उनका वह कंडक्ट ठीक था? जो माननीय सदस्य राम रत्न वाली बात माननीय सदस्य कर्ण सिंह के बारे में है, क्या वह ठीक है और क्या दलाल साहब का कंडक्ट ठीक है? इनकी पूरी बात का तो मुझे पता नहीं है लेकिन जो वाक्या हुआ, उस समय कर्ण सिंह दलाल साथ थे। क्या दलाल साहब को इस ढंग से एक हरिजन मैम्बर को दबाना शोभा देता है? वह भी इनका मित्र है। दलाल साहब यह कहें कि छतर पाल सिंह की सस्पैंशन को रिवोक किया जाए। क्या यह उन्हें शोभा देता है? मैं कहता हूं कि क्या दलाल साहब का खुद का कंडक्ट ठीक है? जो एक हरिजन मैम्बर को गालियां दें, और उनको यह कहे कि बदबू आ रही है, ऐसे एलीगेशन राम रत्न पर लगाएं। I am talking on the face of it.

श्री अध्यक्ष : नेहरा साहब, आप राम रत्न जी की बात न करें।

चौधरी जगदीश नेहरा : स्पीकर साहब, मेरे कहने का भाव यह है कि जो मैम्बर उनके सस्पैंशन को रिवोक करने की बात कहते हैं, उनका अपना भी कंडक्ट ठीक नहीं है यह भी कहा गया कि प्रो0 छतर पाल सिंह आज आपके चैम्बर में मौन धारण किए हुए बैठे हैं। मैं कहता हूं कि कल को उनकी भूख हड़ताल भी हो सकती है। चौधरी बंसी लाल जी बहुत पुराने मैम्बर हैं और बहिन चन्द्रावती जी भी बहुत पुरानी मैम्बर हैं। इनको पता है कि कई इंस्टांसिज ऐसे भी आए हैं। कई बार मैम्बर्ज को हाउस से सस्पैंड किया गया और उनमें से किसी ने भी मौन धारण नहीं किया। वह कल को मरण धारण भी कर सकते हैं और पैट्रोल ला कर अपने ऊपर छिड़कने की बात भी कर सकते हैं। (शोर)

Prof. Ram Bilas Sharma : Sir, he is provocating. (Interruption).

चौधरी जगदीश नेहरा : स्पीकर साहब, मैं कहता हूं कि जिस दिन उनकी सस्पैंशन हुई, उस दिन उनका कंडक्ट ठीक नहीं था। जिस ढंग से उन्होंने यहां पर बात की क्या उससे हाउस की गरिमा रहेगी? उनका कंडक्ट ठीक नहीं है, इसलिये उनकी सस्पैंशन रिवोक करना उचित नहीं है।

चौधरी बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, अभी नेहरा साहब ने कहा कि प्रो0 छतर पाल सिंह का कंडक्ट ठीक नहीं है और कहा कि जो मैम्बर उनकी सिफारिश कर रहे हैं कि उनकी सस्पैंशन को रिवोक किया जाए, क्या उनका भी कंडक्ट ठीक है ? अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहूंगा कि अच्छी बात तो यह होगी कि पूरी अपोजीशन को ही हाउस से बाहर निकाल दें, अगर हमारा भी कंडक्ट ठीक नहीं है तो।

मुख्य मन्त्री (चौधरी भजन लाल) : आपके बारे में नहीं कहा।

चौधरी बंसी लाल : आप प्रोसिडिंग्ज़ देख लें। नेहरा साहब ने यह कहा है कि जो मैम्बर प्रो0 छतर पाल सिंह की सस्पैंशन को रिवोक करने की सिफारिश कर रहे हैं, क्या उनका कंडक्ट ठीक है ? यदि हम सभी का कंडक्ट खराब है, तो अच्छा यही होगा कि हमें भी आप सदन से बाहर निकाल दें।

चौधरी जगदीश नेहरा : चौधरी साहब, मैंने आपके बारे में नहीं कहा।

चौधरी बंसी लाल : नेहरा साहब ने ऐसा कहा कि जो उसकी रिवोक की सिफारिश कर रहे हैं क्या उनका कंडक्ट ठीक है, ऐसा कहा, बेशक आप प्रोसिडिंग्ज़ देख लें।

चौधरी जगदीश नेहरा : मैंने तो दलाल साहब के लिये कहा था।

चौधरी बंसी लाल : इन्होंने यह कहा कि जो मैम्बर उसके रिवोक की बात कर रहे हैं, क्या उनका कंडक्ट ठीक है ?

चौधरी भजन लाल : मैं इनके साथ बैठा हूं। शायद आपको ठीक से न सुना होगा, इन्होंने यह कहा कि जिन 4 महानुभावों ने उनके रिवोक के बारे में कहा है, क्या उनका कंडक्ट ठीक है ?

चौधरी बंसी लाल : ऐसा नहीं कहा।

चौधरी भजन लाल : ऐसा ही कहा है।

चौधरी जगदीश नेहरा : मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं थी कि जो मैम्बर छतपाल जी की रिवोक की बात कर रहे हैं उनका कंडक्ट ठीक नहीं है। मेरे बोलते हुए जब मैं कह रहा था छतपाल जी के साथ दलाल साहब थे और जब राम रत्न की बात मैंने कहनी शुरु की तो आपने कह दिया कि राम रत्न की बात छोड़िए। मैं कह रहा था कि छतपाल के साथ दलाल साहब रहते हैं और दलाल साहब के साथ छतपाल। दलाल साहब का कंडक्ट भी सही नहीं है, बाकी लीडर्ज के बारे में मैंने ऐसा नहीं कहा।

Chaudhri Bansi Lal : Sir, I will request you to check the record.

श्री अध्यक्ष: उन्होंने कहा कि मेरी ऐसी मंशा नहीं थी। It must be in a lighter way.

वैयक्तिक स्पष्टीकरण—
श्री कर्ण सिंह दलाल द्वारा

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, नेहरा साहब ने मेरा नाम लेकर एक बात कह दी कि मैं छत्रपाल के साथ रहता हूं और वे मेरे साथ रहते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि साढ़े तीन साल तक सारी सरकार उनके साथ रही, तब तक तो वह ठीक था। जब वह मेरे साथ रहने लगा तो वह दुश्मन हो गया। इसलिये मेरा आपसे अनुरोध है कि नेहरा साहब को ऐसे इल्जाम नहीं लगाने चाहियें।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव—

जिला भिवानी में उठान सिंचाई योजना की खराब मशीनों को बदलने सम्बन्धी

Mr. Speaker : Hon'ble Members, I have received a calling attention motion from Shrimati Chandravati regarding repairing of lift irrigation water courses in district Bhiwani. I admit it. She may read her notice.

श्रीमती चन्द्रावती : अध्यक्ष महोदय, मैं इस महान सदन का ध्यान एक अत्यावश्यक लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहती हूं कि जिला भिवानी में लिफ्ट सिंचाई प्रणाली है। पीने का पानी भी उक्त लिफ्ट सिंचाई प्रणाली द्वारा मोघों से सप्लाई किया जाता है। लिफ्ट सिंचाई प्रणाली की मशीनरी वर्ष 1970 में इसकी स्थापना के बाद बदली नहीं गई है। इस समय मुश्किल से 25 प्रतिशत लिफ्टें कार्य कर रही हैं। यहां तक कि उक्त मशीनों के पुर्जे भी नहीं बदले जाते हैं। पानी ओवर फलो होकर गांव रावलधी और कमोद के किसानों की फसलों को प्रतिवर्ष क्षतिग्रस्त करता है तथा उन्हें कोई मुआवजा नहीं दिया जाता है।

खराब मशीनरी, बिजली सप्लाई फेल होने तथा अमले की लापरवाही से पानी ओवर फलो होता है। इससे लाखों रुपये की फसलें क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। लोहारु और भिवानी के गांवों के अंतिम छोर तक पानी नहीं पहुंचता है। वहां पर पीने के पानी की भी समस्या रहती है। विरही के पास भी पानी ओवर फलो होता है।

अतः मैं निवेदन करती हूं कि जल निकास के स्थान पर ड्रेन खोदी जानी चाहिये। लिफ्टों की खराब मशीनें बदली जानी चाहियें। पानी को उक्त ओवर फलो से कमोद तथा रावलधी गांवों की भूमि प्रतिवर्ष प्रभावित होती हैं जो कि एक गम्भीर लापरवाही है। अतः लिफ्टें बदली जानी चाहियें।

अतः मैं सरकार से निवेदन करती हूं कि वह इस संबंध में सदन में एक वक्तव्य देकर अपनी स्थिति स्पष्ट करे।

वक्तव्य—

सिंचाई मन्त्री द्वारा

उक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव सम्बन्धी

Mr. Speaker : Now I would request the Irrigation and Parliamentary Affairs Minister to make a statement.

सिंचाई मन्त्री (चौधरी जगदीश नेहरा) : अध्यक्ष महोदय, जिला भिवानी में सिंचाई विभाग की तीन उठान सिंचाई योजनाएं काम कर रही हैं जिनका नाम सिवानी नहर, जुई नहर और लोहारू नहर उठान योजना है। इन योजनाओं से जल स्वास्थ्य विभाग की कई जल आपूर्ति योजनाओं को पानी मिलता है। इस जल आपूर्ति के लिये जल भण्डार, तालों को प्रथम रोटेशन में उच्च प्राथमिकता से भरवा दिया जाता है। इस विषय में कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई। केवल गांव मिठ्ठी और संधवा जहां कि कमी महसूस की गई है उसका कारण यह है कि ये गांव सिवानी योजना के अन्तिम छोर पर स्थित है जिसकी कमी गाद के जमा होने से और पम्पों की उठान शक्ति कम होने के कारण है। यह उठान योजनाएं 1972 से 1976 में चालू की गई थीं। इन सभी योजनाओं पर कुल मिलाकर 394 पम्प हैं जिनमें से 248 चालू हालत में है। वित्तीय अभाव के कारण पम्पों की मशीन की मुरम्मत नहीं हो सकी और जल उठान में रुकावट आ रही है।

इन उठान योजनाओं पर कुल 20 नम्बर एस्केप बनाये गये हैं। फसल के नुक्सान के मुआवजे की मांग अधिकतर गांव रावलदी, कम्मोद और मेहरा से प्राप्त हुई है। सिवानी नहर पर पम्प हाऊस नं० 1 पर बना एस्केप कभी कभी चलाया जाता है जिसके लिए ओवर फलो पानी के लिए 25 एकड़ भूमि पट्टे पर ली जा चुकी है। इस भूमि के मालकान को 1,550 रुपये प्रति एकड़ प्रति वर्ष पट्टे के एवज में दिये जाते हैं। ये दर कलेक्टर भिवानी द्वारा निर्धारित है। इसी तरह जुई नहर के पम्प हाऊस नं० 1 पर बने एस्केप के लिए 75 एकड़ भूमि ओवर फलो पानी को समाने के लिए अधिग्रहण की गई है। दूसरे स्थानों पर ओवर फलो पानी से फसलों को कोई नुक्सान नहीं होता क्योंकि इस पानी से अधिकतर गांव के जोहड़ भरे जाते हैं। ओवर फलो की समस्या तभी आती है जब बिजली अचानक बन्द हो जाती है इन हालात में नहरों को भारी नुक्सान से बचाने के लिए पानी एस्केप से जाना शुरु हो जाता है।

गांव बिहरी कलां के विषय में ये बताया जाता है कि इस गांव के समीप का एस्केप कभी कभार चला है फिर भी इस गांव के एस्केप से गांव का जोहड़ ही भरता है जिससे फसलों को कोई नुक्सान नहीं होता और न ही आज तक कोई फसलों के नुक्सान का मुआवजा देना पड़ा है।

धनराशि की उपलब्धता के अनुसार पम्पों की मुरम्मत की जा रही है और योजना को हर सम्भव हालत में चालू रखा जाता है।

श्रीमती चन्द्रावती : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री महोदय से एक सवाल पूछना चाहती हूं । मेरे क्षेत्र के 6 पम्पों में से बेरला पम्प तक पानी नहीं पहुंचता । पम्प हाउस नं0 1 जो सवलखी में है, आये साल इसकी वजह से गांव डूब जाते हैं । इसकी कैपेसिटी 1,205 क्यूसिक्स की है और जब इसमें पानी पूरा आता है तो इसमें 1,274 क्यूसिक लास्ट 300 क्यूसिक पानी आते ही एस्केप हो जाता है क्योंकि कुछ तो मिट्टी भरी हुई है और कुछ मशीन खराब है । उनकी कैपेसिटी 300 क्यूसिक से ज्यादा पानी उठाने की नहीं है । यह बात आपके नोटिस में आई कि जब दूसरी जगह पानी नहीं पहुंचता तो एस्केप कहां से होगा । बेरला के बिलावल अटेला में पम्प हाउस का पानी ही नहीं पहुंचता है और दूसरा मैंने बताया कि एक नम्बर पम्प हाउस से 2 नम्बर पम्प हाउस तक 15 किलोमीटर में 10 एकड़ की चौड़ाई तक सेम आया हुआ है । अध्यक्ष महोदय, वहां पर नहर की मुरम्मत नहीं हुई है । माननीय मुख्य मन्त्री जी और श्री नेहरा साहब सिंचाई मन्त्री मेरे साथ चलें । मैं इनको दिखा सकती हूं । (विघ्न) हमारे यहां पानी नहीं पहुंचता । 3-3 महीने तक गांवों में पानी नहीं पहुंचता और यहां पर पानी खराब होता है । अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात बताऊं । पानी जोहड़ में नहीं आता है । उसके आस-पास और खेतों में उसका पानी भरा रहता है । अध्यक्ष महोदय, यह तो तथ्य की बात है इसलिए मैं आपसे कहना चाहती हूं कि वहां पर इतना पानी खराब हो जाता है । अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री जी से यह जानना चाहती हूं कि वहां पर जो मशीनरी है, उसको कब तक ठीक करवाएंगे, नहर में जो गाद है, उसको कब तक निकलवाएंगे और इसमें जो लापरवाही से एस्केप होता है, उसके लिए दोषी अमले को कब तक ठीक करेंगे ?

चौधरी जगदीश नेहरा : अध्यक्ष महोदय, पम्प हाउस नहीं बल्कि पम्प्स खराब होते हैं । पम्प हाउस में कई जगह चार पम्प्स कई जगह तीन हैं और कई जगह तो 6 भी हैं । इस तरह से ये अलग-अलग हैं और उनमें से खराब भी रहते हैं । जिस वजह से कैपेसिटी कम रहती है । मैंने जवाब में भी बताया है कि दो जगहों पर एस्केप बना हुआ है । जहां तक इन्होंने कहा है कि कब तक ठीक करवाएंगे तो अध्यक्ष महोदय, 1995-96 में हम पैसा दे रहे हैं और हम इनको जल्दी से जल्दी ठीक करवाने की कोशिश करेंगे । इसके बाद इन्होंने कह दिया कि फलानी जगह पर सेम आई हुई है । हो सकता है कि उस जगह से पानी निकलता हो जिस वजह से वहां सेम आ सकती है । अध्यक्ष महोदय, जहां तक पानी वापिस आने की बात है, तो लोगों ने जोहड़ बना रखे हैं, वहां पर पानी चला जाता है । इसके साथ ही जो सिल्ट की बात कही गई है उस बारे में मेरा कहना यह है कि हम उसको निकलवाने की कोशिश करेंगे ।

श्रीमती चन्द्रावती : क्या मंत्री जी यह बताएंगे कि यह काम कब तक करवा देंगे ? यह जो लिफ्ट सिस्टम है, यह कब तक 1,205 क्यूसिक पानी उठा सकेगा

और कब तक लोगों को मुआवजा मिलेगा ? जोहड़ों में तो पानी ही नहीं है और ये वहां पर पानी कब तक देंगे ? अब स्थिति यह है कि यह कभी तो मिल जाता है और कभी नहीं मिलता है ।

चौधरी जगदीश नेहरा : अध्यक्ष महोदय, यह इतना बड़ा काम है कि इसको कब तक करवा देंगे, इसकी तारीख निश्चित नहीं की जा सकती है । कारण यह है कि कोई पम्प तो 140 फुट पर है और कोई 100 फुट पर है। टोटल पम्प हाऊस 46 हैं और 400 के करीब बड़े पम्प्स हैं। इसी तरह से नहरें 200-300 के करीब हैं । तो यह निश्चित तारीख के बारे में नहीं कहा जा सकता है कि यह काम कब तक हो जाएगा । हम तो उसको ठीक करवाने की पूरी कोशिश करेंगे ।

वर्ष 1995-96 के बजट पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now the general discussion on the Budgot for the year 1995-96 will be resumed.

चौधरी जाकिर हुसैन (तावडू) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं । वित्त मंत्री महोदय, ने जो 1995-96 का बजट पेश किया है, उसके लिए मैं उनको मुबारिकबाद देना चाहूंगा कि इन्होंने कर-रहित बजट पेश किया है । इन्होंने जो सिन्दूर, मंगल सूत्र, चूल्हा, बाजरा और मक्की इत्यादि पर छूट दी है, उससे हर वर्ग को लाभ होगा।

जैसा कि आप सब भी जानते हैं कि अभी हमारी सरकार ने पंचायतों के चुनाव करवाए हैं। यह बहुत ही सही ढंग से और शांति से करवाए गए हैं।

(इस समय सभापतियों की सूची में से एक सदस्या श्रीमती चन्द्रावती पदासीन हुई ।)

चेयरमैन साहिबा, मैं पंचायती राज के चुनावों के साथ-साथ यह भी जिक्र करना चाहूंगा कि पिछले दो-तीन सालों में जितना गांव का विकास एच0 आर0 डी0 एफ0 के पैसे से हुआ है उतना पहले कभी भी गांवों में विकास नहीं हुआ । इसी तरह से चीफ इलैक्शन कमिश्नर के निर्देशानुसार हर वोटर के आईडैन्टी कार्ड बनाए गए और साथ ही लोगों से यह भी कहा गया कि वे अपने पहचान पत्र चार या पांच मौकों में से एक बार में जरूर बनवा लें । यानी वोटरों को इसके लिए चार-पांच बार मौका दिया गया ताकि वोटर अपने वोट के अधिकार को प्रयोग में ला सकें ।

चेयरमैन साहिबा, हमारे प्रदेश के लोग 80 परसैन्ट गांवों में रहते हैं और हमारा प्रदेश एक किसान प्रमुख प्रदेश है । किसानों की आज सबसे बड़ी जरूरत

[चौधरी जाकिर हुसैन]

अपनी फसलों के लिए, रोजमर्रा के कामों के लिए और घर के लिए बिजली की है। जैसे कि सदन में लगातार चर्चा होती रही है, और सब मानते भी हैं कि बिजली की प्रदेश में दिक्कत है। बिजली की हमारे प्रदेश में ही नहीं बल्कि सारे देश में ही कमी है और इसीलिए हम भी इससे प्रभावित हैं। लेकिन जहां तक विद्युत मंत्री का, सरकार का या मुख्य मंत्री जी का सवाल है, उन्होंने इस दिशा में बहुत प्रयास किए हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि बिजली लोगों को ठीक तरह से मिलने लगेगी। पीछे भी बिजली का प्रदेश में सुधार हुआ है। सरकार ने कई कदम इस बारे में उठाए हैं। सरकार का सबसे बड़ा कदम तो इस बारे में थर्मल प्लांट स्थापित करने का है। चाहे वह प्लांट एक हजार मैगावाट का हो या 75 मैगावाट से सौ मैगावाट का हो। सरकार ने यह भी कहा है कि ये प्लांट प्राईवेट सैक्टर में भी लगाए जाएंगे। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि लोगों को ऐसा करने से राहत मिलेगी। मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि जो बिजली हमारे पास है, या जो बिजली सरकार लोगों को दे रही है, चाहे वह उद्योग हों, या वह कृषि हो, तो उसमें सरकार को एक बात जरूर सुनिश्चित करनी चाहिए कि जो भी सरकार छः या आठ घंटे बिजली दे रही है, उसमें बिजली की चोरी नहीं होनी चाहिए तथा बिजली बोर्ड के कर्मचारियों को गांवों में जाकर लोगों की दिक्कतों को दूर करना चाहिए ताकि लोग अपनी फसलों को पानी दे सकें और दूसरे अन्य काम कर सकें।

चेयरमैन साहिबा, जहां तक सड़कों की बात है, पीछे काफी सड़कों की मुरम्मत हुई है और सड़कों पर पैच वर्क भी हुआ है। मैं मुख्य मंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि जब ये पिछले साल मेरे हल्के में गए थे तो इन्होंने तावडू से कोटा खंडेला तक सड़क को चौड़ा करने यानी दुगनी करने का ऐलान किया था। उस सड़क की एडमिनिस्ट्रेटिव ऐप्रूवल तो नूंह के ऐक्सियन के पास पहुंच गयी है लेकिन मैं मुख्य मंत्री जी से यह भी रिक्वैस्ट करना चाहूंगा कि उसके लिए आप पैसे का भी बन्दोबस्त कराएं ताकि जल्दी ही वह सड़क चालू हो सके। यह सड़क नैशनल हाईवे और तावडू को जोड़ती है। इसी तरह से मेरे हल्के की कुछ सड़कें जैसे मैठेपुर से छापसा, इंडी से नवाबगढ़, शिकरावा से अलावलपुर को भी बनाया जाना चाहिए क्योंकि इन सड़कों को बनाने से बहुत से गांवों के लोगों को फायदा मिलेगा। मैं मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि वे इन सड़कों की भी मंजूरी दें। इसी तरह से बसई से बब्रकन, करथला से गोलपुरी की सड़कों की मुरम्मत भी की जानी चाहिए। ये सड़कें बहुत ही बुरी हालत में हैं। चेयरमैन साहिबा, मैं आपके माध्यम से अर्ज करना चाहूंगा कि पहले ये सड़कें मार्किटिंग बोर्ड ने बनायी थीं लेकिन जब से ये सड़कें बनी हैं, तब से इन पर कोई भी पैच वर्क नहीं हुआ और ये सड़कें आज खत्म होने की स्थिति में हैं। मैं कहना चाहूंगा कि चाहे इनको मार्किटिंग बोर्ड बनाए या पी० डब्ल्यू० का महकमा बनाए, मगर इन सड़कों की मुरम्मत प्रायोरिटी पर

की जानी चाहिए । इसके अलावा जहां तक पानी का सवाल है, पानी किसान की सबसे बड़ी जरूरत है । खासतौर पर दक्षिणी हरियाणा का जो हिस्सा है, चाहे वह गुड़गांव हो या फरीदाबाद हो, इसके लिए एस0वाई0एल0 का बनना बहुत ही जरूरी है । वैसे मुख्य मन्त्री जी ने इसके लिए बहुत प्रयास किए हैं । प्रधानमन्त्री जी से भी इन्होंने मुलाकातें की हैं ताकि यह नहर जल्दी बन सके क्योंकि चेयरमैन साहिबा, इसी नहर के बनने के बाद मेवात कैनाल भी बन सकेगी । मैं अर्ज करना चाहूंगा कि हमारी एस0वाई0एल0 कैनाल जल्दी से जल्दी पूरी हो और साथ ही साथ मैं सरकार को बधाई देना चाहूंगा कि सरकार ने सिंचाई की सुविधा के लिए जो कदम उठाए हैं, वह सराहनीय हैं, चाहे वर्ल्ड बैंक की 1858 करोड़ रुपये की परियोजना है जो कि 6 वर्ष में लागू होगी या चाहे वह यमुना जल समझौते की बात हो जो कि बहुत उलझा हुआ मसला था और जिसकी वजह से हथिनीकुंड बैराज बनना शुरु हो गया है । पिछले दिनों आगरा कैनाल का इस सदन में बार-बार जिक्र हुआ । आगरा कैनाल पुन्हाना और पलवल हल्के को लगती है । हमने अभी जाकर देखा है कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने हमारी सरकार के प्रयासों से वहां काम शुरु कर दिया है । पुन्हाना के एरिये में काफी माइनरों की सफाई हो गई है । आगरा कैनाल के कंट्रोल की बात थी । जैसा कि मुख्य मन्त्री जी ने बताया कि सिंचाई मंत्री जी इस बारे में मीटिंग कर रहे हैं ताकि जब तक उसका कंट्रोल हमारे पास न आए, कम से कम उसका दफ्तर पलवल में बन जाए जिससे छंटाई वगैरह का काम हो जाए और लोगों को राहत मिल सके । हमारे मेवात एरिया में नहर का तो एक सिस्टम है परन्तु उस इलाके में पानी की कमी है । हमारे यहां नहरों में डि-सिल्टिंग और रजवाहों की छंटाई नहीं हुई है जिससे रजवाहे अटे हुए हैं । जो पानी लोगों को मिलना चाहिए वह नहीं मिल रहा है । मैं आपके माध्यम से सिंचाई मन्त्री जी से अनुरोध करूंगा कि या तो वे खुद चलकर देख लें या अफसरों की टीम को निर्देश दें कि वे वहां जाकर देखें और उसके लिए फंड्ज दिए जाएं जिससे डि-सिलटिंग हो सके । इसी तरह गुड़गांव कैनाल में भी डी-सिलिटिंग की जरूरत है । डि-सिलिटिंग न होने की वजह से किसानों को पूरा पानी नहीं मिल पा रहा है । डि-सिलिटिंग कराई जाए जिससे जितना हमारा पानी है, वह हमारे मेवात को मिल सके । चेयरमैन साहिबा, पिछले दिनों मुख्यमन्त्री जी ने नूंह में माईनर बनाने के बारे में एलान किया है । मेरे हल्के में दो माईनरें बननी जरूरी हैं एक दुबालु माईनर और दूसरी मीरका माईनर । यह माईनर बनवाई जाए जिससे इलाके के लोगों को राहत मिल सके और लोग अनाज पैदा कर सकें । जहां तक कृषि का सवाल है, किसानों को बहुत सुविधाएं दी गई हैं । वह सुविधा सबसिडी के तौर पर है जो जिप्सम और स्प्रिंकलर्ज पर दी है, इसके लिए सरकार बधाई की पात्र है । सन् 1980 में मुख्यमन्त्री जी ने मेवात डिवैल्पमैंट बोर्ड की स्थापना की थी । इस बोर्ड की स्थापना इलाके के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए की गई थी । इस साल भी माननीय वित्त मन्त्री जी ने बजट में कोई 4 करोड़ 11 लाख रुपया रखा हुआ है और 4 करोड़ रुपये के लगभग सैन्टर से मिलेगा । इस हिसाब से 8 करोड़ रुपये के लगभग 1995-96 में मेवात एरिया

[चौधरी जाकिर हुसैन]

के विकास के लिए मिलेगा। इसके लिए हम मेवात एरिया के लोग सरकार के बहुत शुक्रगुजार हैं। मैं अर्ज करना चाहूंगा कि जो पैसा सरकार जिस काम के लिए दे, वह पैसा वहां लग जाए। 1992–93 में बजट में साढ़े तीन करोड़ रुपया इस इलाके के विकास के लिये था जिसमें से 2 करोड़ 87 लाख रुपया खर्च हुआ। 1993–94 में बजट में साढ़े तीन करोड़ था जिसमें से 2 करोड़ 25 लाख रुपया खर्च हुआ। 1994–95 में बजट में 3 करोड़ 74 लाख था जिसमें से 3 करोड़ रुपया खर्च हो सका इसलिए अनुरोध है कि इस बार पूरा पैसा इस्तेमाल हो जाए जिससे हमारे इलाके के तरक्की के काम हो सकें। इसके साथ ही मैं यह भी बताना चाहता हूं कि रोम की अन्तर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि नामक जो स्कीम है वह बहुत अच्छी स्कीम है। इसके तहत अढ़ाई करोड़ रुपये अमरीकी डालर मिलने हैं। यहां की टीम को सरकार ने बहुत सहयोग दिया। इसमें से तकरीबन 95 करोड़ रुपये बनते हैं, जो कि मेवात में लगेंगे। चेयरमैन साहिबा, इसके साथ-साथ मैं यह बताना चाहता हूं कि हमारे मेवात के एरिया व गुड़गांव एरिया के अन्दर उद्योगों ने काफी तरक्की की है और इसी वजह से गुड़गांव जिला आज इंटरनैशनल मैप पर है। इसके लिये हम सरकार के बहुत ही आभारी हैं।

जहां तक शिक्षा की बात है। सरकार इस बारे में बड़ी ही प्रयासरत है और सरकार ने शिक्षा के प्रसार एवं प्रचार के लिए कई कदम उठाए हैं। चाहे नकल रोकने का मामला हो, या दूसरे कोई और स्कूलों से संबंधित मामले हों, सरकार हर तरफ पूरी तरह से जागरूक है। इस बार सिवाये एक आध केस के, सरकार ने नकल पर पूरा कंट्रोल पा लिया है और नकल भी केवल नाम मात्र ही है। आगे सरकार इस बारे में पूरी तरह से सतर्क है। जहां तक लड़कियों की मुफ्त शिक्षा का सवाल है, इस बारे में भी सरकार ने काफी कुछ कर दिखाया है। इसके साथ-साथ मैं यह कहूंगा कि मेवात डिवैलपमैंट बोर्ड है या चाहे शिवालिक बोर्ड है, वे बैकवर्ड एरिया में हैं, इसलिये सरकार को इस ओर भी ध्यान देना चाहिये। बच्चों की पढ़ाई से जुड़ा हुआ एक सवाल है। यहां पर जे0 बी0 टी0, पोलिटैक्निक स्कूल्ज, बी0एड0 और आई0टी0आई0ज0 में इस इलाके के लोगों को सरकार की तरफ से ज्यादा से ज्यादा रिजर्वेशन मिलनी चाहिये ताकि इस इलाके की दशा में और सुधार आए। और इस तरह का सरकार को कोई प्रबन्ध करना चाहिये कि यहां से जो बच्चे अपनी शिक्षा लेकर निकलें, उनको इसी अपने एरियाज में ही नौकरियां भी उपलब्ध हो सकें। इसलिये मेरी सरकार से प्रार्थना है कि सरकार इस बात की ओर विशेष तौर पर ध्यान दे।

इसके साथ-साथ मैं वाटर सप्लाई स्कीम्ज के बारे में भी कुछ कहना चाहूंगा। अभी मुख्य मन्त्री महोदय ने गुड़गांव के अन्दर पीने के पानी की व्यवस्था की है। वहां एक कैनाल को पूरा करवाया है। उसका उद्घाटन भी किया है। इससे सारे

गुड़गांव के इलाके में लोगों में बहुत ही खुशी की लहर दौड़ रही है । इसके साथ-साथ मैं मुख्य मन्त्री महोदय से यह रिकवैस्ट करूंगा कि इस मेवात के एरिया की खुशहाली के लिये सोनीपत से गुड़गांव तक जो नहर निकाली गई है, उसको आगे मेवात के एरिया तक बढ़ाया जाए ताकि लोगों को पीने के पानी की और सिंचाई के लिये पानी की और सुविधा मिल सके । इसके साथ मैं वाटर सप्लाई के बारे में और भी कहूंगा कि मुख्य मन्त्री महोदय इस ओर भी विशेष ध्यान दें जिससे हमारे इलाके को पानी की और सुविधा मिल सके क्योंकि आज जो हमारे यहां पर एक वाटर वर्क्स है, वह 28-28 गांवों को फीड करता है । इसलिये इस इलाके को और पानी की सुविधा प्रदान की जाए । पानी तभी इस इलाके को ज्यादा मिलेगा, जब यह नहर गुड़गांव से आगे बढ़ाई जाएगी । तभी सभी गांवों को सुचारू रूप से पानी मिलेगा ।

इसके साथ-साथ मैं एक और बात कहना चाहूंगा कि सैन्ट्रल गवर्नमैंट की स्माल टाऊनज़ के विकास की जो स्कीम है, जिसके अन्तर्गत 20 हजार या 20 हजार से कम आबादी वाले गांवों को सीवरेज और पीने के पानी की सुविधाएं प्रदान करने का लक्ष्य है । इस स्कीम के तहत पहले ही केन्द्र सरकार ने सोहना और पटौदी, दो कस्बों को इसके लिये चुना हुआ है । मेरा सरकार से निवेदन है कि वह केन्द्र सरकार पर इस बात के लिये जोर डाले कि वह इस स्कीम के अन्तर्गत हमारे तावडू के क्षेत्र को भी शामिल कर लें ताकि वहां के लोगों को भी इस प्रकार की सारी सुविधाएं प्रदान की जा सकें । इस स्कीम में इन इलाकों की सड़कों के काम को भी शामिल करवाया जाए ।

इससे आगे मैं मुख्यमन्त्री महोदय व ट्रांसपोर्ट मन्त्री महोदय से भी रिक्वैस्ट करूंगा कि जहां सरकार की ओर से मेरे हल्के का पूरी तरह से हर लिहाज से ख्याल रखा गया है, उसी तरह से अगर मेरे हल्के में एक बस-स्टैण्ड बन जाए तो मेरी सभी उम्मीदें पूरी हो जाएंगी । इसके लिये मैं उनका आभारी रहूंगा ।

इसके साथ-साथ मैं वित्त मन्त्री महोदय से यह निवेदन करूंगा कि जो-जो बातें मैंने यहां पर कही है, उनकी ओर पूरा ध्यान दिया जाए । इन अपनी बातों के साथ मैं इस बजट का जो उन्होंने पेश किया है, समर्थन करता हूं और सभापति महोदया, आपका धन्यवाद करता हुआ अपना स्थान लेता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया । धन्यवाद ।

चौधरी बंसी लाल (तोशाम) : सभापति महोदया, मैं इस बजट के संबंध में कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपके जरिए सदन के नोटिस में लाना चाहता हूं । कल मैं शाहबाद के इलाके में गया था और वहां मुझे उस इलाके के किसानों ने बताया कि शाहबाद के इलाके का जो किसान है, वह पंजाब में अपना गन्ना ले जाना चाहता है । शम्भू बार्डर पर पंजाब सरकार गन्ना 90-92 रुपए क्विंटल के हिसाब से खरीद रही

[चौधरी बंसी लाल]

है और वहां की सरकार ने वहां पर किसानों के लिए हर तरह की सहूलियतें प्रदान कर रखी हैं। चाहे वह खाने की हो, पीने की हो या दूसरी चीजों की हो। उन्हें हर प्रकार की सहूलियतें प्रदान कर रखी हैं और जब किसान ट्रकों में भर कर अपना गन्ना वहां पर ले जाने लगता है तो पुलिस के स्क्वैड द्वारा उनको धक्के मार-मार कर वापिस शाहबाद की मिलों में ले जाया जाता है। सभापति महोदया, अगर पंजाब की शूगर मिलें गन्ना 90-92 रुपये पर क्विटल खरीद कर कमाई कर सकती हैं तो मेरी समझ से यह बात बाहर है कि फिर हरियाणा की मिलें इस भाव पर गन्ना खरीद कर कमाई क्यों नहीं कर सकती। अगर सरकार समझती है कि हरियाणा की मिलें वह कमाई नहीं कर सकतीं तो फिर उन मिलों को बन्द कर देना चाहिए और गन्ने को पंजाब में जाने दें क्योंकि वहां इस के लिये कोई पाबन्दी तो है नहीं। मैं आपको बताता हूं कि हमारी हरियाणा की शूगर मिलें यू०पी० से गन्ना ले रही हैं। और शायद इस साल भी लाए होंगे। तो मैं इससे कोई वजह नहीं समझता कि शाहबाद के किसानों को पंजाब में गन्ना ले जाने की इजाजत न दी जाए। मैं चाहूंगा कि मुख्य मन्त्री जी इस बात का जवाब दें कि यह क्या हो रहा है? इसके अलावा एक चीज और है कि पूरे हिन्दुस्तान की बहुत सी स्टेटों ने मौलासिज को पूरा खोल दिया है लेकिन हरियाणा सरकार ने 50 परसैंट पर कन्ट्रोल कर रखा है और 50 परसैंट खोल रखा है। जो 50 परसैंट मौलासिज कन्ट्रोल पर देना पड़ता है, वह 9, 11 और 14 रुपए क्विटल के हिसाब से देना पड़ता है जबकि मार्किट में इसका भाव साढ़े तीन सौ रुपए से लेकर पौने चार सौ रुपए क्विटल का है। चेयरमैन साहिबा, जो 50 परसैंट खुला रखा है, उस पर सरकार ने पाबन्दी लगा रखी है कि उस 50 परसैंट में से 75 परसैंट 180 रुपए क्विटल के हिसाब से डिस्टिलरीज को देना पड़ेगा। मैं समझता हूं कि यह तो एक तरह से डिस्टिलरीज को फायदा पहुंचाने वाली बात है और किसान का नुक्सान करने वाली बात है। अगर किसान का मौलासिज 350 रुपए के हिसाब से बिकेगा तो उसके गन्ने का भाव भी बढ़ेगा। यह किसान के साथ ज्यादती है। यह सरकार किसान के साथ ज्यादती करने में झिझकती नहीं लेकिन डिस्टिलरीज को फायदा होना चाहिए।

इसी तरह से यमुना वाटर एग्रीमैंट के बारे में सदन में पहले भी चर्चा हो चुकी है और इस अधिवेशन में भी हो चुकी है लेकिन मुख्य मन्त्री जी एक बात का जवाब अब तक सही नहीं दे पाए हैं। वह यह कि जो चार नदियां राजस्थान से हमारे यहां आती हैं। उन के पानी पर हमारा राइपेरियन राईट था। उस पानी को राजस्थान ने अपने यहां बांध बना कर रोक लिया। अगर मुख्य मन्त्री जी एक महीना या बीस दिन उस एग्रीमैंट पर दस्तखत न करते और कहते कि पहले हमारा हिस्सा दो तो इसमें क्या बुराई थी? राजस्थान कैनाल सिरसा जिले से हो कर निकलती है। ये कह सकते थे कि उन नदियों के पानी के बदले हमें राजस्थान कैनाल का पानी दो। वह पानी सिरसा में इस्तेमाल हो जाता। अभी जाकिर हुसैन जी

ने कहा कि उनके यहां पीने का पानी नहीं है क्योंकि जो चार नदी नालों का पानी राजस्थान से आता था, वह ज्यादातर मेवात में आता था और वहां से दूसरी जगहों पर जाता था। अगर पानी आता तो इनके यहां पीने के पानी की कमी न रहती। तो जब मुख्य मन्त्री जी ने दस्तखत किए तो उस बारे में इन्होंने कहा था कि राजस्थान के मुख्य मन्त्री ने कहा है कि आप इंस्पैक्शन कर लें। हमने कोई बांध नहीं बनाए हैं। तो इंस्पैक्शन करने का तो दो दिन का काम था। आप अफसरों की कमेटी बना कर पहले यह काम कर लेते। राम बिलास जी ने भी कहा था कि उनके इलाके के साथ लगते राजस्थान के इलाके में उन्होंने बांध बना रखे हैं। आप अधिकारियों की एक टीम भेज देते और फैसला हो जाता। तो मैं समझता हूं कि मुख्य मन्त्री जी ने अभी तक इस बात का सही उत्तर नहीं दिया है। मैं उनसे जानना चाहूंगा कि यह ज्यादती क्यों हुई? चौटाला साहब आज सदन में हाजिर नहीं हैं। उन्होंने कहा था कि हरियाणा के इलाके में एल0वाई0एल0 पहले क्यों बनाई गई? चेयरमैन महोदया, हरियाणा के हिस्से में जो एस0वाई0एल0 बनी हुई है, वह आज भी इस्तेमाल होती होगी क्योंकि एन0बी0 लिंक की कैपेसिटी 2700 क्यूसिक से ज्यादा है। उसमें सिल्ट और घास खड़ा है। इस वजह से उसमें 1600-1700 क्यूसिक पानी चलता है। जब वह पूरा पानी ले नहीं सकती तो जो एस0वाई0एल0 हरियाणा में बनी हुई है, बाकी के पानी का उसमें इस्तेमाल होता है। अगर वह नहर न बनी होती तो हम आज इतना पानी भी इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। हमारा एक हजार क्यूसिक पानी बेकार चला जाता है। मेरा ख्याल है कि चौटाला साहब इस बात को भूल गए कि यह नहर क्यों बनाई गई थी? जब वे मुख्य मन्त्री थे, तो उन्होंने कभी यह भी नहीं देखा होगा कि वह नहर कहां है? उन्होंने एस0वाई0 एल0 नहर को कभी देखा ही नहीं है। उस नहर का क्या इस्तेमाल है? अगर उन्होंने देखा है तो जिस दिन वे सदन में आए, अपनी पर्सनल एक्सप्लेनेशन में यह बात बता दें। चेयरमैन महोदया, फरीदाबाद और गुड़गांव जिलों में जो माईन्ज हैं, उन माईन्ज का दुरुपयोग हो रहा है। जिला हिसार और बाहर से लोग ला करके लोगों को वह माईन्ज दे रखी हैं। वहां पर हरियाणा सरकार को कई लाख रुपए का नुकसान होता है। अभी दो-तीन दिन पहले शायद इसी सदन में कहा हो। यह 15-3-95 का हिन्दुस्तान टाईम्ज अखबार है। इसके पेज 7 कालम 1 में बताया हुआ है। इसमें हरियाणा मिनरल्ज लि0 के चेयरमैन चौधरी अजमत खां ने कहा है कि अगर ये माईन्ज सरकारी कर दी जाएं और हरियाणा मिनरल्ज लि0 को दे दी जाएं तो वह हरियाणा के सभी बुजुर्गों को बुढ़ापा पैंशन दे देगी तथा चीफ मिनिस्टर रिलीफ फण्ड में भी कुछ पैसा दे देगी। मैं कहता हूं कि यह काम उसको देने में क्या हर्ज है? सरकार का तो कुछ भार कम हो जाएगा। मैं समझता हूं कि वहां की माईन्ज का काम हरियाणा मिनरल्ज लि0 को दे देना चाहिए। चेयरमैन महोदया, हरियाणा मिनरल्ज लि0 के चेयरमैन इनकी अपनी पार्टी के हैं, उनके जिम्मे यह काम दे दिया जाए तो बहुत अच्छा होगा।

[चौधरी बंसी लाल]

चेयरमैन महोदया, मैंने 1986 में माईन्ज को नैशनेलाईज कर दिया था लेकिन कुछ चौधरी देवी लाल ने वापिस दे दिया और कुछ हाई कोर्ट से स्टे ले आए बाकी चौधरी भजन लाल ने किस को दिया, इसको वह जानें ।

चेयरमैन महोदया, यह कम्पट्रोलर एण्ड आडिटर जनरल आफ इण्डिया की रिपोर्ट है । इसमें एक बात मैं प्वायंट आउट करना चाहता हूं ।

This is a Report of the Comptroller and Auditor General of India for the year ended 31 March, 1994.

> "The Excise and Taxation Commissioner, Haryana, also held (April 1990) in the case of a distillery at Hathin that recovery of 36.61 proof litres of spirit from one quintal of molasses as provided in the Rules was quite correct.
>
> During the audit of the records of Deputy Excise and Taxation Commissioner, Hisar, it was noticed (June 1991) that in a distillery at Hisar 88,81,072.3 proof litres of spirit were manufactured in the year 1990-91 from 2,98,567.35 quintals of molasses as against 1,09,30,551 proof litres recoverable as per the norm laid down in the Rules. The shortfall of 20,49,478.7 proof litres involved loss of excise duty amounting to Rs. 143.46 lakhs.
>
> On this being pointed out (July 1991) in audit, the department issued (June 1992) notice for recovery to the distillery. The Excise & Taxation Commissioner further informed in October 1993 that the matter was under consideration with the Government. Further report in the matter has not been received (October 1994)."

मैं समझता हूं कि इस केस में खासी इंवैस्टीगेशन की आवश्यकता है । अगर यह रिपोर्ट हाउस में डिस्कस हो जाए तो और भी अच्छा है ।

चेयरमैन महोदया, आज तक हाउस में एक बात क्लीयर नहीं हो पाई कि बिजली के लाईन लौसिज कितने हैं । सरकार ने एक बात यह कही कि अभी इलैक्ट्रोनिक मीटर लगाएंगे । मैं जानना चाहता हूं कि ये मीटर कैसे होंगे और कहां पर लगेंगे ? धारूहेड़ा में एक फैक्टरी पकड़ी गई जिनके मीटर का ताल्लुक मेन गेट से था । कोई चैक करेगा, दरवाजा खोलेगा तो मीटर चल पड़ेगा और चैक करने 16.00 बजे के बाद दरवाजा बन्द होगा तो मीटर भी बन्द हो जाएगा । इस बारे में मैंने पहले भी सुझाव दिया था कि जितनी भी फैक्ट्रियां हैं, उन सब के मीटर बाहर सड़क पर लगने चाहिए ताकि कोई भी आये, किसी भी समय आये चैक कर ले । जिस तरह अब मीटर चल रहे हैं और जिनका जिक्र मैंने किया है कि दरवाजा खोलो तो मीटर चल पड़ेंगे और दरवाजा बन्द करेंगे तो मीटर बन्द हो जाएगा, ऐसे केसिज राजस्थान और हरियाणा के धारूहेड़ा में भी पकड़े गए हैं । ये

जो अब नए मीटर लगा रहे हैं, मैं जानना चाहता हूं कि वे किस प्रकार के होंगे, कहां लगेंगे ? यह बताने का कष्ट करें ।

चेयरमैन महोदया, अब मैं थर्मल प्लांट्स के बारे में जिक्र करना चाहूंगा । हमारे यहां पर पानीपत और फरीदाबाद की थर्मल प्लांट की जो यूनिटें हैं, मैं जानना चाहूंगा कि उनमें से कितनी काम कर रही हैं और कितनी नहीं कर रही हैं उनका प्लांट व लोड फैक्टर क्या है और क्या वे प्रोडक्शन कर रहे हैं ? इस बारे में सरकार अपनी स्थिति स्पष्ट कर दे ।

चेयरमैन महोदया, अब सड़कों की स्थिति का जिक्र करते हुए मैं कहना चाहूंगा कि सरकार तो यह कहती है कि हमने प्रदेश की सारी सड़कों की मुरम्मत करा दी है । राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जवाब देते समय पता नहीं मुख्य मन्त्री जी ने इस बारे में स्थिति स्पष्ट की या नहीं, कुछ पता नहीं चला क्योंकि ये तेजी से पढ़ते जा रहे थे । अब मैं चाहूंगा कि वे इस बारे में स्थिति स्पष्ट करें क्योंकि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में सरकार ने कहा है कि 7,538 किलोमीटर सड़कों का इन्होंने साढ़े तीन साल में सुधार किया है और 831 किलोमीटर सड़कों को चौड़ा किया गया है और इन साढ़े तीन साल में 484 कि0मी0 नई सड़कें बनाई हैं । चेयरमैन महोदया, आप देखिए कि जहां राज्य में 22–23 हजार कि0मी0 सड़कें हों और गत साढ़े तीन वर्षों में केवल 831 कि0मी0 सड़कों को चौड़ा करके सुधारा जावे, यह जंचने वाली बात नहीं है । यह सरकार मेनटेनैंस और रिपेयर पर सारी स्टेट में क्या ध्यान दे रही है, इस बारे स्थिति स्पष्ट करे ।

चेयरमैन महोदया, अब मैं नहरों की डी-सिल्टिंग के बारे में कहना चाहता हूं । हमारे हरियाणा में जितनी नहरें हैं, और माईनर्ज हैं, अगर उन सबकी प्रौपर मेन्टेनैंस हो जाय तो मैं समझता हूं कि 30–40 परसैंट पानी की समस्या हल हो सकती है । क्योंकि मैंने इस सब्जैक्ट को अच्छी तरह से स्टडी किया है । यहां पर हाउस में कहा जाता है कि मौनसून शुरु होने से पहले डी-सिल्टिंग करा दी जाएगी, लेकिन इस समस्या की तरफ सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही और डी-सिल्टिंग की समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है । सरकार ने हाउस में खुद माना है कि जहां 1200 क्यूसिक्स पानी आना चाहिए वहां डी-सिल्टिंग प्रौपर न होने की वजह से सिर्फ 300 क्यूसिक्स पानी ही आ रहा है । अतः इस बारे में, जो लिफ्ट इरीगेशन की स्कीम्ज हैं, उनके बारे में मुख्यमन्त्री को सुझाव दूंगा कि यह सारा काम ठीक हो, इसके लिये मुख्य मन्त्री व मन्त्री खुद निरीक्षण करें । अब लिफ्ट इरीगेशन की स्कीमों पर, यानि इन नहरों पर जो पुल बने हुए हैं, वे बालू रेत की वजह से ऊंचे उठ गए हैं और नहरों में से ही ऊंट और बैलगाड़ियां निकल जाती है । इसलिए मेरा सुझाव है कि इनकी डी-सिल्टिंग प्रौपर कराई जावे और मुख्य मन्त्री जी 10 परसैंट नहरों की इन्सपैक्शन खुद करें और जो पंप हाउसिज लगे हुए हैं, उनको भी वे खुद

[चौधरी बंसी लाल]

चैक करें । मैंने ऐसे पंप हाउसिज भी देखे हैं, जिन पर दो महीने पानी आया और उसके बाद आया ही नहीं । फिर ये कह रहे हैं कि हम पीने के पानी की माता 70-80 लीटर प्रति व्यक्ति करने जा रहे हैं जबकि दो-दो साल से किसी गांव में पीने का पानी जा ही नहीं रहा । ये कैसे उनको 70-80 लीटर प्रति व्यक्ति पानी देंगे ? अतः मेरा अनुरोध है कि सरकार इस तरफ विशेष ध्यान दे ।

चेयरमैन महोदया, यह सरकार वर्ल्ड बैंक से कर्जा लेकर अपना काम चला रही है । मैं मुख्य मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि अब तक सरकार ने वर्ल्ड बैंक से टोटल कितना कर्जा लिया है यह भी बताने की कृपा करें । सरकार बताए कि नहरों के लिए, सड़कों के लिए, एच0एस0ई0बी0 के लिए और शिक्षा के लिए या एग्रीकल्चर के लिए वर्ल्ड बैंक से कितना पैसा लिया है । सारी सूचना अलग-अलग से बता दें । मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे ये कर्जा ले रहे हैं, उससे कहीं ऐसी स्थिति न हो जाए कि उस लिए हुए ऋण का ब्याज भी हरियाणा न दे सके । चेयरमैन महोदया, मैं मुख्य मन्त्री जी से यह जानना चाहूंगा कि टोटल कितना खर्चा हुआ है और किस-किस आईटम पर हुआ है, ये चीजें इनको बतानी चाहिएं । चेयरमैन साहिबा, मैं अब कीटनाशक दवाईयों के बारे में कहना चाहता हूं । पिछले सदन में भी करनाल का मामला आया था । सब-स्टैंडर्ड बीज दिया जाता है और कीटनाशक भी नकली हैं । करनाल में जो सीड का केस हुआ है उस कम्पनी के खिलाफ आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है । चेयरमैन महोदया, अब यह कोशिश की जा रही है कि 40-50 लाख रुपये मुआविजा दे कर फैसला करा दें । जिस आदमी से, जिस कम्पनी से सीड लिया गया, मेरी इत्तलाह के मुताबिक उसके पास सीड बेचने का लाईसैंस भी नहीं है । सरकार में बैठे हुए इन्फल्यूएंशियल आदमी कोशिश कर रहे हैं और यह चाहते हैं कि यह केस खत्म किया जाए मगर जिस किसान की पूरी फसल तबाह हो गई, उसका कोई ख्याल नहीं किया जा रहा है । फिर मैंने एक चिट्ठी देखी । दुकानदार ने लिखा है कि हमारा फैसला हुआ था कि हरियाणा सरकार उन किसानों को कम्पनसेशन देगी जिनकी दरख्वास्तें डी0 सी0 के पास आ गई हैं या जिनकी दरख्वास्तें कन्ज्यूमर फोरम में चली गई हैं । चेयरमैन महोदया, गरीब किसान कहां जानता है कि कन्जयूमर फोरम कहां है ? वह बेचारा तो कई बार डिप्टी कमिश्नर के पास भी नहीं पहुंच पाता । डिप्टी कमिश्नर करनाल का इसमें जिक्र आता है कि दरख्वास्तें उनके पास पहुंची हैं । वे पिहोवा, कैथल, कुरुक्षेत्र में गए । जब वे वहां जा सकते हैं तो आस-पास के इलाके में भी वे जा सकते हैं । सभी किसानों को पूरा मुआवजा दिलाया जाए । यह पूरा मुआवजा मेरे ख्याल से 2 से 4 करोड़ रुपये का बनेगा । चेयरमैन साहिबा, केवल मुआवजा देने से ही काम नहीं चलेगा । जिस कम्पनी के खिलाफ केस दर्ज हुआ है, उसमें दोषियों को सजा भी होनी चाहिए, इनको गिरफ्तार भी करना चाहिए और दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही भी

होनी चाहिए । केवल मुआवजा देने से काम नहीं चलेगा । कीटनाशक दवाईयां ऐसी हैं कि चाहे कोई कितना ही छिड़काव कर ले कोई कीड़ा उन दवाइयों से नहीं मरता । चेयरमैन साहिबा, कम से कम दवाईयां तो ऐसी लाएं जिनसे किसान को नुकसान न हो । (विघ्न) मैं यह आज की बात नहीं कह रहा हूं पिछले साल भी मैंने बताया था । मेहता हरी चन्द से पूछना उनको पता है । डिप्टी कमिश्नर और डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर आफिसर ने बताया कि फलां दवाई ले आईये । वह बड़ी मंहगी दवाई लाये । मेहता साहब ने मुझे बताया कि उस दवाई से कोई कीड़ा नहीं मरा। शायद वह अमरीकन सुण्डी थी या क्या था वह कपास में लग गई थी । उन्होंने बताया कि मैंने कीड़ों पर यह छिड़काव किया लेकिन कोई कीड़ा नहीं मरा तो मैंने अपने सीरी से कहा ये दवाई ले तो आए । उन्होंने दवाई को कटोरे में डालकर उसमें कीड़े डाल दिये, चेयरमैन साहिबा, वे कीड़े कटोरे में यूं ही फिरते रहे कोई कीड़ा नहीं मरा । मुझे यह सारी बात मेहता हरी चन्द जी ने बताई । आप चाहें तो उनसे पूछ सकते हैं । वे एक रिस्पोंसिबल आदमी हैं । चेयरमैन साहिबा, मेरे कहने का मतलब यह है कि कीटनाशक दवाई चाहे कोई भी हो, और चाहे कहीं पर भी हो, हर जगह सही किस्म की दवाई दी जानी चाहिए ताकि किसान को कोई नुकसान न हो ।

चेयरमैन महोदया, जहां तक टूरिज्म का सवाल है, मेरी इसमें पहले भी दिलचस्पी रही है और अब भी दिलचस्पी है । आप के जरिये मैं मुख्य मन्त्री जी से कहना चाहूंगा कि जितने टूरिस्ट कौम्प्लैक्सिज़ हैं उनका स्टैंडर्ड सब जगह गिरता जा रहा है । हरियाणा दिल्ली की प्रौक्सिमिटी का फायदा उठा सकता है ? आप किरायेदार से 10 रुपये ज्यादा ले लें लेकिन उसको फैसिलिटीज़ पूरी दें । 450 रुपये आप कमरे का किराया लेते हैं । आदमी चाहता है कि आराम से रहे, आराम से नहाए-धोये, वहां पर इन्सपैक्शन करके देखिये कि वहां पर फैसिलिटीज़ की हालत क्या है । वहां पर बड़ी खराब हालत है ।

चेयरमैन महोदया, इसके साथ ही मैं एक और बात कहना चाहता हूं कि फ्रीडम फाईटर का कोटा सरकारी नौकरियों में 2 प्रतिशत मुकर्रर है और उसमें भी यह किया हुआ है कि अगर कोई एक्स-सर्विसमैन नहीं आएगा तो ही फ्रीडम फाईटर के डिपैंडैंट को लिया जाएगा वरना नहीं लिया जाएगा । फ्रीडम फाइटर्ज के जो डिपैंडैंट्स हैं, वे भी बूढ़े हो चुके हैं और ये फ्रीडम फाईटर्ज भी थोड़े ही दिन रहेंगे । बहुत से फ्रीडम फाईटर्ज तो चले गए हैं । चेयरमैन साहिबा, इसलिए सरकार से मैं कहना चाहूंगा कि वह इस तरफ भी ध्यान दें । मैं समझता हूं कि फ्रीडम फाईटर्ज का कोटा अलग से होना चाहिए उसको ऐक्स सर्विसमैन के कोटे में नहीं होना चाहिए ।

इसी के साथ मैंने ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई के बारे में राज्यपाल महोदय, के अभिभाषण पर बोलते हुए भी बताया था । बहुत सी ऐसी जगहें हैं, जहां पर पीने के पानी का प्रबन्ध नहीं है । इस बारे में आपको ध्यान देना चाहिए ।

Vidhan Sabha Secretariat LIBRARY

[चौधरी बंसी लाल]

चेयरमैन महोदया, एक बात और है कि शराब की दुकानों के विरोध में एजिटेशन करने पर हमारे आदमियों और महिलाओं पर लाठीचार्ज किया गया। अश्रु गैस का इस्तेमाल किया गया। हिसार में तो बहुत सीनियर आदमी चौधरी जगन्न नाथ और चौधरी मनीराम जी को भी लाठी लगी और वे जख्मी हो गए। इसी के साथ कुरुक्षेत्र में औरतों के ऊपर भी लाठी चार्ज किया गया। यह कोई अच्छी बात नहीं है। मैं इसका विरोध करता हूं। चेयरमैन साहिबा, जब ऐसी बातें सरकार करेगी, तो काम कैसे चलेगा ?

चेयरमैन महोदया, यह जो सरकार ने पे-कमीशन बनाने का ऐलान किया है, मैं नहीं समझता कि यह क्यों बनाया जा रहा है ? जब हमने फोर्थ-पे-कमीशन एम्पलाईज को दे दिया तो उसमें हमने यह तय किया था कि जो भारत सरकार एम्पलाईज को तनखवाह देगी, वही हमारे एम्पलाईज को भी होगी। फोर्थ-पे-कमीशन में कुछ डिसक्रिमैंसीज रह गई थीं, तो हमने चीफ-सैक्रेटरी की चेयरमैनशिप में एक कमेटी बना दी थी और उन्हें कहा था कि एम्पलाईज की रिप्रेजैनटेशन लेकर के तीन महीने के अन्दर-अन्दर इसको ठीक कर दो। लेकिन आज तक वह हुआ नहीं है। अब तो इन्होंने पे-कमीशन बना दिया ताकि यह मामला और लम्बा हो जाए। अगर आपने यह बना ही दिया है तो आप तीन महीने के अन्दर-अन्दर उनसे टाईम बाउन्ड रिपोर्ट मंगवा लो और उसको इम्पलीमैंट कर दो।

चेयरमैन महोदया, कल मुझे अम्बाला में एक सनसनीखेज बात का पता लगा है। यह बात मुझे पत्रकारों ने बताई थी। मुख्य मंत्री जी खुद इसकी तफतीश कर लें। शायद वहां पर तो कोई न कोई सी0 आई0 डी0 वाला भी बैठा होगा और वह टेप करके लाया होगा। मुझे तो यह कहा गया कि जे0 बी0 टी0 के इन्टरव्यू हो रहे हैं। उनमें महिलाओं से जो सवाल पूछे जाते हैं, वे जॉब से ताल्लुक रखने वाले नहीं पूछे जाते हैं। किसी से तो पूछा जाता है कि सूट कहां से बनवाकर लाए हो। अगर कोई बेरोजगार हो तो कहा जाता है कि कहां से आए हो ? अगर तुम्हें नौकरी दी गई तो तुम अपने पति देव को छोड़कर देहात में रहोगी। इस प्रकार तरह-तरह के सवाल उनसे पूछे जाते हैं। एक पत्रकार ने तो यह भी बताया कि उन्होंने एक महिला से पूछा कि तुम ऐसे बाल क्यों रखती हो। मैं समझता हूं कि यह बात काबिले ऐतराज है। चेयरमैन महोदया, वहां पर जो इन्टरव्यू लिया गया, उसमें यमुना नगर के लड़के थे और जो इन्टरव्यू लेने वाला था वह भी यमुनानगर का था। अगर यमुनानगर के ही कन्डीडेट्स हों तो यमुनानगर के मैम्बर को इन्टरव्यू नहीं लेना चाहिए था। इन्टरव्यू चाहे अम्बाला में हो, चाहे यमुना नगर में हो पर वहीं का मैम्बर नहीं होना चाहिए। अगर कोई और जगह का मैम्बर हो, तो उसमें हमें कोई ऐतराज नहीं है। इसके साथ ही चेयरमैन महोदया, बहुत सी ऐसी चीजें हैं, जिसकी तरफ अगर सरकार तवज्जोह दे तो वे ठीक हो सकती हैं। एडमिनिस्ट्रेशन

का क्रिटीसिज्म बच सकता है । आज जहां पर भी जाएं, चारों तरफ एडमिनिस्ट्रेशन का क्रिटीसिज्म होता है । अभी 3-4 दिन पहले इसी सदन में श्री राजेन्द्र सिंह बिसला ने कह दिया कि शायद डी0 जी0 पी0 को कोई गाड़ी नहीं दी गई है । चौधरी बंसी लाल को बीसियों गाड़ियां दी गई हैं । मैं समझता हूं कि अगर राजेन्द्र सिंह बिसला जी की साढ़े तीन साल की तकरीर निकाल कर देखें तो इन्होंने सिवाय अफसरों की तारीफ के अलावा, कोई देहात के इलाके और शहरों के इलाकों की बात नहीं कही है । इनको यह नहीं पता कि मैंने तो किसी लड़के की और लड़की की शादी में इन्वीटेशन कार्ड भी नहीं छपवाए हैं । मैंने तो पांच आदमियों को भेजा और लड़की मंगवा ली और पांच आदमियों को बुलाया और लड़की भेज दी । यह सब तो चेयरमैन महोदया, आप भी जानती हैं और मुख्य मंत्री जी भी जानते हैं । इनको ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए । अगर कोई भी कन्टेसा लेकर आया हो तो वह कह दे तो चेयरमैन साहिबा, लोग इस तरह की बेबुनियाद बातें यहां पर करते हैं । ऐसी बातों के कहने पर रोक लगनी चाहिए । मैं मुख्य मन्त्री जी से कहूंगा कि वे इनको थोड़ा सा पढ़ा कर लाया करें, थोड़ी सी ट्रेनिंग देकर लाया करें । इनकी डिग्री तो भैरों सिंह शेखावत ने छीन ली । उसी ने इनको यह डिग्री दी थी और उसी ने यह छीन ली । इनका फैसला तो भैरों सिंह शेखावत ने कर दिया । इसलिए मैं मुख्यमंत्री से कहूंगा कि वे इनको थोड़ी ट्रेनिंग देकर लाया करें । चेयरमैन साहिबा, मैं चाहूंगा कि इन सारी बातों का जवाब मुख्य मंत्री जी स्वयं दें, तो ज्यादा अच्छा रहेगा । धन्यवाद ।

श्री धीरपाल सिंह (बादली) : चेयरमैन साहिबा, 13 तारीख को मांगे राम जी ने घाटे का बजट प्रस्तुत किया । इस बजट के अध्ययन करने के बाद ऐसा अहसास हुआ कि यह बजट दिशाहीन है, नीरस है और इसमें केवल अगले चुनाव की झलक देखने को मिलती है । विधान सभा और लोक सभा के बजट देखने के बाद ऐसा अहसास हुआ कि सरकार ने जिन चीजों पर यानी बिजली पर, पानी पर या दूसरी आईटम्ज पर जो टैक्स लगाना था, वह तो उसने पहले ही लगा दिया और इस बजट से इस तरह की धारणा लोगों में पहुंचाई है कि वह लोगों का भला कर रही है । (विघ्न) इसका फायदा नुक्सान तो आपको ही पता होगा । चेयरमैन साहिबा, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप हाउस के नेता से कहें कि वे थोड़ा संयम रखने की हिम्मत रखें । (विघ्न) अगर आप फायदे की बात कर रहे हैं, तो इस बारे में कई बार चैलेंजबाजी हुई है । आप इस्तीफा देकर आएं, तब आपको पता चल जाएगा कि कौन आएगा और कौन नहीं आएगा । (विघ्न) चेयरमैन साहिबा, गुप्ता जी ने लम्बी-चौड़ी बात की कि इनकी सरकार ने जून, 1991 के बाद से 484 किलोमीटर लम्बी सड़कों का निर्माण किया है और 7,538 किलोमीटर सड़कों पर परत चढ़ाई। इसके अलावा जो ये फरवरी, 1995 की बात कह रहे हैं तो मैं हाउस में दावे के साथ कहता हूं कि मेरे हल्के बादली में और खास तौर से विरोधी पक्ष के जो भी साथी हैं उन के हल्कों में किसी भी सड़क पर कार्य नहीं हुआ । अगर आप

[श्री धीरपाल सिंह]

चाहें तो हाउस की इस बारे में एक कमेटी बना ली जाए । कमेटी का बनाना तो एक अच्छी परम्परा है और उस कमेटी के द्वारा यह इंक्वायरी हो कि विरोधी पक्ष के जो लोग आरोप लगाते हैं, क्या वह आरोप निराधार हैं या उनमें कुछ सच्चाई है ? ट्रैजरी बैंचिज के जो हमारे साथी हैं या हाउस के नेता हैं तो उन्होंने अपने तीन साल या पौने-चार साल के राज्य में, केवल पीछे का रोना रोने के सिवाए और कोई भी कार्य नहीं किया । अगर ये पीछे का ही रोना रोते रहे तो क्या यह आगे प्रदेश के साथ नाइन्साफी नहीं होगी ? मैं यह बात ओन ओथ कहता हूं कि झज्जर बादली दिल्ली रोड पर तीन-तीन फुट गड्ढे हैं और वहां पर पानी भरा हुआ है । कोई भी साधन वहां से निकलने में असमर्थ हैं । चेयरमैन साहिबा, इनके मंत्री साहब ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में 28 तारीख इंगित की है कि इस तारीख तक वहां काम हो गया है । इसलिए मैं मंत्री जी की जानकारी के लिए कह रहा हूं कि जो उनके पास जवाब आया है तो वे उसको जरा चैक कर लिया करें । इन्होंने जो 484 किलोमीटर सड़कों के निर्माण की बात की है, मैं ओन ओथ कह रहा हूं कि मेरे हल्के में केवल आधा किलोमीटर तक तो सड़क ठीक हुई है, वह भी इसलिए कि वहां के एक गांव में डांगी साहब का कोई रिश्तेदार है, उसके अलावा बाकी तीन या पौने-चार साल के राज में मेरे हल्के बादली में अगर एक इंच भी किसी सड़क का निर्माण किया गया हो, तो मैं यह असत्य बोलने पर हाउस का गुनाहगार हूं । चेयरमैन साहिबा, जैसे इन्होंने रिपेयर की बात कर दी । सड़कों का बहुत बुरा हाल है । ये सोचते हैं कि विरोधी पक्ष के सदस्य बजट सैशन या दूसरे सैशन में अपनी भड़ास निकालकर चले जाते हैं । विरोधी पक्ष के सदस्यों द्वारा कही हुई बातों पर इंक्वायरी कराने का कष्ट सरकार की तरफ से नहीं उठाया जाता । चेयरमैन साहिबा, झज्जर के बारे में आप भली भांति परिचित हैं और आपसे लोगों का सम्पर्क भी है । लोग आपकी आशा भरी निगाहों से देखते हैं । झज्जर के चारों तरफ के रास्ते बन्द हो गए हैं । आजादी के 46 साल के बाद भी उस नगर का यह हाल हो कि वह चारों तरफ से सील कर दिया गया हो, कोई एन्ट्रैंस न हो, (विघ्न) यह कितनी अनुचित बात है ?

लोक निर्माण मन्त्री (चौधरी अमर सिंह) : चेयरमैन साहिबा, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है । आनरेबल मैम्बर झज्जर के बारे में बता रहे हैं लेकिन यह नहीं बता रहे हैं कि जुलाई 1994 में झज्जर में कितना जबरदस्त फ्लड आया था और वहां पर सारी रोड बह गई थी । (विघ्न)

सभापति महोदया : झज्जर का तो हमेशा ही बुरा हाल रहता है ।

श्री धीर पाल सिंह : सभापति महोदया, मैं ओन-ओथ कह रहा हूं । प्वायंट आफ आर्डर पर मंत्री जी ने रिप्लाई देने की कोशिश की है कि वहां बाढ़ आ गई

थी उसकी वजह से सड़क खराब हो गई थी । (शोर एवं व्यवधान) अगर बाढ़ की वजह से सड़कें खराब हुई हों तो मैं हाउस में ईमानदारी से इनकी बात मानने के लिये तैयार हूं । (शोर एवं व्यवधान) चेयरमैन साहिबा, शहर के पानी की निकासी न होने की वजह से झज्जर की सड़कें खराब हो गई हैं । इसी तरह छारा का बुरा हाल है । जो भी आदमी बेरी से बहादुरगढ़ जाता है, उसका रोड पर से निकलना मुश्किल हो जाता है । (शोर एवं व्यवधान) जब हमारी सरकार थी, तब याकूपुर से सौंधी तक के लिए सड़क को ऊंचा उठाने के लिए हमने पैसा अलाट कराया था । उस पर इस सरकार ने काम तो किया लेकिन काफी बेकायदगी से किया जिसकी वजह से दुबारा उठी हुई सड़क समाप्त हो गई है । कोई भी व्हीकल वहां से आ जा नहीं सकता । मैंने बार-बार एस0 ई0 से कहा कि वहां यातायात के साधन आ-जा नहीं पा रहे हैं । बहिन-बेटियों को 3 कि0 मी0 से ज्यादा पैदल चलना पड़ता है । उन्होंने कहा कि इंक्वायरी हो रही है । इंक्वायरी से पहले हम पैसा अलाट नहीं कर सकते । कब इंक्वायरी होगी ? दुबारा कब मुरम्मत होगी ? सड़कों का बुरा हाल कर रखा है (शोर एवं व्यवधान) बूपनियां गांव की सड़क पर अढ़ाई से तीन फुट के गड्ढे हुए पड़े हैं । डाबोधा, खरमान, रिवाड़ी खेड़ा, बधानी, मूंडाखेड़ा, पेलपा, कबलाना से जो सड़क याकूपुर जाती है वह दोनों तरफ से कटी हुई है । वहां कीकर लगे हुए हैं । पूरा गांव एप्रोच रोड पर है बहुत मुश्किल हो जाती है या तो कीकर हटवाए जाएं या किनारों को ठीक करवा दिया जाए अन्यथा वहां से व्हीकल पास होने का रास्ता भी नहीं रह जाता है ।

सभापति महोदया, अब मैं एस0 वाई0 एल0 पर भी कुछ कहना चाहूंगा । यह सरकार दावे करके आई थी कि हमारी सरकार बनने के कुछ ही समय बाद एस0 वाई0 एल0 का निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा । सभापति महोदया, यह एस0 वाई0 एल0 आप को पता है कि हमारी जीवन रेखा है और पानी न आने की वजह से हमारे जिले रोहतक, सोनीपत, भिवानी महेन्द्रगढ़ रिवाड़ी नारनौल के इलाकों में पानी हर साल नीचे ही नीचे जा रहा है जिसकी वजह से गम्भीर संकट आज पैदा हो गया है । सरकार यह कह रही है कि आज किसान को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है और फिर हम जब यहां पर अपने इलाकों की मुश्किलों को सरकार के सामने रखते हैं, लोगों की मुश्किलों को, किसानों की दिक्कतों को यहां हाउस में रखते हैं तो इस सरकार के अन्दर उन बातों को सुनने की हिम्मत नहीं है । सरकार हमारी बातों का सामना नहीं कर सकती । अगर इस सरकार के अन्दर कोई गैरत हो तो सरकार हमारी बातों का सही जवाब दे । हमारी बातों का सामना करें लेकिन इस सरकार में गैरत नाम की तो कोई चीज ही नहीं है । साढ़े तीन साल के अन्दर उस एस0 वाई0 एल0 के निर्माण के ऊपर इस सरकार द्वारा एक ईंट भी नहीं लगाई गई है । फिर ये सरकार यहां पर इस की चर्चा करने से भागती है । कितनी शर्म की बात है इस सरकार के लिये ?

[श्री धीरपाल सिंह]

इसके बाद इन्होंने यहां हाउस में यमुना समझौते की भी चर्चा की कि यह मामला 20 सालों से पेंडिंग था । हमने बड़ा काम कर दिया है । सभापति महोदया, इस सरकार ने जो काम किया है, वह सब के सामने है । इस सरकार ने समझौता क्या किया, हमारा पानी बेच दिया । प्रान्त को बरबाद कर दिया । हमारे खेतों को खत्म कर दिया । लोग पानी को तरसेंगे । लोगों को बिल्कुल उजाड़ कर रख दिया है । मैंने इस बारे एक स्टार्ड क्वैश्चन व एक अन-स्टार्ड क्वैश्चन भी दिया था कि जो दुल्हेड़ा डिस्ट्रीब्यूटरी के बारे है । उसकी कैपेसिटी 160 क्यूसिक फुट पानी की है उसमें 3/4 गाद आ गया और यह बात आन रिकार्ड है कि इस कारण से अब उसमें केवल 40 क्यूसिक फुट पानी छोड़ा जाता है और आप ही सोचिये, सभापति महोदया, कि ये इतने पानी से कितने इलाके की सिंचाई कर पाएंगे और कितना पानी लोगों को पीने के लिये दे पाएंगे ? यह हमारी समझ में तो आता नहीं है । आश्वासन तो ये सरकार हमेशा दे देती है कि हम यह कर देंगे, हम वह कर देंगे लेकिन वास्तव में यह सरकार अपना वायदा कभी भी पूरा नहीं कर सकी । इसी तरह से इसमाईला, मूलताना व छारा माईनर्ज जो हैं, ये सारी की सारी गाद से भरी पड़ी हैं । टेल तक पानी नहीं जा रहा है । साढ़े तीन साल के अन्दर किसी भी टेल तक पानी यह सरकार नहीं पहुंचा सकी है । आप बेशक पिछला रिकार्ड उठाकर देख लें । इसके साथ साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि मैंने एक बार यहां पर कहा था कि हमारे जौहड़ों में पानी नहीं है तो मुख्य मन्त्री महोदय ने इस हाउस में यह आश्वासन दिया था कि 31 मार्च, 1994 तक सभी जौहड़ों में पानी डाल दिया जाएगा, लेकिन मैं आज दावे के साथ कह रहा हूं कि बादली हल्के में आज तक किसी भी माईनर, किसी भी जौहड़ में पानी नहीं जा पाया है । यह जून 1991 से लेकर मार्च, 1995 तक की स्थिति है । बादली हल्के में जितनी भी माईनर्ज हैं, वहां कहीं भी पानी नहीं जा रहा है, सिवाय गाद के वहां कुछ भी नहीं है । फिर ये यहां पर इसके इलावा यह भी कहते हैं कि हमने तो मानवता के आधार पर राजस्थान को पानी दिया है । वहां की सरकार के मुख्य मन्त्री श्री भैरों सिंह शेखावत ने यह कहा था कि चौधरी भजन लाल जी, यह आपका ऐहसान हम नहीं मानते यह हमारा मालिकाना अधिकार है । यह हमारी अपनी इच्छा है कि हम इसका प्रयोग खेती के लिये करें या पीने के लिये करें । मेरा कहने का मतलब यह है सभापति महोदया, कि यह हमारे मुख्य मन्त्री महोदय की आदत सी हो गई है कि कहना कुछ और करना कुछ और । जहां प्रदेश का अहित हो, उसके लिये जवाब देने की कारीगरी इन में विराजमान है । झूठी बात को सच्चा करने की इनकी आदत है । यमुना समझौता करके इन्होंने हरियाणा की जनता के साथ खिलवाड़ किया है । हरियाणा के हितों को बेचा है, जिससे हरियाणा की जनता, हरियाणा का किसान बेहद परेशान है । इस सरकार द्वारा सदा ही असत्य बात हाउस में कही जाती रही है । यहां हर बात पर ये हाउस को आश्वासन दे देते हैं और चले जाते हैं ।

6 महीने के बाद सैशन होता है । इनको पता है कि क्या कार्यवाही होगी ? ये अच्छी प्रकार से जानते हैं कि एक बार जो सरकार ने आश्वासन दे दिया, उसके बारे में विरोधी दल क्या कहेंगे क्योंकि 6 महीने के लिये सैशन उठ जाता है । बात आई गई हो जाती है । किसी को अपनी बात कहने का मौका ही नहीं मिलता । असत्य को सत्य बनाने की इनके पास कला है । इस बात को सभी जानते हैं । यहां पर बिजली के बारे में चर्चा हुई । मैं इस बारे में चौधरी वीरेन्द्र सिंह पर कोई आरोप नहीं लगाना चाहता क्योंकि ये गड्ढे तो इनके आने से पहले के खुदे हुए हैं । जब हमारी सरकार थी, तो उस समय 24 घंटे बिजली मिलती थी । उस समय चौधरी वीरेन्द्र सिंह जी स्वयं बिजली मन्त्री थे । लोग हमारे समय को याद करते हैं कि कितनी सस्ती बिजली उस समय मिलती थी । चेयरमैन महोदया, आज बिजली की यह हालत है कि सुबह से शाम तक गांवों में मुतवातर बिजली नहीं मिल रही । मैं तो भगवान का आभारी हूं कि उसने समय पर बारिश कर दी और इस वजह से बिजली की डिमांड कम हो गई और लोग बच गए । आज विद्यार्थियों को भी रात दस बजे के बाद बिजली मिलती है । मैं एक बात चौधरी वीरेन्द्र सिंह जी के नोटिस में लाना चाहूंगा कि आज एक ट्रैंड हो गया है कि मीटर रीडर घर बैठे-बैठे बिजली का बिल बनाकर भेज देते हैं । कई बार ऐसा होता है कि कम्प्यूटर लाखों रुपए का बिल दे देता है । गांव माजरी में बादली सब-डिवीजन का आफिस है । उसके तहत 30 बिल जारी हुए और तीसों पर लिखा गया कि ताला बन्द है । जो तीस कंज्यूमर थे, उन्होंने एस0डी0ओ0 को आ कर कहा कि हमारे तो घर में बच्चे रहते है, वहां पर कोई ताला नहीं लगा हुआ है । फिर जो बिल दिए गए, वे भी फ्लैट रेट पर दिए गए । तो अगर इस तरह की परेशानी लोगों को होगी, चाहे वह शहर में हो या देहात में हो, तो उससे लोगों में नाराजगी बढ़ेगी । ऐसा करके आपको कोई ईनाम मिलने वाला नहीं है । एक बात मैं खेड़ी जट गांव की बताना चाहता हूं कि वहां का ट्रांसफार्मर जल गया था । उसको एक महीने के बाद रिप्लेस किया गया । आप हाउस में तो आश्वासन देते हो कि सात दिन के अन्दर ट्रांसफार्मर रिप्लेस हो जाएगा । इसको अमली जामा पहनाने के लिए आपको अपनी शक्तियों का प्रयोग करना पड़ेगा ।

चेयरमैन महोदया, यहां पर पब्लिक हैल्थ के बारे में भी चर्चा हुई । कहा गया कि गांवों में पानी बढ़ा कर 70 लिटर किया जाएगा । मैं जानना चाहता हूं कि सरकार यह फिगर कहां से ले कर आती है ? मेरा एक काल अटैन्शन मोशन था कि मुंडा-खेड़ा गांव में पिछले कई दिनों से पानी नहीं जा रहा । चेयरमैन महोदया, वहां पर पहले साहबी नदी का पानी आता था और उससे झज्जर तहसील में अषाढ़ी की खेती होती थी । लेकिन पिछले दिनों राजस्थान ने उस पानी को अपने यहां बांध बनाकर रोक लिया । इसी बात को ले कर यहां पर शोर मचाया गया कि मसानी बांध क्यों बनाया गया । मैं बताना चाहता हूं कि 1978 में भयंकर बाढ़

[श्री धीर पाल सिंह]

आई और भयंकर बाढ़ के बाद दिल्ली बार्डर पर सैंटर ने आर्मी भेज दी। उस समय यहां पर हमारी सरकार थी। वहां पर हमारे कई गांव पानी से डूब रहे थे। उस समय चौधरी साहब आपने समझौता कराया कि उस पानी को वहां से निकाला जाए। उस समय सरकार ने निर्णय लिया कि मसानी डैम बना कर पानी को रोका जाए और वह पानी रिवाड़ी और आगे के इलाकों को सिंचाई के लिए दिया जाए। वहां पर लाखों क्यूसिक्स पानी बरबाद हो जाता है। आज वहां पर पानी नहीं आ रहा है पानी सूख गया है। पानी सूखने की वजह से वहां पर लोगों ने डीप ट्यूबवैल्ज लगाए थे लेकिन वहां पर पानी रीचार्ज न होने की वजह से सारे के सारे ट्यूबवैल्ज का पानी खारा हो गया है। बाढ़सा, मुण्डाखेड़ा, खंगाई, बादली झांगीपुर रेवाड़ी खेड़ा में यही हालत है। मेरे कहने का मतलब यह है कि झज्जर सब-डिवीजन के सभी गांवों के ट्यूबवैल्ज का खारा पानी हो गया है। उनको रीचार्ज न होने की वजह से पानी नहीं मिलता है। पूरा झज्जर सब-डिवीजन का नीचे का पानी खारा हो गया है। मैं हाउस में एक बात यह कहना चाहता हूं कि जो कैनाल बेस्ड वाटर सप्लाई स्कीम्ज हैं, उनके अन्दर कितने दिन से पानी नहीं है। वहां पर झज्जर सब-डिवीजन में जितनी भी कैनाल बेस्ड वाटर सप्लाई स्कीम्ज हैं, उनके अन्दर पानी नहीं जाता है और लोग एक-एक बूंद पानी के लिए तरसते हैं। जैसे खंगाई, रेवाड़ी खेड़ा, बादली झांगीपुर गांवों की जितनी भी कैनाल बेस्ड वाटर सप्लाई स्कीम्ज हैं उनके अन्दर पिछले काफी दिनों से पानी मुहैया नहीं हो रहा है। उन सभी वाटर वर्क्स में बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। मुझे ऐसा महसूस होता है कि पीने के पानी के बारे में यह सरकार गम्भीर नहीं है। यह सरकार सदन में बड़े-बड़े बुलंद दावे करती है कि लोगों को पीने का पानी मुहैया कराया जा रहा है लेकिन इस काम के लिए राशि कहां से आती है और कहां पर जाती है, इस बारे में हम तो अभी तक जान नहीं पाए हैं। पिछले तीन-चार साल से यहां पर बजट पेश किया जा रहा है। हम उस किताब को पढ़ते हैं। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण को पढ़ते हैं। गुप्ता जी, हमने आपके बजट को देखा! अच्छा लगा। लेकिन इसके अन्दर हमें कुछ नहीं मिला। हमें पूरी आशा थी कि गुप्ता जी बहुत अच्छा बजट पेश करेंगे और उसमें विकास की गति की बात होगी लेकिन इस बजट में हमें कहीं पर भी विकास की गति की झलक दिखाई नहीं दी। चेयरमैन महोदया, अगर ये कहीं पर विकास करते होंगे तो अपने साथियों के हल्कों में करते होंगे। इन्होंने जो आंकड़े प्रस्तुत किए हैं, वे काल्पनिक हैं और ये लोगों को गुमराह करने वाले आंकड़े दर्शाए गए हैं। चेयरमैन साहिबा, इस बजट स्पीच के पेज 36 पर महालेखाकार, हरियाणा के लेखों के अनुसार 31 मार्च, 1994 को राज्य पर ऋण भार 4,373.01 करोड़ रुपए था। प्रस्तुत संशोधित अनुमानों के अनुसार राज्य की ऋण देयता में 642.35 करोड़ रुपए की वृद्धि होगी। अतः 31 मार्च, 1995 को राज्य की कुल ऋण देयता 5015.36 करोड़ रुपये होने की संभावना है जो 31 मार्च,

1994 के ऋण भार से 14.7 प्रतिशत अधिक होगी। यह भार 1995-96 के बजट अनुमानों के अनुसार 31 मार्च, 1996 तक 16 प्रतिशत बढ़ कर 5816.84 करोड़ रुपए होने की संभावना है। चेयरमैन साहिबा, पिछले तीन साल में इस सरकार ने हर साल सैंकड़ों रुपए ऋण के रूप में लिए हैं। वह पैसा कहां पर प्रयोग होता है ? कहीं पर भी नहरों की डी-सिल्टिंग नहीं करवाई गई है। दूसरे काम भी नहीं हुए हैं। जहां तक हथिनी कुण्ड बैराज की बात है, वह तो ताजेवाला हैड वर्क्स की रिप्लेसमैंट है इससे ज्यादा कोई बात नहीं है। यह एक तरह से स्टेट पर बोझ लादा जा रहा है। सदन में एम0आई0टी0सी0 द्वारा खाल पक्के करवाने की बात आई। यह ठीक बात है कि जहां पर खाल पक्के करने की आवश्यकता है, वह पक्के होने चाहिएं लेकिन जहां पर पानी ही नहीं है, वहां पर खाल पक्के करने का क्या फायदा है ? इस प्रदेश की सम्पत्ति के साथ खिलवाड़/दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए। इस तरह से पैसे को बेरहमी के साथ नहीं फूंकना चाहिए। मैं यह चेलैंज के साथ कहता हूं कि एम0आई0टी0सी0 ऐसी जगहों पर खाल पक्के कर रही है, जहां पर पानी ही नहीं है। जहां पर पानी नहीं है, वहां पर खाल पक्के किए हैं। उनका क्या लौजिक है ? क्या उसकी उपयोगिता है ? यह बात मेरी समझ से बाहर की बात है। जो पैसा वर्ल्ड बैंक से लिया गया है, यह ऋण के रूप में लिया गया है और यह सारा पैसा ब्याज सहित वापस करना है। इसका कौन जिम्मेदार होगा ? यह सरकार होगी या आने वाली कोई सरकार होगी। इस कर्ज को तो हरियाणा की जनता ने ही वहन करना है (विघ्न) मेरा कहना यह है कि जहां पर जरुरत हो, वहां पर पैसे खर्च करके पक्के खाल बनाए जाने चाहिएं। कई जगहों पर पक्के खाल के नाम से पैसा खर्च कर दिया गया। वहां पर न तो पानी पहुंचा है और न ही कभी पहुंच पायेगा। बादली हल्के में ऐसा कई जगहों पर हुआ है।

सिंचाई मन्त्री (चौधरी जगदीश नेहरा) : आन ए प्वायंट आफ आर्डर सर। चेयरमैन महोदया, मैं आपके माध्यम से धीरप ल जी से पूछना चाहता हूं कि क्या नहरें पक्की करने से या खाले पक्की करने से सीपेज कम नहीं हुई और पानी की बचत नहीं हुई। इससे सैंकड़ों क्यूसिक्स पानी की बचत हुई है और इरीगेशन बढ़ी है। एक-दो खालें ऐसी हो सकती हैं, जैसा ये कह रहे हैं कि वहां पर पानी नहीं जा रहा। ऐसा शेयर होल्डरों की गलती की वजह से हुआ होगा। इस्तेमाल में जो जगह छोड़ी गई थी, वहां पर ये खालें बनायी गई हैं। इसलिए, चेयरमैन महोदया, इनको चाहिए कि ये हर बात को गलत न कहें और न ही हाउस को मिसलीड करने की कोशिश करें। जहां पर भी खाल पक्के किए गए हैं वहां कमांड एरिया है। (विघ्न)

श्री धीर पाल सिंह : मैं ओन ओथ अब भी कह रहा हूं कि कई जगह ऐसी हैं जहां पर खाल पक्के कर दिए गए हैं लेकिन न पानी वहां पर कभी पहुंचा है और न ही पहुंचेगा।

चौधरी जगदीश नेहरा : धीरपाल जी, आप हाउस को मिसलीड कर रहे हैं। हम जहां पर भी खाल बनाते हैं, वहां पर इस्तेमाल में जगह छोड़ी हुई होती है। बाकायदा कमांड एरिया होता है। कुछ जगह ऐसी हो सकती हैं, जहां पर गलत खालें पक्की हुई हों। मगर सारी जगह ऐसे हो, ऐसी बात नहीं है। (विघ्न)

सभापति महोदया : आप जल्दी खत्म करें।

श्री धीरपाल सिंह : सभापति महोदया, मेरे बोलते हुए बार-बार इन्ट्रप्ट किया गया है। हाउस के नेता ने पिछले बजट सैशन में कहा था कि हम बेकार नौजवानों को काम देने जा रहे हैं। कितनों को रोजगार दे रहे हैं, यह आंकड़े याद रखना और तारीखें याद रखना आपका काम है। इस बारे में मैं बताना चाहूंगा कि सरकार की परिवहन नीति के मुताबिक लोगों ने अपना घर का सामान बेच कर कर्जा लेकर या किसी दूसरे तरीके से 7-8 लाख रुपये इकट्ठे करके अपनी गाड़ियां बनाईं। वे सभी घाटे में जा रही थीं, तो वे मुख्य मन्त्री जी से मिले। हाउस के नेता ने जो प्रदेश के मुख्य मन्त्री हैं, वे उनके साथ हमदर्दी से पेश नहीं आए। उन्हें कम से कम उनके जले हुए घावों पर मरहम पट्टी लगानी चाहिए थी लेकिन उन के घावों पर मरहम पट्टी करने की बजाये उनको कहा गया कि क्या ये गाड़ियां आपने मेरे से पूछ कर खरीदी थीं? ये लोग कर्जा लेकर बरबाद हो गए। मेरे कहने का मतलब यह है कि हाउस के नेता को उनके साथ हमदर्दी के साथ पेश आना चाहिए था और उनकी शिकायत पर दुबारा से जांच होनी चाहिए थी। उनके घावों पर मरहम पट्टी लगानी चाहिए थी। लेकिन मुख्य मन्त्री ने उनको जो जवाब दिया वह शोभनीय नहीं था।

मुख्य मन्त्री (चौधरी भजन लाल) : मैंने क्या जवाब दिया ? क्या वहां आप मौके पर थे ?

श्री धीरपाल सिंह : मुख्य मन्त्री प्रदेश का मुख्य मन्त्री होता है और यह बात मुख्य मन्त्री के लिए अशोभनीय बात है।

चौधरी भजन लाल : क्या आप खुद उनके साथ गए थे ?

श्री धीरपाल सिंह : मैं खुद तो साथ नहीं गया था लेकिन और जो भाई गए थे उन्होंने आ कर तो बताया है। क्या यह कम है ?

चेयरमैन साहिबा, रोड्ज बेहद खराब हैं, सड़कों की मुरम्मत नहीं होती। एक और जिम्मेदारी उन पर डाल दी और टैक्स बहुत ज्यादा लगाया, जिसका नतीजा यह हुआ है कि वे बसें घाटे में चल रही हैं। वे बेचारे घाटे से परेशान हैं। जो पैसा उनके पास था, वह तो उन्होंने साधन जुटाने में लगा दिया जिसकी वजह से आज वे न घर के रहे न घाट के। चेयरमैन साहिबा, इसके साथ ही मैं मुख्य मन्त्री

जी का ध्यान एक और बात की तरफ दिलाना चाहूंगा । 13 तारीख को बस का एक हादसा हो गया था । यह बस रोहतक से लखनऊ जाती है । जो लखनऊ से वापिस गाड़ी आ रही थी उस बस में सीतापुर के पास दो-तीन लोग बस के पीछे से बस में चढ़े । एक डाकू ने ड्राईवर की गर्दन पर रिवाल्वर रख दिया । ड्राईवर के साथ ही कण्डक्टर भी बैठा हुआ था । कण्डक्टर ने अपनी पद की गरिमा और लोगों की जान बचाने के लिए उस डाकू की कौली भर ली उसको यह ध्यान नहीं था कि वह बस में अकेला डाकू नहीं था बल्कि उसके और साथी पीछे भी खड़े थे उस डाकू के साथी ने उस कण्डक्टर को गोली मार दी और वह मर गया । उस घटना में ड्राईवर भी घायल हुआ । चेयरमैन साहिबा, उसको कम्पनसेशन नहीं दिया गया जिस की वजह से रोहतक डिपो में कोई कर्मचारी काम पर नहीं गया । उस कण्डक्टर ने इतनी बहादुरी से उस डाकू को पकड़ा कि उसने अपनी जान की भी परवाह नहीं की । उस हादसे में ड्राईवर भी घायल हुआ । जिस कण्डक्टर ने डाकू से लड़ाई की, उसका मुकाबला किया उस को यूनियन की डिमाण्ड के हिसाब से उनके परिवार को कम्पनसेशन मिलना चाहिए और उसके परिवार के किसी एक सदस्य को नौकरी देनी चाहिए । चेयरमैन साहिबा, रोहतक में कोई बस रात को नहीं निकलती है और वहां से रात के रूट्स बन्द हो गए हैं । रात के रूट्स सारे के सारे बन्द हो गए हैं । इसलिए मैं आपके माध्यम से मुख्य मन्त्री जी से सिफारिश करूंगा कि जो गाड़ियां रात को जाती हैं, उन गाड़ियों के साथ ऐसा कोई हादसा होने पर उचित मुआविजा मिलना चाहिए । कण्डक्टर के परिवार को 1 लाख रुपये की जो राशि दी गई है, वह कम है । (विघ्न) मृतक कण्डक्टर की शादी केवल 3 महीने पहले हुई थी । वह नौजवान लड़का था । उसकी पत्नी समय से पहले विधवा हो गई और इतना लम्बा जीवन उसके सामने है । मैं पूरी बात कहना चाहता हूं । 2–2 लाख रुपये की राशि ऐसे ही कई मरने वाले लोगों को दी जाती रही है, अगर मैं उस बात का जिक्र करूंगा तो मुख्य मन्त्री जी को पीड़ा होगी मैं सिफारिश करूंगा कि इस कण्डक्टर की बेवा को कम से कम 5 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाए । उस नौजवान ने प्रदेश के हित के लिए और अपनी परिवहन की साख को बनाने के लिए अपनी कुर्बानी दी है । उस भाई के लिए 1 लाख रुपये का मुआविजा बहुत ही कम है । मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि इस पर सरकार पुनर्विचार करने की कोशिश करे । (विघ्न)

चौधरी भजन लाल : चेयरमैन साहिबा, जिस प्रदेश में इस प्रकार का कोई वाक्या हो जाता है, तो मरने वाले के परिवार को मुआवजा वह स्टेट गवर्नमैंट देती है । हमने हमदर्दी के तौर पर और यह बात मानते हुए कि हरियाणा का एक नौजवान इसमें मारा गया है, उसके परिवार को एक लाख रुपया तथा उसकी बीवी या अगर उसका भाई नौकरी करना चाहे तो उसको सरकारी नौकरी पर लगाने का फैसला किया है ।

श्री धीर पाल सिंह : चेयरमैन महोदया, मैं मुख्य मन्त्री जी को याद दिलाना चाहूंगा कि बलम्भा गांव में एक छज्जा गिरा था उसमें मरने वाले के परिवार को 50–50 हजार रुपये की राशि दी गई थी। यह हादसा भी मेहम के खरकड़ा गांव के नौजवान के साथ हुआ है। उसकी तुलना में तो कहीं ज्यादा सराहनीय काम इस नौजवान ने बहादुरी के साथ डाकू का मुकाबला करने का किया। चेयरमैन साहिबा, इसके साथ ही मैं मुख्य मन्त्री जी से यह आश्वासन भी चाहूंगा कि सरकार उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य मन्त्री से मिल कर इस बारे में बात करें और जिन लोगों ने डाका डाला है, उनको गिरफ्तार करने के लिए उन्हें कहें।

सभापति महोदया : धीरपाल सिंह जी, आप प्लीज वाइंड-अप कीजिए। आपको 34 मिनट से ज्यादा समय मिल गया है। आप अब जल्दी वाइंड-अप करिये।

श्री धीर पाल सिंह : चेयरमैन साहिबा, बजट सैशन में गवर्नर साहब के ऐड्रेस पर ट्रेजरी बैंचिज के साथियों ने बहुत लम्बी-चौड़ी बातें कही थी कि इस बार फसल बहुत अच्छी हुई है। इनकी मेहरबानी से जहां पर बिजली, पानी और खाद नहीं मिली, वहां पर भी फसल बहुत अच्छी हुई। चेयरमैन साहिबा, सप्लीमैंटरी एस्टीमेट में दिया हुआ है कि शूगर केन में 1991–92 में उत्पादन 950 लाख टन था और इस सरकार की मेहरबानी से वह पैदावार घटकर 650 लाख टन रह गई है। गुड़ की पैदावार 1991–92 में 905 लाख टन थी और आज वह घटकर 672 लाख टन रह गई है और उससे अगले साल यह घटकर 642 लाख टन ही रह गई है। 1992–93 में व्हीट-पर-एकड़-ईल्ड 3,621 किलोग्राम से घटकर 3,619 किलोग्राम ही रह गई है। इन्होंने अपने हल्के में बहुत सी घोषणाएं की हैं लेकिन जो फिगर हैं वह बिल्कुल उल्ट हैं। पेज नं0 17 पर दिया है कि हास्पिटलज 78 से 59 ही रह गए हैं, डिसपैन्सीरिज 2325 थीं और 2325 ही हैं।

श्री राजेन्द्र सिंह बिसला : चेयरमैन साहिबा, मैं पर्सनल एक्सप्लेनेशन पर बोलना चाहता हूं।

सभापति महोदया : धीरपाल जी, आप का टाईम हो गया है।

श्री धीरपाल सिंह : मैं थोड़ी देर और बोलूंगा। चेयरमैन साहिबा, मैं इस सरकार के बारे में कह रहा हूं कि कितनी इनकी अचीवमैंट है। चेयरमैन साहिबा, 20 प्वायंट प्रोग्राम के तहत इस सरकार ने 33 लाख 34 हजार लोगों को रोजगार देना था और 15 लाख 35 हजार लोगों को ही ये रोजगार दे पाए हैं, यह टोटल 50 प्रतिशत से भी कम है। यह तो इनकी अचीवमैंट है। बच्चों को टीके 5 लाख 38 हजार लगाने थे और 3 लाख 45 हजार टीके ही ये गांवों कस्बों और शहरों में लगा पाए हैं। आगे इन्होंने जो काम किया है कि हरिजनों को न्याय दिलाएंगे, उनके लिए वकील की होंगे। इनका टारगेट 68 हजार का था और ये

सुविधा केवल 20 हजार 173 लोगों को ही दे सके। हाऊस साईट के प्लाट 20 हजार को देने थे और ये सिर्फ 16 हजार 381 को ही दे पाए। इन्दिरा आवास योजना के तहत एस0सीज को 1760 मकान देने थे और ये 868 मकान ही दे पाए। ई0डब्ल्यू0एस0 के अन्दर 600 लोगों को मकान देने थे और ये 20 मकान ही दे पाए। एल0आई0जी0 के बारे में 15 सौ का टारगेट था और ये सिर्फ 45 मकान ही बनाकर दे पाए हैं। (घन्टी) मैं आपके कारनामों को ही पढ़ रहा हूं। आपने सिर्फ आंकड़े ही दर्शाए हैं। जो टारगेट फिक्स किए हुए हैं, तो उनको अचीव करने की बात तो दूर रही, उनके नजदीक भी यानी एक चौथाई कार्य भी पूरा नहीं कर पाए हैं। इन्होंने आंकड़ों में सिर्फ यही कहा है कि तीन महीनों में हम सारे आंकड़ों को पूरा कर लेंगे तो चेयरमैन साहिबा, ये इस तरह के आश्वासन देते हैं। इसके अलावा जो सड़कें इनके द्वारा खायी गयी हैं, उसके बारे में भी मैं बताना चाहता हूं। 1992-93 में टोटल सड़कों के यानी 23,168 किलोमीटर के बारे में इन्होंने कहा है। इस 23,168 किलोमीटर में से नैशनल हाईवे भी इंक्ल्यूडिड हैं। इस 23,168 किलोमीटर के टारगेट में से इन्होंने 1993-94 में 22947 किलोमीटर सड़कों की मुरम्मत का टारगेट ही अचीव किया है यानी 221 किलोमीटर सड़कों को स्वाहा कर दिया। (विघ्न) मैंने नैशनल हाईवे को जोड़कर ही कहा है। यह 221 किलोमीटर कहां गयीं आप इसकी भी तो जानकारी दे दो।

वैयक्तिक स्पष्टीकरण—

श्री राजेन्द्र सिंह बिसला द्वारा

श्री राजेन्द्र सिंह बिसला : चेयरमैन साहिबा, मेरी पर्सनल ऐक्सप्लेनेशन है। मैं आपके माध्यम से सदन से और विशेषकर आदरणीय बंसीलाल जी से निवेदन करना चाहूंगा। जैसा कि उन्होंने बोलते हुए हाउस में मेरे बारे में कहा है कि यह अफसरों की चापलूसी करने वाला है और हल्के में भी नहीं जाता। मैं आदरणीय चौधरी बंसी लाल जी के ध्यान में यह लाना चाहूंगा कि मैं किसी अफसर की, किसी राजनीतिक आदमी की चापलूसी करने वालों में से नहीं हूं। मैंने यह कहा है कि आपने जो ऐलीगेशन लगाया था कि के0के0 मिश्रा, एस0पी0 फरीदाबाद ने डी0जी0पी0 लक्षमण दास के लड़के की शादी में उसे कार दी है, वह सही नहीं है और मैंने उसको डिनाई किया है। यह गलत बात है। इनको निराधार आरोप नहीं लगाना चाहिए कि मैंने यह भी कहा था कि हमारे चीफ सैक्रेटरी एच0डी0 बंसल डैड आनेस्ट है, ट्रांसपेरेन्ट उनकी औनेस्टी है तो मैंने इस तरह की कोई चापलूसी नहीं की है। मैं चौधरी बंसी लाल जी से निवेदन करना चाहूंगा कि मैं कोई नया राजनीति में नहीं हूं। पार्टीशन से पहले 1937 से पहले हमारे घर में एम0एल0ए0 शिप रही है। जो पुराने राजनीतिक परिवार हैं, आप उनसे दरियाफ्त कर सकते हैं। मैं उन

[राजेन्द्र सिंह बिसला]
विधायकों में से हूं जिसने ओन दी फ्लोर आफ दी हाउस, 1977 में इस हाउस में मिनिस्टर पर भी करप्शन के आरोप लगाए थे। इसलिए मैं चौधरी बंसी लाल जी से निवेदन करना चाहूंगा कि सबको एक ही लाठी से न हांकें। जो मेरी नालेज में है, जो असलियत है उसको ही मैंने हाउस में कहा है। इस तरह से गलत आरोप किसी पर नहीं लगाने चाहिए। चेयरमैन साहिबा, यही मैंने निवेदन करना था।

चौधरी बंसी लाल : चेयरमैन साहिबा, इनके याद दिलाने से मुझे भी यह बात याद आ गयी कि इन्होंने मेरे ऊपर एक इल्जाम यह भी लगाया था कि ये यहां पर तो इल्जाम लगाते हैं और बाहर जाकर पुलिस वालों को टेलीफोन करते हैं। मैंने आज तक किसी डी0जी0पी0 को या अन्य किसी दूसरे को कभी भी कोई टेलीफोन नहीं किया।

वर्ष 1995-96 के बजट पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)

साथी लहरी सिंह (रादौर—अनुसूचित जाति) : चेयरमैन साहिबा, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। (विघ्न)

सभापति महोदया : कर्ण सिंह जी, क्या आप प्वायंट आफ आर्डर पर बोलना चाहते हैं ?

श्री कर्ण सिंह दलाल : जी हां। चेयरमैन साहिबा, मेरा प्वायंट आफ आर्डर यह है कि माननीय बिसला साहब ने आज फिर दोबारा से फरीदाबाद पुलिस प्रशासन की तारीफ की है।

सभापति महोदया : यह कोई प्वायंट आफ आर्डर नहीं है।

श्री कर्ण सिंह दलाल चेयरमैन मैडम, यह भी प्वायंट आफ आर्डर है कि हमारे जिला फरीदाबाद में पुलिस के एस0पी0 ने बुरी तरह से फरीदाबाद को लूट लिया है।

श्री राजेन्द्र सिंह बिसला : चेयरमैन मैडम, इनको तो पुलिस के नाम का फोबिया हो गया है।

श्री कर्ण सिंह दलाल : चेयरमैन साहिबा, हमारे जिले के लोग पुलिस प्रशासन से परेशान हैं। इनको उनकी ईमानदारी के लिए तगमा देने की बजाए, उनकी खिचाई करनी चाहिए और उनके तबादले की सिफारिश करनी चाहिए। (विघ्न)

श्री राजेन्द्र सिंह बिसला : सर, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। (विघ्न)

साथी लहरी सिंह : सभापति महोदया, आपका एक बार फिर बहुत-बहुत

17.00 बजे

धन्यवाद कि आपने मुझे बोलने का समय दिया । सबसे पहले तो चौधरी और पाल जी ने जैसा कहा मैं उस बारे कहना चाहता हूं कि अगर अच्छा बजट आ जाए तो इनको दर्द और घाटे का बजट आ जाए तो भी इनको दर्द । अच्छा बजट आ गया तो कहते हैं कि इलैक्शन की वजह से ऐसा बजट दिया है । मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जिस तरह से यह बजट दिया गया है, इसमें गरीब आदमी का, व्यापारी का, किसान का, मजदूर का और सारे हरियाणा के हितों का ख्याल रखा गया है । इतना ही नहीं, ये सब जो कहते हैं कि इस बजट में क्या दिया इस बजट में वह चीज दी जिस से इनके खोदे हुए गड्ढे भर जाएं । यह चाहे जैसे भी सोचें, मैं तो एक ही निवेदन करूंगा कि गुप्ता जी ने जो बजट पेश किया किया है, उसमें सबसे पहले यह कहा है कि हमारे हरियाणा की 87 प्रतिशत जनता गांवों में रहती है । (इस समय सभापतियों की सूची में से एक सदस्य श्री मनीराम केहरवाला पदासीन हुए) उस पर अब सबसे ज्यादा खर्च होगा । कोई भी स्कीम गवर्नमैंट आफ इण्डिया शुरू करती है, वह स्कीम सबसे पहले हमारे हरियाणा प्रदेश में लागू होती है । वह इसलिए लागू होती है, क्योंकि यहां के अफसरों, मंत्रियों और मुख्य मन्त्री जी की लग्न हमेशा इस बात में रहती है कि हरियाणा की जनता की सेवा करनी है और जो इंसान सेवा करेगा उसकी हाजिरी भी परमात्मा के दरबार में लगेगी । हम लोगों से वायदा करके आए हैं कि जहां काम की जरूरत होगी, वहां काम करेंगे । जहां काम की जरूरत थी, वास्तव में वहां काम प्रौयरिटी पर किए हैं, चाहे वह सड़कों के हों, कृषि के हों या रूरल डिवैल्पमैंट की स्कीम हो, उस पर सरकार ने पूरी तवज्जोह दी है । सभापति महोदय यू०पी० की सरहद से और हिमाचल की सरहद से जो हमारी जान है दादुपुर नलवी नहर निकालनी है, उसके लिए मैं मुख्यमन्त्री जी का, सरकार का और चौधरी जगदीश नेहरा जी का आभारी हूं कि इन्होंने हिम्मत करके सारे स्टेट्स के मुख्य मन्त्रियों को इकट्ठा करके एक ऐसे फैसले पर आए हैं कि जो पानी बेकार जा रहा था, उससे हमारा इलाका सरसब्ज होगा और वास्तव में एक ऐसी दिशा बनेगी कि आज हमारे एक एकड़ में जितनी फसल होती है । इस नहर के बन जाने से, उसमें दो क्विंटल का फर्क पड़ जाएगा । इस बात की इनको दाद देनी चाहिए । बजाए इसके ये उल्टा कहते हैं कि इस बजट में क्या दिया है ? वहां इतना बड़ा काम शुरु होगा, जिसमें 300-400 करोड़ रुपये लगेंगे । हमारे इलाके के गरीब बच्चे इंजीनियर और क्लर्क लगेंगे । उनको रोजगार मिलेगा ।

शिक्षा के बारे में भी इस बजट में प्रोविजन रखा गया है । इस बजट में यह कहा गया है कि हम इतने स्कूल अपग्रेड करेंगे । वास्तव में सरकार का यह कर्तव्य है और सरकार इसके लिये पूरी तरह से जागरूक है कि सब को साक्षर बनाने के लिये अच्छी से अच्छी शिक्षा देनी है । शिक्षा मन्त्री जी यहां पर बैठे नहीं हैं, मेरा उन से अनुरोध है कि वे इस बात की ओर विशेष ध्यान देवें कि जहां-जहां स्कूलों को अपग्रेड करने की जरूरत है, वहां पर स्कूलों को अपग्रेड किया जाये । कई गांव

[साथी लहरी सिंह]

ऐसे हैं जहां पर कि प्राईमरी स्कूल्ज की ब्रांचिज हैं । उन स्कूलों को सब से पहले इंडीपैंडैंट तौर पर प्राईमरी स्कूलों में कंवर्ट किया जाना चाहिये । जैसे छारपुरा, सतगौली, और रामगढ़ व साहुबपुरा इत्यादि जगहों पर प्राईमरी स्कूल्ज में अप-ग्रेडेशन होनी चाहिये । इस तरह का सरकार को एक क्राइटेरिया बनाना चाहिये कि एक ब्लाक के लिए कम से कम एक 10+2 स्कूल अवश्य होना चाहिए । जैसे मेरा ब्लाक बवैन है । यारा है, गुमथला, जठलाना, मेहरा जोकि पांच-पांच, सात-सात, 10–10 हजार व 15–15 हजार की आबादी के गांव हैं, इनको आबादी के लिहाज से 10+2 का एक-एक स्कूल अवश्य दिया जाना चाहिए ताकि बच्चों को पढ़ने के लिए दूर दूर तक न जाना पड़े ।

इसी तरह से मिडल स्कूल्ज के बारे में भी कहना चाहूंगा । जहां पर बहुत पुराने प्राईमरी स्कूल्ज हैं, उनको मिडल स्कूलों में अप-ग्रेड किया जाना चाहिए । जैसे खेड़ी दावदलान है । यहां पर 1897 से एक प्राईमरी स्कूल है उसको मिडल स्कूल अप-ग्रेड कर दिया जाए । इसी तरह से चौलरा, कलालमाजरा व ईशर हेड़ी गांव है । वहां पर भी प्राईमरी स्कूल्ज को मिडल में अपग्रेड कर दिया जाए । इसी तरह से हर पहलू पर आम आदमी को सरकार द्वारा फायदा पहुंचाना चाहिए ।

इसके साथ-साथ दूसरी बात सड़कों से संबंधित है । चौधरी अमर सिंह जी बैठे हैं । इन्होंने इस बारे में काफी कोशिश की है । इन्होंने लिखा है कि 450 करोड़ रुपए की लागत से 811 किलोमीटर लम्बी सड़कें बनाने की राज्य सड़क परियोजना विश्व बैंक द्वारा सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर ली गई है तथा परियोजना बनाने का तथा मूल्यांकन का कार्य चल रहा है । मैं आपको बताता हूं कि यह जो सरकार ने कहा है, इसकी हम सराहना करते हैं लेकिन मैं उनके नोटिस में यह बात लाना चाहता हूं कि कई छोटी-छोटी सड़कों के ऐसे टुकड़े हैं जो दो-दो किलोमीटरज के हैं, जिनको आपस में जोड़ने से कम से कम 40 किलोमीटर का रास्ता कट जाता है । इस बीमारी को काटने के लिये मैं सरकार से कहूंगा कि जन्धेड़ा से चौलरा, काबुलपुर से गोलनी, महमदपुर से थम्मड़, खेड़ी दावदलान से मेहरा, फतेहगढ़ से टसका खादर, हंड़ताल से गलौर, गलौर से भजरा, सिली खुर्द से गलौर, गंदयाना से जीवन माजरी, पोटली से डेरापुरबीयान, यह छोटी-छोटी सड़कें हैं, इनको बनाना चाहिए । इनके बनाने से लोगों को आने-जाने में कम से कम 40, 20 या 30 किलोमीटरज का फर्क अवश्य पड़ेगा । इसलिए सरकार इन सड़कों की ओर ध्यान देवे ।

इसके साथ-साथ मैं यह कहूंगा कि सिकन्दरा से भोगपुर में बीच का एक पुल बन रहा है । इसके लिए हम सरकार के आभारी हैं । इस पुल के बनने से किसान जो अपनी ट्राली पर सामान ढोता है, गन्ना मिल में ले जाता है, उसको 70 पैसे प्रति क्विंटल का किराए का फर्क पड़ेगा । इसका फायदा यह होगा कि किसान को जितना

ज्यादा रेट उसकी जिन्स का मिलेगा, उतनी ज्यादा मार्किट फीस सरकार को भी आएगी। सरकार को इससे इन्कम भी होगी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस रास्ते से हर साल 6 लाख क्विटल गन्ना जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि किसानों को इस पुल के बनने से चार लाख रुपये का फायदा होगा।

अब मैं ऐग्रीकलचर से संबंधित कुछ बातें कहूंगा कि ऐग्रीकल्चर के लिये, कृषि के लिये सरकार ने जो रुख अपनाया है उसका ताजा सबूत यह है कि जितना आपके हिस्से सैंट्रल पूल में अनाज आता है उससे कहीं ज्यादा हम उन्हें अनाज दे देंगे और अगले साल इसे और ज्यादा बढ़ा देंगे (तालियां) और इसका सारा श्रेय किसानों को ही जाता है न कि हम लोगों को। मजदूर भी इसमें भागीदार हैं। मजदूर खेत में काम नहीं करेगा तो लोग भूखे मर जाएंगे। हमारा इलाका तो ऐसा है कि अगर वह खेती करना बन्द कर दे, तो सारे हरियाणा में रोटी नहीं मिलेगी। यह मैं यमुनानगर और कुरुक्षेत्र जिलों की बात कह रहा हूं। वहां पर वास्तव में इतना अनाज होता है। इसके बावजूद हमारे साथ ज्यादती भी हुई है। हमारे यहां पर आगुमैंटेशन कैनाल बनाई गई और वह हमारी छाती को चीरती हुई चली गई। यहां के पानी को भिवानी में ले गए। हम तो यह कह रहे हैं कि जो हमारे मुश्किल के दिन हैं, जब हमारी फसल पकने को होती है, तो उस समय हमें एक-दो पानी उस पानी में से मिलने चाहियें। इसके बाद में मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे इलाके में जहां आप एक्सप्रैस-हाई-वे बना रहे हैं, वहां मिसिंग लिंक्स भी बना दें। यह बात मैं मानता हूं कि इस साल सड़कों की मुरम्मत काफी हुई है। लेकिन कई सड़कें ऐसी हैं, जिनकी तरफ ज्यादा ध्यान देने की जरुरत है। जैसे बड़सामी से खुरकनी सड़क है जो आदी जानकी देवी जी के हल्के में पड़ती है।

इसके अलावा मैं नेहरा साहब को कहना चाहता हूं कि इरीगेशन की जहां तक बात है, एक पुल ऐसा है जो टूट गया है और उस पर 50-60 लाख रुपए लगेंगे। वह पुल डब्ल्यू0 जे0सी0 पर है। इस वजह से रास्ते बिल्कुल रुके पड़े हैं। बीस-पच्चीस गांव ऐसे हैं जिनकी जमीन उधर है और गांव इधर हैं। इसलिये यह धनौरे का पुल जरुर बनना चाहिये। उस पर जो लागत आएगी, उसे आप चाहे टोल टैक्स की तरह से रिकवर कर लें। इसके साथ-साथ मैं ट्रांसपोर्ट का जिक्र करना चाहूंगा। आज इन भाइयों को दर्द इसलिये होता है कि इनके टाईम में हमारी ट्रांसपोर्ट न फर्स्ट, न सैकिंड न थर्ड और न ही फोर्थ प्लेस पर थी। लेकिन आज हमारी ट्रांसपोर्ट हिन्दुस्तान में पिछले तीन सालों से नम्बर एक पर आ रही है। आज इससे अच्छी से अच्छी सर्विस दी जा रही है। मैं तो चाहता हूं कि अच्छे काम को हमेशा सराहना चाहिये। मैं भी एक टाईम अपोजीशन में था लेकिन जब इन मुख्य मन्त्री महोदय ने लड़कियों की फीस माफ की थी तो मैंने उसकी तारीफ की थी। अब मैं ट्रांसपोर्ट के बारे में कहना चाह रहा था कि आज हमारे यहां एक एक्सप्रैस सर्विस शुरु हुई है जिसने डिलक्स बस सर्विस को भी मात कर दिया है। दूसरी स्टेट्स में हमारी एक्सप्रैस सर्विस के मुकाबले डिलक्स बसें भी पीछे

[साथी लहरी सिंह]

रह गई हैं। दूसरी स्टेट का हर आदमी आज हमारी एक्सप्रैस बसों में बैठना चाहता है। चेयरमैन महोदय, मेरा हमारे भाई बलबीर पाल शाह के चरणों में निवेदन है कि ये जो प्राइवेट बसें चलाई हैं, इनके बारे में धीर पाल जी ने कहा था कि सरकार ने प्राइवेट बस वालों को मार दिया। इस बारे में बात यह है कि अगर प्राइवेट ट्रांसपोर्ट वाले यहां पर पार्टी बाजी करना शुरू कर दें, तो उन्होंने कोई ठेका थोड़ा ले रखा है। हमारी तरफ के आदमियों का भी सरकार ने ध्यान रखना है। हमारी तरफ के आदमियों ने बड़ी अच्छी तरह से मुख्य मन्त्री जी के सामने अपनी बातें रखी हैं। मैं कहता हूं कि उनके साथ बिल्कुल भी भेद भाव नहीं हुआ। यह मैं मानता हूं कि जिन्होंने बसें ली हैं, उनको घाटा जरूर हुआ है लेकिन अपनी बात रखने का कोई तरीका होता है। हमारे अम्बाला, करनाल और यमुना नगर के जितने भी यूनियन वाले या ट्रांसपोर्टर आए हैं, उन्होंने कहा है कि अगर हमारा 4-5 किलोमीटर का रूट बढ़ा दें तो हमें न घाटा होगा और न मुनाफा होगा यानी उससे उनका रोजगार चल सकेगा। सरकार ने सभी को लाटरी निकाल कर रूट दिए और किसी के साथ भेदभाव नहीं बरता गया। यह बहुत बढ़िया काम किया है। उसके बावजूद भी अगर किसी को घाटा है तो मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि सरकार उनका चार-पांच किलोमीटर का रूट बढ़ा दे क्योंकि यह उनकी रोजी रोटी का काम है और वह पब्लिक को सफर करने की अच्छी सहूलियत दे सकते हैं।

सभापति महोदय, अब मैं कोआप्रेशन डिपार्टमैंट के बारे में अपने विचार प्रकट करना चाहूंगा। मैं सरकार को इस बात की मुबारिकबाद देना चाहूंगा कि हमारी सरकार ने जिस आदमी को वास्तव में कोआप्रेशन का हिस्सा मिलना चाहिये, उसको दिया है। हमारी सरकार ने पौने दो लाख शिड्यूल्ड कास्ट्स के मैम्बर्ज को मैम्बरशिप दी है। सभापति महोदय, आप तो हरको बैंक के चेयरमैन भी हैं। आपने वास्तव में हरको बैंक में बहुत बढ़िया काम किया है। मैं मुख्य मंत्री जी को और अपनी बहन, जो इस महकमे की मंत्री हैं, को मुबारिकबाद देता हूं कि इस महकमे में आम आदमी के कर्ज लेने की जो पालिसी बनाई है, वह बहुत बढ़िया है। जो आदमी सिक्योरिटी जमा करवाएगा, उसको कर्जा मिल जाएगा। लेकिन इसमें फील्ड स्टाफ थोड़ी सी कोताही करता है और कर्जा लेने वाले आदमी को तंग करता है। उन पर आपको लगाम लगानी चाहिये। अगर आपके नोटिस में न हो तो मैं आपके नोटिस में ला देता हूं कि उनका आम आदमियों के साथ व्यवहार ठीक नहीं है। उनका व्यवहार ठीक होना चाहिये। जिस आदमी को जमानत की जरूरत नहीं है, उसको लोन मिल जाना चाहिये। सभापति जी, बागवानी की जो बात है, वह बहुत अच्छी बात है। बागवानी की स्कीम हिन्दुस्तान में सबसे पहले हमारे प्रदेश में आई थी। अब मैं अनाज के बारे में कहना चाहूंगा। हमारे मुख्य मंत्री जी विदेश जा कर आए। वहां पर इनके सामने बीज का जिक्र आया। हमने यहां करनाल फार्म में देखा कि वहां पर आधा आधा किलोग्राम का टमाटर लगा हुआ था। यह वास्तव में हरित क्रांति है। मेरे कहने का मतलब है कि जो हमारे टैक्नीकल आफिसर्ज हैं, चाहे

वे एयर कंडीशंड कमरों में बैठते हैं लेकिन उनमें बीज के बारे में इतना ज्ञान नहीं है जितना ज्ञान हमारे किसानों को है। हमारे किसानों को यह ज्ञान है कि किस समय किस फसल में क्या दवाई डालनी चाहिये जबकि हमारे टैक्नीकल साईंटिस्टों को इतना ज्ञान नहीं है। मैं किसानों को इस बात की दाद देता हूं कि वह आज बहुत समझदार हो गए हैं। आज हमारे किसान सारे देश का पालन पोषण कर रहे हैं। सभापति महोदय, हमारी पब्लिक हैल्थ मिनिस्टर साहिबा इस समय हाउस में नहीं बैठी है। मेरा उनसे निवेदन है कि पब्लिक हैल्थ डिपार्टमैंट जिस किसी भी गांव में पानी की टूटी लगाए, वह टूटी लगाने से पहले गांव की गलियों में नालियां बना दे क्योंकि नालियां न बनने के कारण पानी गलियों को तोड़ देता है। अगर नालियां बन जाएंगी तो वह पानी जोहड़ में चला जाएगा। सभापति महोदय, हमारा पब्लिक हैल्थ डिपार्टमैंट बहुत अच्छे काम कर रहा है। अभी यमुना वाटर के बारे में इन्होंने नींव पत्थर रखा कि यमुना में तो गंदा पानी जा रहा है, उसको ट्रीट करके साफ पानी बनाया जाएगा।

सभापति महोदय, अब मैं हैल्थ डिपार्टमैंट के बारे में कहना चाहूंगा। हमारी हैल्थ मिनिस्टर बहन करतार देवी बहुत कोशिश कर रही हैं कि हर हॉस्पिटल में पूरी दवाईयां पहुंचे। इन्होंने यह बहुत ही सराहनीय काम किया है। ये पहले भी इस विभाग की मंत्री रही हैं और अब भी हैं। इनकी यह पूरी कोशिश होती है कि रूरल एरियाज में दवाईयां पूरी अवश्य पहुंचे। मेरा बहन जी से नम्र निवेदन है कि जहां पर डाक्टर पूरे नहीं हैं, वहां पर जल्दी से जल्दी डाक्टर भेजें। कम से कम जो सी0एच0सीज0 हैं, उनमें डाक्टर पूरे होने चाहियें ताकि वहां के लोगों को दिक्कत न हो। मैंने मांगे राम गुप्ता जी से एक क्वैश्चन किया था। उसका जवाब आया कि सब-सैंटर पर 800 रुपए और सी0एच0सी0 पर 10 हजार रुपए दवाईयों के लिये दिए जाएंगे। यह बहुत मामूली सी अमाउंट है। एक सी0एच0सी0 जो 30 हजार की आबादी पर एक बनाई जाती है, उसको साल में दवाईयों के लिये केवल 10 हजार रुपये दिए जाएं, यह तो ऊंट के मुंह में जीरा देने के समान है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस राशि को बढ़ाया जाना चाहिये। इसके साथ ही साथ यह भी अनुरोध है कि वहां पर ऐसी दवाईयां तो होनी ही चाहियें जो एमरजैंसी सेवा में काम में आ सकें। यदि गांव में भी कोई सीरियस एक्सीडैंट किसी का हो जाए तो उसको इलाज के लिये या तो कुरुक्षेत्र, या यमुना नगर या फिर चण्डीगढ़ आना पड़ता है। अतः इस बात का अवश्य ध्यान रखना चाहिये कि इन पी0एच0सीज0 में ऐसी दवाईयों की कमी न हो। रादौर में जो सी0एच0सी0 हैं, वहां पर 10 बैड्ज हैं। मैं चाहता हूं कि वहां पर कम से कम 30 बैड्ज होने चाहिये। मेरे हल्के के दो गांव जिनकी आबादी 12-15 हजार के बीच है, वहां पर यानि जठलाना और गुमथला में पी0एच0सीज0 जरूर बननी चाहियें ताकि रूरल एरियाज को ज्यादा से ज्यादा सहूलियत मिल सके।

चेयरमैन महोदय, अब मैं तकनीकी शिक्षा के बारे में जिक्र करते हुए कहना चाहता हूं कि आज हमारे नौजवान प्रदेश में भटकते फिर रहे हैं। उनको सही रास्ते पर लाने

[साथी लहरी सिंह]

की तकनीकी शिक्षा के माध्यम से सरकार कोशिश कर रही है। मेरे हल्के में इन्जीनियरिंग कालेज खुलना चाहिये और साथ ही साथ आई0टी0आई0 व वोकेशनल इंस्टीच्यूट्स भी खुलने चाहियें ताकि बच्चे अधिक से अधिक तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर सकें। मैं सरकार के ध्यान में कुछ बातें लाना चाहता हूं। मेरे हल्के में एक सेठ ने 50 लाख रुपये खर्च करके इंजीनियरिंग कालेज की बिल्डिंग बना रखी है। मैं चाहता हूं कि जब इतना पैसा लगा कर सरकार को बिल्डिंग दे दी गई हो तो वहां पर इसे तुरंत चालू कर देना चाहिये। हमारी सरकार ने जो जगह-जगह पर वोकेशनल इन्स्टीच्यूट्स दिए हैं, उनमें 6-7 हाई स्कूलों से जो बच्चे मैट्रिक पास करके निकलेंगे, वे इन इन्स्टीच्यूट्स में वोकेशनल ट्रेनिंग ले सकते हैं और अपनी जिन्दगी बना सकते हैं।

इसके साथ-साथ अब मेरा सरकार से अनुरोध है कि सरकार को नैतिक शिक्षा की तरफ विशेष ध्यान देना चाहिये। इस विषय का एक पीरियड पहली क्लास से लेकर कालेज स्तर तक अवश्य लगना चाहिये बेशक वह पहला पीरियड हो ताकि हमारे बच्चे समझें कि हमें बुजुर्गों का कैसे आदर-सम्मान करना चाहिये और छोटे-बड़े भाई बहनों में किस तरह से बैठना और बात करनी चाहिये। उनको पता लग सके कि हमारी संस्कृति क्या है और हमारी सभ्यता क्या है ? हमारे ऋषि मुनियों ने कैसे और क्या संदेश दिए हैं। हमारी सभ्यता और संस्कृति पर इंग्लैंड और अमेरिका व दूसरे देशों से रिसर्च स्कॉलर आकर रिसर्च कर रहे हैं। अभी पीछे कुरुक्षेत्र में एस्कोन (Escon) से कोई आए थे जो रिसर्च कर रहे थे। इसी प्रकार से और दूसरी जगहों से लोग आकर यहां की संस्कृति और सभ्यता की रिसर्च कर रहे हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि एक पीरियड नैतिक शिक्षा का बच्चों को अवश्य पढ़ाया जाना चाहिये ताकि बच्चों को पता लग सके कि भारत वर्ष में विवेकानन्द और महर्षि दयानन्द जैसे महान सपूत पैदा हुए हैं। इन शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हुआ अपना स्थान लेता हूं। जय हिन्द।

श्री धर्मपाल सिंह (दादरी) : आदरणीय चेयरमैन साहब, फाईनैंस मिनिस्टर श्री मांगे राम गुप्ता जी ने जो बजट रखा है मैं उसके समर्थन में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। हरियाणा प्रदेश देश के अग्रणी राज्यों में से एक है और उसका सारा श्रेय चौधरी भजन लाल जी की नीतियों को जाता है। बजट स्पीच के प्रथम पृष्ठ पर 1994-95 के दौरान राज्य की आर्थिक स्थिति पर मोटे तौर पर प्रकाश डाला गया है। वर्ष 1993-94 के दौरान स्थिर मूल्य 1980-81 के आधार पर राज्य की आय में 4.2 प्रतिशत वृद्धि हुई। यह आय वर्ष 1992-93 में 5818 करोड़ रुपये से बढ़ कर वर्ष 1993-94 में 6065 करोड़ रुपये हो गई है। वर्तमान मूल्यों के आधार यह आय वर्ष 1992-93 में 15,644 करोड़ रुपये से बढ़ कर वर्ष 1993-94 में 18,057 करोड़ रुपये हो गई। इस प्रकार इसमें 15.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

वर्ष 1993-94 में स्थिर मूल्यों (1980-81) के आधार पर प्रति व्यक्ति

आय 3,479 रुपये होने का अनुमान है जब कि वर्ष 1992-93 में यह आय 3,411 रुपये थी। केन्द्र सरकार द्वारा कीमतों में वृद्धि पर नियन्त्रण के प्रयत्नों के फलस्वरूप अखिल भारतीय श्रमिक वर्ग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक मार्च, 1993 में 243 से 9.9% बढ़ कर मार्च 1994 में 267 हुआ। उसके बाद यह 9% बढ़ कर नवम्बर, 1994 में 291 हो गया। इसी प्रकार हरियाणा राज्य श्रमिक वर्ग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक मार्च 1993 में 229 से 9.2% दर से बढ़ कर मार्च, 1994 में 250 हो गया। बाद इसके 8.8% की दर से बढ़ कर यह नवम्बर, 1994, में 272 हो गया।

इसके साथ ही राज्य की सार्वजनिक वितरण प्रणाली में काफी सुधार हुआ है। गेहूं, आटा, चीनी, मिट्टी का तेल, कपड़ा, खाद्य तेलों आदि जैसी वस्तुओं का उचित मूल्य पर 4,728 ग्रामीण और 2,488 शहरी दुकानों पर दिया गया है। इसके साथ ही जो पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जाति के लोग हैं उनके लिये भी सरकार ने प्रावधान रखा है और उनको भी इस वितरण प्रणाली के अधीन लाया गया है। उनको भी कण्ट्रोल रेट पर जो भी खाद्य पदार्थ होंगे, वे होटल चलाने के लिये या दुकानें चलाने के लिये मिलेंगे। चेयरमैन साहब, इस सरकार ने वित्त आयोग और चुनाव आयोग का गठन भी किया है और पंचायतों के जो चुनाव करवाए गए हैं, वे बड़े ही निष्पक्ष करवाए गए हैं। जिला परिषदों और नगरपालिकाओं के भी चुनाव करवा दिए गए हैं और उनकी वित्तीय स्थिति सुधारने के लिये एक वित्त आयोग का गठन किया गया है यह एक सराहनीय कदम है। जहां तक केन्द्रीय सहायता का सवाल है, चौधरी भजन लाल जी ने केन्द्र के नेताओं से मिल कर और आयोग से मिल कर अधिक से अधिक केन्द्रीय सहायता हरियाणा को दिलाने के लिये सिफारिश की है। हरियाणा में बिजली की खपत बाकी के राज्यों से अधिक है। बिजली की आश्वकता पूरी करने के लिये सरकार ने काफी प्रयत्न किये हैं। बिजली के उत्पादन में वृद्धि की है बिजली की वितरण प्रणाली में सुधार लाया गया है और लाईन लौसिज को कम किया गया है। यमुना नगर में थर्मल प्लांट लगाने के लिये 25 जनवरी, 1995 को इस्राईल के आईजनबर्ग कम्पनी के ग्रुप के एक सदस्य मैसर्ज यू0 डी0 आई0 के साथ समझौता करके 210 मैगावाट वाली छठी यूनिट का निष्पादन किया गया है। इसी तरह से हिसार में नया थर्मल बिजली संयन्त्र स्थापित करने के लिये सहयोग देने के लिये निजि बिजली उत्पादकों से प्रस्ताव मांगे गए हैं और सभी प्रमुख औद्योगिक नगरों में 70 से 100 मेगावाट वाले डीजल पर आधारित बिजली उत्पादन संयन्त्र स्थापित करने के लिये भी निजी पार्टियों से प्रस्ताव मांगे गए हैं। लाईन लौसिज को कम करके तथा बिजली की चोरी रोकने के लिये तथा बिजली का उत्पादन बढ़ाने के लिये यह सरकार प्रयत्न कर रही है। बिजली की चोरी रोकने के लिये उपभोक्ता परिसरों की व्यापक

[श्री धर्मपाल सिंह]

तौर पर जांच पड़ताल सरकार करवा रही है और ऐसे इलैक्ट्रोनिक मीटर लगाने का प्रस्ताव है ताकि बिजली की चोरी न हो पाए। वर्ष 1995-96 के दौरान सरकार ने 11 हजार नये ट्यूबवैल कनैक्शन देने की स्कीम भी रखी है। इससे साफ झलकता है कि सरकार की कृषि की तरफ बहुत ज्यादा तवज्जोह है। चेयरमैन साहब, जहां तक बिजली की नाजुक स्थिति का सम्बन्ध है, सरकार को जो बिजली खरीदनी पड़ती है, वह महंगे दरों पर खरीदनी पड़ती है और महंगी बिजली ले कर जमीदारों को सस्ते दर पर उसका लगभग 50% हिस्सा कृषि क्षेत्र में रियायती दरों पर सप्लाई किया जाता है जिस कारण से बोर्ड को काफी हानि हो रही है। चालू वर्ष के दौरान, बोर्ड को 234.84 करोड़ रुपए की कुल वाणिज्यिक हानि होने की संभावना है। कोयले और तेल जैसी बुनियादी जरूरतों की बढ़ती हुई लागत को ध्यान में रखते हुए और वाणिज्यिक हानि को अशंतः पूरा करने के लिए बिजली की दरें बढ़ाना अनिवार्य हो गया था इससे लगभग 170 करोड़ रुपये का वार्षिक राजस्व प्राप्त होने की संभावना है। इसके साथ ही इस बात का भी ध्यान रखा गया है कि बिजली की जो दरें बढ़ाई गई हैं, उनका कृषि के क्षेत्र में कम से कम बोझ पड़े। चेयरमैन साहब, इसके साथ ही जो सड़क संरचना व्यवस्था है, इस बारे में सरकार ने सड़कों को तुरन्त व बेहतर बनाने के लिये संकल्प किया है। इस सरकार ने 3 वर्षों में 484 किलो मीटर लम्बी सड़कों का निर्माण किया है विद्यमान 7538 किलोमीटर लम्बी सड़कों पर नई परत चढ़ाई गई है और 831 किलोमीटर लम्बी सड़कों का सुधार किया है। इसके साथ ही राजमार्गों को चार लाईन किया गया है और इसके साथ ही 16 पुलों का निर्माण किया जा रहा है, जिनमें फरीदाबाद, हिसार और सोनीपत के ओवर ब्रिज तथा जल्ला सड़क पर घग्गर नदी पर और नारायणगढ़ सढौरा सड़क पर मारकंडा नदी पर पुल बनाने की योजना है। रिवाड़ी और बल्लबगढ़ के दो ओवर ब्रिजों का कार्य भी 1995-96 के दौरान शुरू किए जाने की संभावना है।

चेयरमैन साहब, आज सिंचाई के लिए पानी की जरूरत बढ़ गई है और हम एस0 वाई0 एल0 को जल्दी पूरा करने के लिये केन्द्रीय सरकार से अनुरोध कर रहे हैं। आज 20 वर्षों से लटके हुए यमुना के मामले पर भी समझौता हुआ है और 100 सालों से लटके हुए ताजेवाला हैड वर्क्स के निर्माण को भी जल्दी से पूरा किया जाएगा। यह सब मुख्यमन्त्री चौधरी भजन लाल जी की मेहरबानी से ही हुआ है। वर्ष 1994-95 के दौरान लघु सिंचाई के अन्तर्गत 366 किलोमीटर लम्बी 100 खालों को 20 करोड़ रुपये की लागत से पूरा किया जाएगा।

चेयरमैन साहब, जहां तक कृषि का मामला है इस बारे मेरा कहना है

कि यह 75 प्रतिशत लोगों के लिये जीविका का साधन है। कृषि इनपुट्स के लिये वर्ष 1994-95 के दौरान पर्याप्त व्यवस्था की गई है । विभिन्न कृषि इन्पुट्स तथा प्रमाणित बीजों आदि पर सबसिडी दी जा रही है । किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने तथा उन्हें अधिक लाभ पहुंचाने के लिये फसलों की विविधता पर उचित बल दिया जा रहा है । गन्ना, कपास और तिलहन जैसी फसलों की खेती में तेजी से वृद्धि हो रही है । राज्य में सूरजमुखी की खेती व्यापक स्तर पर की जाती है सोयाबीन और राजमाह की खेती को लोकप्रिय बनाने के प्रयत्न किए जा रहे हैं । वर्ष 1995-96 में कृषि क्षेत्र में असरदार बढ़ोतरी के लिये विभिन्न स्कीमों को लागू करने पर विचार यह सरकार कर रही है । इसी तरह से हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड सोनीपत के निकट राई में 550 एकड़ भूमि पर 100 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से एक आधुनिक प्रोसैसिंग काम्पलैक्स विकसित कर रहा है ।

जहां तक बागवानी का सवाल है फलों, और सब्जियों को, खुम्बी, फूलों के क्षेत्रों में तथा ड्रिप सिंचाई और पालीथीन हाउस जैसी नई तकनीकों को शुरू करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है । इसी तरह से सहकारिता के क्षेत्र में हमने बहुत भारी उन्नति की है और गरीब किसानों, गरीब कारीगरों को गैर सरकारी कर्जा और दूसरे कर्ज देने के लिये भी रुपयों का प्रावधान है ।

जहां तक उद्योगों का मामला है तो राष्ट्रपति शंकरदयाल शर्मा जी ने उद्योगीकरण के क्षेत्र में हरियाणा की उपलब्धियों की प्रशंसा की है ।

इसके साथ ही हरियाणा ने देश में पर्यटन के मानचित्र पर अपना प्रमुख स्थान बना लिया है । इस समय राज्य में पर्यटन के विकास के लिये 45 पर्यटन केन्द्र हैं जिनमें लगभग 2500 व्यक्तियों को सीधा रोजगार मिला हुआ है । वार्षिक योजना 1995-96 में पर्यटन के विकास के लिये 3.52 करोड़ रुपये रखे गए हैं ।

चेयरमैन साहब, जहां तक परिवहन का ताल्लुक है, सरकार ने बहुत बढ़िया बसिज दी हैं । पिछली सरकार द्वारा जो बसों का भट्ठा बैठाया गया था सरकार ने उनका सुधार वर्ष 1993-94 में बहुत ज्यादा किया है । इस समय दो हजार से भी अधिक मार्गों पर लगभग 38,00 बसें करीब 11.99 लाख किलोमीटर प्रतिदिन रास्ता तय करती हैं और इन बसों में लगभग 11.79 लाख व्यक्ति प्रतिदिन यात्रा करते हैं (विघ्न) चौहान साहब को पता नहीं दादरी के बारे में क्यों दर्द हो रहा है? आप औरों की चिंता न करें, केवल अपनी ही देखें। लिंक सड़कों पर लोगों की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिये सरकार ने दिसम्बर, 1994 तक बेरोजगार युवकों की सहकारी समितियों को 1177 बस परमिट जारी किए हैं।

[श्री धर्मपाल सिंह]

इसके अलावा ग्रामीण विकास और शहरी विकास पर सरकार ने पूरा ध्यान दिया है। सरकार ने 60 शहरों में कम लागत वाला सफाई कार्यक्रम क्रियान्वित किया है। सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि 1996 तक हरियाणा को सिर पर मैला उठाने की प्रथा से मुक्त करा दिया जाएगा। इसके अलावा सरकार ने अम्बाला जिले के मोरनी, पिंजौर तथा अन्य इलाकों के विकास के लिये शिवालिक विकास बोर्ड का गठन भी किया है। इसी तरह से जहां तक विकेन्द्रीकृत आयोजना का सवाल है, इसके तहत जिला आयोजना एवं विकास बोर्ड की सिफारिश के अनुसार छोटी विकास परियोजनाओं पर खर्च किया जाता है। जिला स्तर पर विकास स्कीमें बनाने में लोगों की ज्यादा भागीदारी का प्रयास सरकार द्वारा किया गया है और 1995-96 में इस कार्य के लिये 15.63 करोड़ रुपये रखे गए हैं। इसके साथ ही साथ सांसदों के निर्वाचन क्षेत्रों और स्थानीय विधायकों के निर्वाचन क्षेत्रों के लिये विकास की स्कीम्ज चालू की गयी हैं। इससे हर जिले में विधायक अपनी इच्छानुसार विकास के कार्य सरकार के मार्ग निर्देशों के अनुसार करवा सकता है। इसके लिये प्रत्येक विधायक के लिये बीस लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। यह बहुत ही हर्ष की बात है।

चेयरमैन साहब, इसके अलावा जहां तक रोजगार का सवाल है, सरकार ने रोजगार आश्वासन स्कीम के तहत 18 से 60 साल तक की आयु के लोगों के लिये 8.80 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा है।

इसके अलावा जहां तक तकनीकी शिक्षा का सवाल है, सरकार ने प्राईवेट पालिटैक्निकस को सुदृढ़ करने और आधुनिक बनाने के लिये हिसार, फरीदाबाद उटावड़ तथा नारनौल में चार नए पालिटैक्निकस स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है। इसके साथ ही हिसार में तीसरे इंजीनियरिंग कालेज के निर्माण के लिये दो-सौ एकड़ भूमि अधिग्रहण कर ली है और 1995-96 में चार नए पालिटैक्निकस खोलने के लिये 38.99 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रावधान भी सरकार ने रखा है।

जहां तक शिक्षा का सवाल है, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही अच्छी उपलब्धि प्राप्त हुई है। मैं इसके लिए चौधरी भजन लाल जी और माननीय शिक्षा मन्त्री जी को बधाई देना चाहूंगा। प्रान्त में नकल को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। जे0 बी0 टी0 अध्यापकों के 500 अतिरिक्त पद बनाए गए हैं और लगभग 5,160 जे0 बी0 टी0 के रिक्त पदों की भर्ती के लिये विज्ञापन दिए गए हैं। जहां तक लड़कियों की शिक्षा का सवाल है, लड़कियों को स्नातक स्तर तक मुफ्त शिक्षा दी जा रही है। हरियाणा पूरे भारत-वर्ष में ऐसा पहला राज्य

है जहां पर लड़कियों को बी०ए० तक मुफ्त शिक्षा दी जा रही है। यह हमारे लिये बहुत ही गर्व की बात है। शिक्षा की बढ़ रही मांग को पूरा करने के लिये सरकार ने 110 प्राईमरी स्कूलों, 102 मिडिल स्कूलों और 46 हाईस्कूलों का दर्जा बढ़ाकर उन्हें क्रमशः मिडिल, हाई और सीनियर सैकेंडरी स्तर तक का बनाया है।

इसके साथ ही साथ जहां तक स्वास्थ्य सेवाओं का संबंध है, स्वास्थ्य सेवाओं की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिये भी काफी कुछ सरकार ने किया है। लेकिन इस बारे में अभी काफी कुछ और करना बाकी है। इसके अलावा जहां तक जल सप्लाई स्कीम और सफाई का संबंध है, सरकार 2,723 गांवों में जल सप्लाई स्तर को चालीस लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन तक बढ़ाना चाहती है। चालू वर्ष के दौरान 24 करोड़ रुपये की लागत से सात सौ गांव में जल सप्लाई स्तर चालीस लीटर प्रति व्यक्ति तक बढ़ाया जाएगा। वर्ष 1995–96 के दौरान लगभग 30 करोड़ रुपये की लागत से और 800 गांवों को यह सुविधा दी जाएगी और छोटी छोटी ढाणियों तक भी पानी पहुंचाया जाएगा। इसके लिये सरकार बधाई की पात्र है। इस बारे में मेरी माननीय मंत्री महोदया से गुजारिश है कि गांव में पानी के नलकों की मांग रहती है। पानी की कमी को मद्देनजर रखते हुए यदि और नलके लगा दिए जाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। ऊंचे इलाकों में पानी नहीं चढ़ता है। गलियों में कीचड़ ज्यादा रहता है। पानी की टंकियों से पानी के कनैक्शन दे दिए जाएं ताकि गांव में सामूहिक पनघट की जो परिपाटी पहले थी, वह बनी रहे और किसी भी टाईम टूटी खोलकर टंकियों से पानी लिया जा सके। यदि बिजली टाईम-बेटाईम आए तो उससे भी दिक्कत की बात नहीं रहेगी। गलियों में कीचड़ भी नहीं होगा। इसके साथ ही बहिन जी से मेरा यह अनुरोध भी है कि हमारा दादरी वाटर वर्कस बहुत पुराना है। शहर की आबादी पहले से लगभग दुगुनी हो गई है। दादरी शहर में एडीशनल वाटर वर्कस की जो पाईप लाईन है, उसका साईज बहुत छोटा है, उसको बदलने की जरूरत है। मैं गुजारिश करूंगा कि इस तरफ जरूर गौर करें। ऐडीशनल वाटर वर्कस का निर्माण कराएं। सीवर की बड़ी भारी जरूरत है। उसके लिये मुझे उम्मीद है कि बहिन जी जरूर कुछ करेंगी।

जहां तक राज्य लाटरी का सवाल है, सरकार ने बहुत बड़ा निर्णय लेकर राज्य लाटरी पर पूर्णतया: प्रतिबन्ध लगा दिया है। इससे गरीबों पर मार वाली जो बात थी, वह समाप्त हो गई है। सरकार इस बात के लिये बधाई की पात्र है। जहां तक विश्वविद्यालयों की सहायता प्राप्ति का मामला है उसमें सरकार ने पैंशन सेवानिवृति लाभ का निर्णय लिया है। उसके लिये आदरणीय मुख्यमन्त्री जी को धन्यवाद देता हूं और गुप्ता जी ने जो बजट पेश किया है, उसका सहर्ष समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

श्री राम भजन अग्रवाल (भिवानी) : सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया इसके लिये आपका बहुत बहुत धन्यवाद । मांगे राम गुप्ता जी ने जो बजट पेश किया है वह वास्तविकता से बहुत परे है । वास्तविकता तो यह है कि प्रान्त के अन्दर चाहे सड़क का सवाल है, चाहे सीवर का है, सभी का बुरा हाल है । बजट में दिए हुए आंकड़े तो बहुत सुन्दर लगते हैं लेकिन इन आंकड़ों को देखने से निराशा होती है और खास कर मेरे जिले भिवानी पर तो मुख्यमन्त्री जी की विशेष कृपा है। मेरे जिले को नजर अन्दाज कर रखा है । जो आंकड़े दिए गए हैं उस अनुपात में मेरे जिले भिवानी को जरूर हिस्सा मिलना चाहिए। (विघ्न) जहां तक बिजली का सवाल है इस बारे में मैं एक चीज कहना चाहता हूं (विघ्न) मेरी आपसे प्रार्थना है कि भिवानी जिले को इतना नजर अन्दाज न करें । (विघ्न)

सभापति महोदय, स्टेट के अन्दर बिजली का बुरा हाल है । बिजली नाम की तो चीज ही नहीं है । किसी भी क्षेत्र में आप चले जाएं । बिजली का हर जगह पर बुरा हाल है । बिजली चाहे सरकार छः घंटे दे, चाहे आठ घंटे दे लेकिन सरकार को इस बारे में समय निश्चित करना चाहिए । किसी प्रकार की अनियमितता नहीं होनी चाहिये कोई किसी किस्म का ब्रेक डाउन नहीं होना चाहिये । यही कारण है कि सरकार जिस समय बताती है, उस समय ही बिजली पूरी नहीं मिल पाती जिससे किसानों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है । बिजली के समय के बारे में सरकार को पहले ही अनाऊंस कर देना चाहिये । बिजली मन्त्री ने जैसे कहा था कि 6 बजे से 10 बजे तक बिजली अवश्य देंगे लेकिन बिजली जाती भी इसी समय में है । इस ओर सरकार को अवश्य ध्यान देना चाहिये ताकि जनता को, किसानों को किसी प्रकार की तकलीफ न हो ।

इसी तरह से बिजली के खम्भों का बुरा हाल है । जो पुराने बिजली के खम्भे हैं वे नीचे से गल गये हैं। उनकी नीचे से मुरम्मत करवानी चाहिये । कहीं यह न हो कि अगर वे गिर जायें और किसी का नुक्सान कर दें । गले हुए खम्भों से कोई न कोई एक्सीडैन्ट भी हो सकता है । अगर उन खम्भों को उतरवा कर बेचो तो उनकी कीमत आपको सीमेंट के खम्भों से ज्यादा मिलेगी । इस ओर सरकार को ध्यान देना चाहिये ।

इसी तरह से बिजली के बिलों का सवाल है । बिजली के रेटस तो सरकार ने बढ़ा दिये लेकिन बिजली की सप्लाई प्रोपर नहीं है। जो बिजली के बिल आते हैं उनको साधारण आदमी सहन नहीं कर सकता । न ही दे पाता है । बिजली तो आती नहीं बिल जरूर आते हैं । होता क्या है कि मीटर रीडर घर बैठा ही मन गढ़न्त बिजली के बिलों की रीडिंग देता रहता है और उसी

के हिसाब से बिल आ जाते हैं। जैसे पहले मीटर रीडिंग का सिस्टम ए0 सी0 साहब ने बताया था, वह सही था कि मीटर के पीछे एक चार्ट लगा हुआ होता था और मीटर रीडिंग के लिये जो आदमी जाता था, वह उस पर रीडिंग लिख देता था, साथ में डेट वगैरह भी लिख देता था। अगर वैसा सिस्टम हो तो ठीक है। घर बैठे ही कोई रीडिंग ले ले तो उससे लोगों को ही भुगतना पड़ेगा.। इसके अलावा एक काम और क्या करते हैं कि घर बैठे ही चार छः महीने का ऐवरेज डाल कर बिल भेज देते हैं। जिसको देने में आदमी को दिक्कत होती है। साधारण आदमी यह बोझा बरदाश्त नहीं कर सकता। एक हजार का दो हजार का बिल इस तरह से आ जाता है। जिससे बिल देने वाले को तकलीफ होती है। जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, उनके बिल बहुत कम आते हैं क्योंकि उनके पास पावर है. गरीब आदमी के बिल उनकी निस्बत ज्यादा आते हैं। अगर इसकी बारीकी में जाएं तो यह सरेआम एक किस्म की बिजली की चोरी हो रही है। मैं तो यह भी कहूंगा कि बड़े-बड़े अधिकारी जैसे एक्सीअन, एस0 ई0, एस0 डी0 ओज वगैरह के नाक तले बड़े कारखानों में बिजली की चोरी बड़े स्तर पर हो रही है जिसका भार गरीब किसान पर डाला जा रहा है। इसी कारण से लाईन लासिज भी ज्यादा हैं। मेरा सरकार से सुझाव है कि सरकार इस विभाग को दो भागों में बांट दे। एक मैनुफैक्चरर विभाग और दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन विभाग। मिसाल के तौर पर एक किसी शहर को बिजली देनी है तो उसे यह कह दिया जाए कि एक लाख यूनिट बिजली इस शहर के लिये देनी है और उसका मीटर सिस्टम अलग से कर दिया जाए और इसका डिस्ट्रीब्यूशन दूसरे विभाग को दे दिया जाए। मैनुफैक्चरर विभाग डिस्ट्रीब्यूशन विभाग को कहे कि 20% परसैन्ट लाईन लासिज निकाल कर के 80 परसैन्ट के पैसे हमें वह दे दे और वे आगे अपने अपने हिसाब से पैसे वसूल करें। इस तरह से बिजली की चोरी बिल्कुल रूक सकेगी और फेयर डिस्ट्रीब्यूशन आफ पावर भी होगी। मैंने इस तरह का सिस्टम विदेशों में भी देखा है। इस तरह से किसी प्रकार की वहां पर बिजली की चोरी नहीं होती। वहां पर तो यह सारा सिस्टम प्राईवेट लोगों के हाथ में है। इस तरह से अगर सरकार बिजली विभाग को दो भागों में बांट दे, तो इसका बोझ फिर सरकार के ऊपर कम पड़ेगा और लोगों को बिजली भी सही समय पर और सही रेटस पर मिलती रहेगी। यह काम अगर सरकार किसी प्राईवेट या पार्टीकुलर एजेन्सी को दे दे तो इसमें कोई नुक्सान नहीं होगा। इससे जहां सरकार का काम घट जाता है वहां करप्शन की बीमारी भी खत्म हो जाएगी। अब जैसे ठेकेदार और अधिकारी मिल कर करप्शन करते हैं, ऐसा करने से यह बात खत्म हो जाएगी और दूसरी तरफ सरकार का काम भी सुचारू रूप से चलेगा। मेरा मुख्य मन्त्री जी से निवेदन है कि बिजली की चोरी को रोकने के लिये ऐसा कोई फूलप्रूफ सिस्टम बनाएं जिससे पता चल सके कि चोरी कहां होती है। इसके अलावा जो ट्रांसफार्मर जले पड़े हैं, उनको जल्द

[श्री राम भजन अग्रवाल]

ठीक करवाया जाए। यहां पर सड़कों के बारे में आंकड़े पढ़ कर सुनाए गए। चौधरी धर्मपाल जी ने भी बताया और चौधरी बंसी लाल जी ने भी इस बारे में बताया। साढ़े तीन सालों के जो सड़कों की रिपेयर के आंकड़े दिए गए हैं, मैं उनकी डिटेल में नहीं जाऊंगा। अगर इन आंकड़ों को हम देखते हैं तो साढ़े तीन सालों में 841 किलोमीटर सड़कों की रिपेयर की गई है जो एक साल की एवरेज 250 किलोमीटर बनती है। दूसरी तरफ सरकार बार बार कहती है कि सारी स्टेट की सड़कों की रिपेयर कर दी है। तो या तो ये आंकड़े झूठे हैं या सरकार का ब्यान झूठा है। इन आंकड़ों के मुताबिक तो सारी स्टेट की सड़कों की रिपेयर नहीं हुई है। अगर अभी रिपेयर का काम हो रहा है, तो गुप्ता जी के ये आंकड़े शायद सच्चे हैं। ये आंकड़े खुद बोलते हैं। इसलिये सरकार को यह नहीं कहना चाहिए कि सारी स्टेट की सड़कें ठीक हो गई हैं।

जहां तक वाटर सप्लाई की बात है इसमें तीन महकमे इनवाल्वड हैं। एक तो इर्रीगेशन का महकमा दूसरा पब्लिक हैल्थ का और तीसरा बिजली का। इन तीनों का आपस में कोआर्डिनेशन नहीं है। अगर हम एक महकमे को कहते हैं कि पानी क्यों नहीं आता तो वह दूसरे महकमे पर आरोप लगा देता है कि इर्रीगेशन वाले हमें नहर से पानी नहीं दे रहे या बिजली वाले हमें बिजली नहीं दे रहे। मेरी सुजैशन है कि ये तीनों आपस में मीटिंग करें और एक दूसरे पर ब्लेम न लगाएं। जहां तक नहरों का सवाल है, बदकिस्मती से हमारा इलाका टेल पर है। क्योंकि नहरों में सिल्ट भरी पड़ी है और उनकी सफाई नहीं हुई है। इसलिये टेल तक पानी नहीं आता। जहां कहीं पानी आता है तो वह भी केवल तीन दिन तक आता है। दूसरी तरफ सिरसा और हिसार जिलों में महीने में 22–23 दिन पानी मिलता है। मेरा सुझाव यह है कि टेल पर टॉप प्रियारिटी पर पैसा खर्च होना चाहिए ताकि लोगों की तकलीफ दूर हो। अगर आप इस तरफ ध्यान देंगे तो हो सकता है कि टेल तक भी पानी पहुंच जाए। चेयरमैन साहब, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि मेरे कई गांवों की कंसोलिडेशन नहीं हुई जिस वजह से वहां के नाले पक्के नहीं बन रहे हैं। नाले पक्के न होने की वजह से खेतों में पानी नहीं लग रहा है। पीने के पानी के लिये एक स्कीम आपने हमें दी थी। वह स्कीम यह थी कि अगर आप वाटर सप्लाई कैनाल वाटर से नहीं कर सकते तो ट्यूबवैल से पानी लें। जिन कुओं का मीठा पानी है, उनमें ट्यूबवैल लगा कर उसको वाटर सप्लाई से जोड़ दें ताकि सब जगह पानी पहुंच जाए। मेरे हल्के के कई गांवों में मीठा पानी है। (इस समय श्री अध्यक्ष पदासीन हुए) अध्यक्ष महोदय, जब हम अधिकारियों से एप्रोच करते हैं कि जिन गांवों में नीचे का पानी मीठा है, आप वहां पर ट्यूबवैल लगा कर पीने के पानी की सप्लाई कर दें तो अधिकारी कहते हैं कि हम पहले उस पानी को टैस्ट करेंगे क्योंकि अगर पानी खराब

होगा तो उससे बीमारी फैलती है। अध्यक्ष महोदय, या तो वे अधिकारी उन गांवों के पानी को एग्जामिन करते नहीं अगर करते हैं तो उसमें कुछ त्रुटियां निकाल देते हैं जिससे उन गांवों में ट्यूबवैल लगाने की स्कीम सिरे नहीं चढ़ पाती है। सरकार से मेरा आग्रह है कि सरकार देहात और शहरों में वाटर सप्लाई के लिये ट्यूबवैल ओरिएन्टिड पालिसी बनाए जिससे लोगों को पीने का पानी मिल सके। अध्यक्ष महोदय, जहां तक सीवर का सवाल है, उसका मेरी कांस्टीच्यूऐंसी भिवानी में बहुत बुरा हाल है। भिवानी शहर के अन्दर सीवर की बहुत बुरी हालत है। पहली बात तो यह कि मेन होल्ज पर ढक्कन नहीं है। अगर कहीं पर ढक्कन हैं तो सीवर के पानी का निकास नहीं होता है सीवर का पानी बाहर आ कर सड़कों पर खड़ा हो जाता है। लोग उस पानी के कारण सड़क के ऊपर से नहीं गुजर सकते। भिवानी के अन्दर सीवर का पानी ओवर फलो हो करके सड़कों के ऊपर चलता है। मैं कहता हूं कि भिवानी शहर में सीवर का बहुत बुरा हाल है। उसकी तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिए। वहां पर सीवर के पानी की निकासी नहीं हो रही है। भिवानी शहर के सीवर का पानी मेरे हल्के के हालुवास के तालाब में जाता है। उस गांव की लगभग 200 एकड़ जमीन में उस पानी के कारण फसल भी नहीं होती है उस पानी को पी कर मवेशी बीमार हो जाते हैं।

श्री अध्यक्ष: अग्रवाल साहब, आप अपनी स्पीच 6.00 बजे तक खत्म कर दें।

श्री राम भजन अग्रवाल: स्पीकर साहब, यदि आप मुझे बोलने के लिये आज टाईम नहीं दे सकते, तो मैं कल बोल लूंगा। मैं अपने हल्के की बातें ही कहना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं कहता हूं कि सीवर के पानी से हालुवास गांव के मवेशी बीमार होते हैं क्योंकि भिवानी शहर के सीवर का पानी उस गांव के तालाब में जा रहा है। मैं भिवानी शहर के सीवर के बारे में सरकार को सुझाव देना चाहूंगा। जैसे सरकार करोड़ों रुपए खर्च करके डैम बनाती है या बड़ी बड़ी दूसरी योजनाएं बनाती है वहां पर इसी तरह से एक बड़ा टैंक बना दिया जाए और उसमें वह सीवर का पानी इकट्ठा कर लिया जाए और वह पानी आबपाशी के लिये किसानों को दे दिया जाए, उससे सरकार को आबियाना मिलेगा तथा लोगों की फसलें भी अच्छी होंगी। आप तो करोड़ों रुपये की बड़ी बड़ी योजनाएं बनाते हैं वह टैंक तो केवल दो चार करोड़ रुपये में बन कर तैयार हो जाएगा। अगर टैंक बना दिया जाए तो हालुवास गांव के लोग बच जाएंगे। उस गांव के लोगों का भला हो जाएगा।

अध्यक्ष महोदय, जहां तक स्कूलों में शिक्षा का सवाल है। स्कूल तो हैं लेकिन उनमें अध्यापक नहीं हैं अगर अध्यापक हैं तो वे 15 दिन के अन्दर दो दो लाख रुपए का गबन करते हैं और स्कूलों में शराब पीते हैं। अगर सरकार उसको

[श्री राम भजन अग्रवाल]

सस्पैन्ड करती है तो कोई पोलिटिकल प्रैशर हो या भाई भतीजावाद उस के कारण वे बहाल हो जाते हैं। इस तरह से शिक्षा का स्तर नहीं सुधर सकता। अध्यक्ष महोदय, मैं तो हाई स्कूल तक पढ़ा हूं। मुख्य मन्त्री जी चाहे कम पढ़े हों लेकिन यहां हाउस के अन्दर प्रोफैसर भी हैं। अध्यक्ष महोदय, जहां-जहां स्कूलों को अपग्रेड करने का सवाल है। मेरे हल्के के गांव कितलाना नीमड़ीवाला पहलादगढ़ और ढाणा नरसांग के स्कूल पिछले 20 साल से अपग्रेड नहीं हुए हैं जबकि यह गांव कमरों की और स्टुडैंटस की संख्या की सारी शर्तें पूरी करते हैं। मेरे हल्के के उन गांवों के साथ भेदभाव बरता जा रहा है। जब से इन गांवों के अन्दर मिडल स्कूल बने हैं तब से मिडल ही हैं। इन स्कूलों में खास तौर से लड़कियां ज्यादा हैं उन गांवों के नजदीक हाई स्कूल भी हैं लेकिन 5 या 7 किलोमीटर की दूरी पर लड़कियां पढ़ने के लिये नहीं जा सकतीं। उन गांवों के स्कूल सभी शर्तें पूरी करते हैं इसलिये उनको अपग्रेड किया जाए। 18.00 बजे | अध्यक्ष महोदय, सरकारी स्कूलों का रिजल्ट क्या है, उसके बारे में क्या कहा जाये, सभी को पता है कि इनका रिजल्ट कैसा आ रहा है?

अध्यक्ष महोदय, अब मैं स्वास्थ्य विभाग के बारे में जिकर करना चाहता हूं। भिवानी में बहुत बढ़िया हस्पताल बनाया गया लेकिन उसके रख रखाव की तरफ कतई ध्यान नहीं दिया जा रहा। न वहां पर बिजली उपलब्ध है और न सफाई की तरफ कोई ध्यान है। बरामदों में कोई लाईट का प्रबंध नहीं है न ही वहां पर दवाईयां हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार के नोटिस में लाना चाहता हूं कि वहां पर करोड़ों रुपये की मशीनरी काफी दिनों से खरीदी पड़ी है, उस मशीनरी को डिब्बों से भी नहीं खोला गया और वह मशीनरी अब आउट डेटिड हो चुकी है। यह कैसी विडम्बना है कि मशीनरी आने के बावजूद भी उसको इस्तेमाल न किया जाये। शायद इसलिये इसको यूज नहीं किया गया, कि कहीं भिवानी का हस्पताल चमक न जाये।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं वहां की नगरपालिका के बारे में जिकर करना चाहूंगा। भिवानी में या दूसरी जगहों पर इनके चुनाव कैसे हुए, वह तो सभी को पता है। आज उनके पास फण्ड्ज की कमी है। भिवानी नगरपालिका के पास पैसे की बहुत कमी है। अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार के नोटिस में लाना चाहता हूं कि सरकार ने एक नियम पास किया था कि जो धार्मिक संस्थाएं हैं, उनसे हाउस टैक्स न लिया जाये लेकिन भिवानी की कमेटी वाले धार्मिक स्थानों से भी टैक्स वसूल करने पर तुले हुए हैं। यदि सरकार ने वह अमैंडमैंट वापस ले लिया है तो फिर हाउस में यह बात आनी चाहिए। आप हैरान होंगे कि गऊशाला जैसी संस्था से भी कमेटी वाले टैक्स लेने के लिए उनके पीछे पड़े हुए हैं। आप देखिए कि क्या गऊशाला से भी बढ़कर कोई धार्मिक संस्था हो सकती है? ये कमेटी वाले उसे भी नहीं छोड़ रहे।

यदि सरकार ने यह ऐग्जमशन वापस ले ली है तो यहां पर बताया जाये नहीं तो फिर क्यों कमेटी वाले उनसे पिछले 10-10 सालों का टैक्स लेने पर तुले हुए हैं। इसी प्रकार से वहां पर कमेटी में जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनका जो प्रोविडैंट फंड (P.F.) का पैसा कटता है, वह उनके खाते में जमा न होकर दूसरे मदों में जमा करके खर्च किया जा रहा है। दूसरे मद में जब कर्मचारियों का पैसा जमा हो रहा है, तो उसका लाभ उन्हें कैसे मिल पायेगा ? इसलिए मेरी सरकार से मांग है कि उनका पैसा ठीक जगह पर जमा होना चाहिए ताकि उनको उसका समय पर लाभ हो सके।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं रोडवेज के बारे में जिकर करना चाहता हूं। मेरे हल्के में बसों की हालत बहुत ही खराब है। सारी बसें बिना खिड़की शीशों के एयरकंडीशंड बना रखी हैं। लगता है सरकार ने मेरे जिले भिवानी के बारे में एयर कंडीशंड बसों की परिभाषा बदल दी है क्योंकि किसी बस में शीशे व खिड़की आदि नहीं है। मुझे लगता है कि सरकार जानबूझ कर ऐसा भेदभाव कर रही है क्योंकि हम अपोजीशन पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। इसी प्रकार से जो सोसायटीज बनाकर लोगों को रोजगार दिया गया था, उस नीति का भी गलत प्रयोग हो रही है क्योंकि रोडवेज की बसें समय पर तो चलती थीं, लेकिन प्राईवेट बसें जो सोसायटीज बनाकर दी गई थीं, यदि उनका चलने का समय 12 बजे का है तो जब तक पूरी सवारियां नहीं हो जाती, वे नहीं चलती। चाहे इसके लिए उन्हें दो अढ़ाई घंटे इंतजार करनी पड़े। यानि यदि उस बस का चलने का समय 12 बजे का है, तो वे 2.30 बजे से पहले नहीं चलती। वे सवारियों का ध्यान नहीं रखती बल्कि अपनी सुविधा के अनुसार सवारियां पूरी करके ही चलती हैं। सरकार ने जो यह एक अच्छी शुरूआत की थी उसका बहुत बुरा हाल हो रहा है यानि उसका गलत प्रयोग हो रहा है। अतः इस बारे में मेरा सरकार से अनुरोध है कि यदि इन सोसायटियों का रूट बढ़ाने की आवश्यकता हो, तो 14-15 किलोमीटर तक रूट बेशक बढ़ा दें ताकि सवारियों को तो फायदा हो सके। (घण्टी) अध्यक्ष महोदय, आपसे मेरी प्रार्थना है कि मुझे अपनी बात कहने के लिए थोड़ा सा और समय दे दीजिए। मैं कन्कलूड कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : सभी को इतना ही टाईम दिया गया है, आप अब बैठें।

श्री राम भजन अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मैंने व्यापार के बारे में भी बात कहनी थी। इस हाउस में मुझे बड़ी तकलीफ है कि गवर्नर अभिभाषण पर भी मुझे बोलने का मौका नहीं मिला। गवर्नर के अभिभाषण पर भी मुझे यह कहते हुए बड़ी शर्म आती थी कि उसमें व्यापारियों के लिये किसी रियायत का जिक्र नहीं, व्यापारियों का जिक्र नहीं, खेती का जिक्र है इसमें व्यापारियों को बिल्कुल इग्नोर किया हुआ है। मुख्य मन्त्री जी जमींदार विरोधी तो हैं ही वह महा व्यापारी विरोधी भी हैं। मुझे गवर्नर अभिभाषण पर बोलने का मौका क्यों नहीं दिया गया ? मैं अपनी बात आपके सामने कहता। अब मैं व्यापारियों के बारे में कहना चाहता हूं तो वह मुझे बिठाना चाहते हैं ताकि मैं अपना मुंह बन्द रखूं और मुझे बोलने न दिया जाए। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : आप इमोशनल न हों, व्यापार के बारे आप अपनी बात कहें (विघ्न) पहले उस सब्जैक्ट पर बोलना चाहिए, जिसमें आप एक्सपर्ट हैं ।

श्री राम भजन अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलना अलाऊ किया है । मैं दो मिनट में अपनी बात कह लूंगा । जहां तक मुर्गी और सूअर पालन का सवाल है, वहां मुर्गी और सूअर पालन का जिकर गुप्ता जी के बजट अभिभाषण में किया गया है । उस काम को बढ़ावा दिया जाता है लेकिन गऊ जैसे पशु के लिए बजट अभिभाषण में कोई व्यवस्था नहीं है, कोई जिक्र नहीं है । कोई गऊशाला का जिक्र नहीं है । अध्यक्ष महोदय, मेरी आपसे प्रार्थना है और निवेदन है कि जैसे आदमियों के अस्पतालों में दवाईयां नहीं हैं, वैसे ही पशुओं के अस्पतालों में भी दवाईयां उपलब्ध नहीं होती हैं जोकि उपलब्ध करवाई जानी चाहिएं । वी0एल0डी0ए0 परेशान हैं । सरकार उनका रजिस्ट्रेशन करे । पशु पालन विभाग पशुओं के अस्पतालों में दवाईयों का इन्तजाम करें । अध्यक्ष महोदय, एक दो बातें मुझे व्यापार के बारे में भी कहनी हैं । यह सरकार व्यापारी विरोधी नीति अपनाए हुए है । अध्यक्ष महोदय, व्यापारी वर्ग हमेशा सरकार का साथ देता है, चाहे वह सरकार भजन लाल जी की सरकार हो चाहे किसी और की सरकार हो । व्यापारी शांति से रहना चाहता है और पूरा टैक्स देना चाहता है लेकिन वह यह आशा भी करता है कि उसे सम्मान मिले, उनको इज्जत मिले । अध्यक्ष महोदय, अभी पिछले दिनों हमारी प्रार्थना पर मुख्य मन्त्री जी ने कृपा कर के बैरियर्ज हटा दिये थे । जय प्रकाश गुप्ता जी ने बताया था कि इससे सरकार को आमदनी ज्यादा हुई है । इसी प्रकार से जब यह आमदनी बढ़ी है, तो इसका मतलब यह है कि व्यापारी तो टैक्स देना चाहता है । अगर सरकार व्यापारियों को सुविधा देगी तो व्यापारी हर प्रकार से सरकार के साथ को-आपरेट करेंगे । अभी पिछले दिनों व्यापारियों ने माननीय मुख्य मन्त्री जी को हिसार में चान्दी से तोला है । (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, जहां तक सेल्ज टैक्स का सवाल है, सेल्ज टैक्स में कई स्लैब्ज न हो कर 2-3 स्लैब्ज कर दी जाएं । अगर टैक्स की 2%, 4%, 6% सलब कर दें तो आप देखेंगे कि उससे स्टेट का रैवेन्यू बढ़ेगा । दूसरे एग्रीकल्चरल इम्पलीमैंटस पर सेल्ज टैक्स नहीं है लेकिन फव्वारा सैट्स पर सेल्ज टैक्स माफ नहीं हैं क्या वे खेती के काम नहीं आते हैं ? जो जमीदार खेती के लिए फव्वारा सैट्स लेते हैं, उनको सेल्ज टैक्स जरूर देना पड़ता है । ऐसी चीजों की तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिए । जहां तक मार्किट फीस का सवाल है, हमेशा सदन के अन्दर यह बात आती है कि हरियाणा के अन्दर मार्किट फीस तीन है, जब कि दिल्ली के अन्दर एक , यू0पी0 में डेढ़ परसैंट, राजस्थान में डेढ़ परसैंट, गुजरात में एक परसैंट, हिमाचल प्रदेश में एक परसैंट है । मार्किट फीस कम होने के कारण व्यापारी पानीपत की बजाय नांगलोई या नरेला जाते हैं । इस कारण हमारे हरियाणा से व्यापार खत्म हो रहा है । इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि जो मार्किट फीस हमारे पड़ोसी राज्यों में कम है तो इसको यहां भी कम किया जावे । अब मुख्य मंत्री जी ने पड़ोसी मुख्य मंत्रियों के साथ इस सम्बन्ध में कुछ मीटिंगें भी की हैं । मैं चाहूंगा

कि टैक्स यू0 पी0, दिल्ली और राजस्थान वालों के बराबर तो कम से कम हम को करना ही चाहिए । और वह यह बताएं कि यह कब तक इम्पलीमैंट करते जा रहे हैं । हम यह नहीं कहते कि दिल्ली से कम टैक्स लें लेकिन पड़ौसियों के बराबर तो कर दें । साथ ही अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि हम नए सदस्यों का भी आप ख्याल रखें और हमें भी अपने हल्कों के बारे में बोलने का मौका दिया करें । इसके साथ ही मैं आपका धन्यवाद करता हुआ अपना स्थान लेता हूं ।

श्री जसविन्द्र सिंह (पेहवा) : अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद । मैं, राम भजन अग्रवाल जी ने जो बात कही है, उसका समर्थन करता हूं कि हम नए सदस्यों को भी बोलने का समय मिलना चाहिए । (शोर) अध्यक्ष महोदय, आज कांग्रेस सरकार से हरियाणा की जनता को कोई उम्मीद नहीं रह गई है कि यह सरकार जनता की भलाई के लिए कोई काम कर सकती है या करेगी । यह जो बजट वित्त मंत्री श्री मांगे राम गुप्ता जी ने पेश किया है, इससे जनता को बहुत उम्मीदें थी कि सरकार जनता की भलाई का काम करेगी । लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ । अध्यक्ष महोदय, किसान की भलाई के लिए खाद की व्यवस्था करना सरकार का मुख्य कर्तव्य होता है । इस बार किसानों को गेहूं की बिजाई के लिए समय पर खाद नहीं मिली और यूरिया खाद तो लोगों को बहुत ही महंगी मिली है । अगर यह सरकार सही तरीके से कृषि को बढ़ावा देना चाहती है, तो इस तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिए । अध्यक्ष महोदय, करनाल में और मेरी कांस्टीचुएंसी में नकली सीड मिला है । किसानों के साथ धोखा हुआ है और आज का किसान इतना जागरूक नहीं है कि नकली बीज मिलने की वजह से वह कोर्ट में जाए जैसा कि आज कानून में प्रावधान है । इस बारे में सरकार को जागरूक होना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय, मैं अपने पेहवा हल्के के बारे में सदन में बताना चाहूंगा । पेहवा का जो वाटर लैवल है, वह आज 60-60 और 70-70 फुट नीचा चला गया है । वहां पर जो पहले ट्यूबवैल्ज लगे हुए थे, उनकी मोटरें 5-10 हार्सपावर की थीं जो कि अब काम नहीं करती हैं । आज किसानों को सबमरसिबल बोर करवाना पड़ रहा है जिसका खर्चा डेढ़-दो लाख तक आता है । स्पीकर साहब, यह ट्यूबवैल 100 फुट गहराई तक लग जाता है और इसमें मोटर भी 25-30 हार्सपावर की लगती है । मैं यह भी कहूंगा कि जैसे रिवाड़ी साईड में रियायत दी गई है, उसी प्रकार हमारे यहां पर भी ज्यादा बिजली पर कम रेट लिया जाए । इस बारे में मंत्री महोदय, ध्यान दें कि जो 25-30 हार्सपावर की मोटर है, उस पर जो आठ परसैन्ट टैक्स लिया जाता है और साथ उस पर 10 परसैन्ट खर्चा भी आ जाता है वह खर्चा बिल्कुल खत्म होना चाहिए जैसे कि छोटी मोटरों पर है । छोटी मोटरों का जिला कुरूक्षेत्र में कोई काम नहीं और न ही इनसे काम चलेगा । इसके साथ-साथ बीमा पोलिसी भी जरूर लागू की जानी चाहिए आज जो डेढ़-डेढ़ लाख रुपये के बोर होते हैं, इस तरह के पहेवा हल्के में भी काफी बोर हुए हैं । मोटर डालने की

[श्री जसविन्द्र सिंह]
वजह से, बजरी डालने की वजह से या फिर पाईप फटने की वजह से इन बोरज पर काफी खर्चा आता है। एक बोर में कम से कम साठ हजार रुपये का पाईप लगाते हैं और 15-20 हजार रुपये की बजरी लगती है तथा बारह या चौदह हजार रुपये बोर करने वाली मशीन ले लेती है तो कुल मिलाकर एक बोर पर 80 हजार रुपये खर्चा होता है। यह नुक्सान वहां पर लोगों का हुआ है इसलिए सरकार को इस बारे में जरूर बीमा पोलिसी लागू करनी चाहिए।

स्पीकर सर, मेरे हल्के में बीबीपुर लेक है जो कि पार्टीशन से पहले की है। उस वक्त तो विदेशी सरकार थी। उस समय पता नहीं कैसे-कैसे किसानों से जमीन लेकर वह बनायी गयी लेकिन सर, आज उन किसानों का बहुत नुक्सान हो रहा है। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि उसका भी मुआवजा किसानों को जरूर दिया जाना चाहिए। वहां पर किसानों की जीरी की फसल तो कभी होती ही नहीं और गेहूं की फसल भी खराब हो जाती है। इसलिए सरकार को उन किसानों को कम से कम एक फसल का तो मुआवजा अवश्य ही देना चाहिए। सर, मेरे हल्के पेहवा में दो मंडियां गुमथला और इस्माईलाबाद हैं। ये मंडियां कभी 1977 में चौ० देवी लाल जी ने बनायी थीं लेकिन वह आज तक भी चालू नहीं की गयीं। इसलिए उन मंडियों को चालू किया जाना चाहिए। इसके अलावा जो गन्ने के कंडे लगाए हुए हैं, वे बहुत छोटी कैपेसिटी के हैं। मैं सरकार से कहूंगा कि इनकी इतनी कैपेसिटी जरूर की जानी चाहिए ताकि ट्रैक्टर और ट्राली का वजन एक साथ हो जाए। इनकी ज्यादा कैपेसिटी न होने की वजह से ट्रैक्टर कंडे से उतारकर खड़ा करना पड़ता है जिसकी वजह से काफी दिक्कत आती है और दुर्घटनाएं भी बहुत ज्यादा होती हैं। इसके बाद मैं एक बात और सरकार के नोटिस में लाना चाहता हूं कि हमारे हल्के में जो नरवाना ब्रांच है, उसके अंदर और बीबीपुर लेक के अंदर कम से कम 25-30 गांव आते हैं। जब वहां पर बारिश का पानी होता है तब दिक्कत होती है। जो पृथला सप्लाई चैनल है, जिसके द्वारा मारकंडा से पानी बीबीपुर लेक में डाला जाता है, वहां पर जब बारिश होती है तो उस पानी को निकालने के लिए केवल थोड़े से ही पाईप नीचे दबे हुए हैं जिनकी वजह से बरसात का सारा पानी नहीं निकल पाता। पृथला सप्लाई चैनल बीबीपुर लेक की जड़ में जाकर खत्म होता है जिसकी वजह से पानी नहीं जा पाता है और फसलों को बहुत ज्यादा नुक्सान होता है। मैं इसके बारे में मंत्री जी से कहूंगा कि वहां और साईफन पाईप लगाए जाएं ताकि फसलों का नुक्सान न हो और पानी आराम से निकल सके। मैं नेहरा साहब से एक और गुजारिश चाहूंगा कि पहले जो हमारे राईस सूट्स थे, वे बड़े थे। जैसे कुरूक्षेत्र एरिया में हमारे यहां का पैडी का एरिया है, अब वह राईस सूट्स बहुत छोटे कर दिए गए हैं। हमारे अपने ही वक्त में जहां पहले 80-80 एकड़ पर तकरीबन छः-छः इंच के ये राईस सूट्स थे। लेकिन अब वे केवल तीन इंच के ही रह गए हैं ताकि जिन जगहों पर वाटर लैवल नीचे चला गया है, वहां पर पानी बढ़ाना

चाहिए था लेकिन बढ़ाने के बजाए उन के साईज कम कर दिए गए हैं। सर, अब तो फसलें अगेती होने लगी हैं इसलिए राईस सूट्स भी जून के पहले सप्ताह में दे दिए जाने चाहिएं और उनका साईज भी वही होना चाहिए जो आज से बीस या पच्चीस साल पहले था। अगर आप उनका साईज बढ़ा नहीं सकते तो कम से कम पहले जितना तो जरूर ही करें। इसी तरह से नरवाना ब्रान्च है। स्पीकर सर, मेरे और आपके हल्के के साथ बहुत ज्यादती हुई है। जब एम0 आई0 टी0 सी0 के ट्यूबवैल्ज लगाए गए थे तो मैंने इसके बारे में पहले भी कई बार चर्चा की है कि या तो इन ट्यूबवैल्ज को बंद कर दिया जाए या फिर इनका पानी उसी इलाके में देना चाहिए जहां ये लगे हुए हैं। (विघ्न) आपके वक्त में भी बहुत ज्यादती हुई है। इसी तरह से मैं नेहरा साहब से कहना चाहूंगा कि वहां एक सप्लाई कैनाल लिफ्ट माईनर है, जहां पर मोटर लगाकर भाखड़ा नहर में पानी डाला जाता है और वहीं पर पानी लिफ्ट करके उन किसानों को भी दिया जाता है जिसकी वजह से दोहरा खर्चा होता है। क्योंकि वहीं लिफ्ट करके पानी नरवाना ब्रांच में डाल रहे हैं और वहीं उन किसानों के खेतों में भी पानी दे रहे हैं इसलिए इसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि बिजली का खर्चा ज्यादा है। उन ट्यूबवैल्ज का पानी वहां के किसानों को ही दिया जाना चाहिए ताकि जो वाटर लेवल नीचे चला गया है, उससे थोड़ी सुविधा उनको मिल सके।

इसके अलावा यहां पर शिक्षा के बारे में नकल रोकने के बारे में भी बहुत कुछ कहा गया और शिक्षा के सुधार के बारे में भी चर्चा हुई। शिक्षा के सम्बन्ध में मेरा कहना यह है कि पिहोवा हल्के का कोई स्कूल ऐसा नहीं है, जहां टीचरों की संख्या पूरी हो। बहुत से स्कूलों में तो एक भी टीचर नहीं है। बिल्डिंग्ज़ का बुरा हाल है। गुमथला में स्कूल की बिल्डिंग पूरी तरह से अनसेफ है। उसके बारे में चिट्ठी भी लिखी है लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। स्पीकर सर, स्कूल बिल्डिंग्ज़ के साथ-साथ कम से कम टीचर्ज़ की भरपाई तो करें। बच्चे तो वृक्षों के नीचे बैठकर भी पढ़ लेंगे लेकिन वहां अध्यापक तो हों। शिक्षा मंत्री जी इस बारे में विशेष ध्यान दें। मेरे हल्के में कई गांव हैं जिनके नजदीक कोई भी हाई स्कूल नहीं है। लगभग 14-15 किलोमीटर की दूरी पर एक स्कूल है जो मिडल स्कूल है। उसको अपग्रेड करके हाई स्कूल किया जाए।

अध्यक्ष महोदय, ला एण्ड आर्डर के बारे में प्रदेश की हालत बहुत खराब है। टोहाना में डा0 स्वर्ण सिंह की हत्या कर दी गई। मुख्य मंत्री जी बड़े-बड़े खोखले दावे करते हैं कि प्रदेश का माहौल ठीक है। लेकिन जुर्म और ज्यादतियां बढ़ती जा रही हैं। छोटे से झगड़े को लेकर डा0 स्वर्ण सिंह को मार दिया गया। छोटे से बच्चे को सारी रात घर से बाहर बितानी पड़ी। रिश्तेदार को जख्मी किया गया। मैं बात को ज्यादा बढ़ाना नहीं चाहता। जब से, 1982 में एशियाड हुआ था, तब से इस प्रदेश का माहौल खराब हुआ है। विशेष रूप से जब चौधरी भजन लाल

[श्री जसविन्द्र सिंह]
प्रदेश के मुख्य मंत्री होते हैं तो मायनौरिटी क्लास के लोगों के साथ बहुत जुल्म और ज्यादतियां होती हैं ।

मुख्य मन्त्री (चौधरी भजन लाल) : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत सीरियस ऐलीगेशन है कि माइनौरिटी क्लास के साथ ज्यादती होती है । यह हाउस की कार्यवाही से निकालिए । किसी माइनौरिटी क्लास के साथ, हरिजन के साथ, गरीब के साथ ज्यादती नहीं होती है । ऐसी बेबुनियाद बात इनको हाउस में नहीं कहनी चाहिए ।

श्री जसविन्द्र सिंह : स्पीकर सर, फतेहाबाद में जो कुछ हुआ था । एक इंस-पैक्टर के बारे में कहा गया था । (विघ्न)

श्री अध्यक्ष: जसविन्द्र सिंह जी, आप इस ढंग से न बोला करें, इससे माहौल खराब होता है ।

श्री जसविन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, एक बच्चा पांचवी क्लास में पढ़ता था कुछ लोगों ने डेरे पर धावा बोल दिया उसको उठाकर ले गए और बांधकर उसको पीटा । बाद में उस बच्चे को होश आ गया । डेरे पर जाकर उसने अपने बाप को सब कुछ बताया । साढ़े पांच बजे वे रिपोर्ट करने के लिए थाने आ गए । साढ़े नौ बजे तक उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी गई । आज तक भी कोई पुलिस वाला उनका हाल-चाल पूछने के लिए नहीं गया । मैंने ए० एस० आई० से पूछा तो उसने कहा कि मेरे पास सात बजे रिपोर्ट आई है । ऐसी बहुत सी बातें हैं जो हुई हैं । लोगों के साथ जुल्म और ज्यादतियां हो रही हैं ।

स्पीकर सर, इसी तरह से नौकरियों के मामले में मैं एक बात सरकार के ध्यान में लाना चाहूंगा । सरकार ने कहा था कि जो लोग दो साल की नौकरी पूरी कर लेंगे, उनको पक्का कर देंगे । कुरुक्षेत्र में सैन्ट्रल को-आपरेटिव सोसायटी में 6-6 साल से जो लोग लगे हुए हैं, उनको भी अभी तक पक्का नहीं किया गया । मेरा अनुरोध है कि उनको जल्दी से जल्दी पक्का किया जाए ।

अध्यक्ष महोदय, सड़कों का सारे हरियाणा प्रान्त में बुरा हाल है । इस मामले में अपोजीशन के विधायकों के साथ ज्यादती हो रही है । पहेवा में सड़कों पर कोई रोड़ी वगैरह नहीं डाली गई । डांगी साहब जब पी० डब्ल्यू० डी० मिनिस्टर थे, तब वहां गए थे और उन्होंने अनाउंस किया था कि यह सड़क एक साल के अंदर बना दी जाएगी । स्पीकर साहब, यह सड़क है अधोया से कड़ा साहब । वहां पर अखण्ड पाठ भी रखा हुआ था । कांग्रेस के प्रधान मलिक धर्म पाल सिंह जी, सरदार तारा सिंह और मुख्यमन्त्री महोदय भी वहां पर गए थे और देसी घी का कड़ाह प्रसाद खा कर आ गये थे लेकिन इस सड़क का अभी तक कुछ नहीं बना । यह बड़े ही दुःख की बात है । आज भी वह सड़क आने-जाने लायक नहीं है । इसी तरह से

मलिकपुर से वाया लुखी कुरुक्षेत्र और टीकरी से वाया छैला कुरुक्षेत्र की सड़क भी बिल्कुल टूटी पड़ी है। इसकी रिपेयर जरूरी है। स्पीकर साहब, आज से तीन-चार महीने पहले मैं आपके इलाके पुंडरी की ओर गया था। वह सड़क भी बिल्कुल टूटी पड़ी है। गड्ढे पड़े हुए हैं। आपको भी शायद इसका पूरा ज्ञान होगा लेकिन सरकार का इन सड़कों की ओर कोई ध्यान नहीं है। इसलिये सरकार इस ओर ध्यान दे।

इसी तरह से बिजली के बारे में भी कहना चाहूंगा कि गांव थाना का जो पावर हाउस है, वह 132 के0 वी0 का है और वह सदा ही ओवर लोडिड रहता है। उसके साथ एक और 132 के0 वी0 का ट्रांसफार्मर लगाया जाए। अगर यह नहीं हो सकता तो पहले लगे हुए ट्रांसफार्मर की कैपैसिटी बढ़ाई जाए। इसी तरह से अजराना कलां में भी पावर हाउस की कैपैसिटी दुगुनी की जाए।

स्पीकर साहब, पेहवा एक तीर्थ स्थान है। वहां पर यात्रियों के निवास के लिये, उनकी सहूलियत के लिये, रहने के लिये कोई यात्री निवास नहीं है। मुख्य मंत्री महोदय वहां पर एक बार गये थे। वहां के किसान उन्हें मिले थे और उन्होंने वहां पर कोई रैस्ट हाउस या धर्मशाला बनाने के लिये उनसे प्रार्थना भी की थी लेकिन आज तक सरकार की ओर से किसानों की सुविधा के लिये व यात्रियों की सुविधा के लिये कोई प्रबन्ध नहीं किया गया है। यह बड़े ही दुख की बात है। मैंने टूरिज्म कारपोरेशन की तरफ से भी इस बारे में काफी कोशिश की है लेकिन सब बेकार रही है। मैंने इस बारे में एक दो प्रश्न भी किये थे, लेकिन सब व्यर्थ गए।

इसके साथ-साथ मैं ट्रांसपोर्ट विभाग से भी कहूंगा कि यह पेहवा का इलाका सारे भारत में एक पवित्र स्थान माना जाता है। सारे भारत से लोग दूर-दूर से यहां पर आते हैं। यहां पर यात्रियों के लिये बस-सेवा भी होनी चाहिये ताकि लोगों को दिक्कत न हो। इसके साथ एक और गुजारिश है कि जो बड़े-बड़े गांव हैं, जैसे लुखी, अजराना कलां, गुमथला इन गांवों से पेहवा के लिये सुबह का टाईम बस सेवा का होना चाहिये ताकि वहां से बच्चे स्कूल, कालेज ठीक समय पर पहुंच सकें और उस बस का समय सुबह 8 बजे या उससे पहले कर दें तो बेहतर रहेगा। इससे बच्चों को कोई दिक्कत नहीं रहेगी।

इसके साथ-साथ स्पीकर साहब, मैं सरकार का ध्यान इस ओर भी दिलाना चाहूंगा कि मधु डेयरी का जो गन्दा पानी है, वह सन्दौला माईनर में पड़ता है। इस बारे में भी कई बार कहा जा चुका है कि इस पानी को किसी और साईड पर डालने का प्रबन्ध किया जाए क्योंकि यह गन्दा पानी पीने से पशु बीमार होते हैं और किसानों की फसलों का भी काफी नुकसान होता है। इसी तरह से शाहबाद शूगर मिल का जो पानी है, वह भी साथ लगते गांवों में जाता है और खेतों को खराब करता है। इस ओर सरकार ध्यान दे। इसके साथ एक बात की ओर मैं स्पीकर

[श्री जसविन्द्र सिंह]

साहब, सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जो रैस्ट हाउसिज पेहवा और अजराना कलां मंडी में है, वे भी दोनों रुके पड़े हैं । एक में पुलिस स्टेशन है और दूसरे रैस्ट हाउस में किसी एक जज साहब की रिहायश है । इन दोनों रैस्ट हाउसिज के बारे में सरकार को कुछ सोचना चाहिये और पुलिस स्टेशन व जज साहब की रिहायश का कहीं और बन्दोबस्त करना चाहिये ताकि यहां पर किसानों को ठहरने में किसी प्रकार की असुविधा न हो सके । इन सारी बातों को देखते हुए मैं तो यह कहूंगा कि मुख्य मन्त्री अगर किसानों के हितों का ध्यान नहीं रख सकते, लोगों के राईट्स की हिफाजत अगर नहीं कर सकते तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिये । इन बातों के साथ वित्त मन्त्री महोदय ने जो यह बजट पेश किया है, मैं इसका विरोध करते हुए अपना स्थान लेता हूं । धन्यवाद ।

बैठक का समय बढ़ाना

श्री अध्यक्ष : अगर सदन की सहमति हो तो बैठक का समय दस मिनट के लिए बढ़ा दिया जाए ।

आवाजें : ठीक है जी ।

श्री अध्यक्ष : बैठक का समय दस मिनट के लिए बढ़ाया जाता है ।

वर्ष 1995-96 के बजट पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)

डा० राम प्रकाश (थानेसर) : अध्यक्ष महोदय, बजट पर सदस्यों ने अपने विचार रखे हैं । मैं कुछ बातों की ओर इस सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं । पिछली बार भी एक बात की चर्चा की थी कि एस० वाई० एल० को पिछले कई सालों से बरसात के दिनों में पंजाब एक ड्रेन के तौर पर इस्तेमाल करता आया है । ज्योतिसर के पास दो किलोमीटर अपस्ट्रीम पर यह चैनल हर बार एक ही जगह से टूटती है, जिसकी वजह से मेरे हल्के के कई गांव, नरकातारी, जोगना खेड़ा, गुलाब गढ़ और डब खेड़ी वगैरह और शहर का काफी हिस्सा जैसे शान्ति नगर और दीदार नगर इत्यादि को यह डुबो देती है । एस० वाई० एल० जो लाईफ लाईन होनी चाहिए थी पर यह काफी बड़े क्षेत्र के लिए डैथ लाइन बन जाती है । उससे फसलें तबाह हो जाती हैं और शहर की गलियों की बुरी हालत हो जाती है । विकास पर जो खर्चा हो रहा है, वह भी बर्बाद हो जाता है । बरसात के दिनों में सात आठ साल से पंजाब इसको इसी तरह से इस्तेमाल कर रहा है । मैं चाहूंगा कि सरकार इस बात की ओर ध्यान दे । इस बार बरसात से पहले ऐसे पग उठाए जाएं कि जिस एक ही

प्वायंट पर यह नहर टूटती रही है, वहां दोबारा ऐसा न हो । उसके लिए मैं सुझाव देना चाहता हूं कि ढांड के निकट बढ़ेड़ा हैड वकर्स को बचाने के लिए पंजाब सीमा पर पानी को रोका जा सकता है । जब तक स्थाई तौर पर हमें पानी नहीं मिलता है, तब तक इसकी व्यवस्था की जा सकती है । झांसे के निकट इसको रोका जा सकता है । ज्योतिसर के नजदीक बांध बना कर एस्केप के जरिए इसे झील में डालने का काम किया जा सकता है । इस्माइलाबाद से पहेवा जाते समय मारकण्डा पर जो पुराना पुल है, वहां के निकट कन्थला सप्लाई चैनल से बीबीपुर झील भरी जा सकती है । यही इस सप्लाई चैनल का मकसद था । इस तरह से हम इस पर विचार करें । एक्सपर्ट्स की कमेटी बना कर सरकार इस बात का निर्णय ले ताकि यह दोबारा वहां से न टूटे ।

अध्यक्ष महोदय, मैं अब कुछ शिक्षा के बारे में कहना चाहता हूं । जो इसमें सुधार किए गए हैं, जहां मैं उनका पूरा स्वागत करता हूं, वहां एक दो सुझाव भी देना चाहता हूं । सरकार को मास्टर्ज और मिस्ट्रैसिज की कुल संख्या, जिसमें परमानैंट और टैम्पोरेरी दोनों किस्म के पद थे, के आधार पर सिलैक्शन ग्रेड देने का निर्णय लेना चाहिए था । क्योंकि पहले टोटल पोस्टों पर सिलैक्शन ग्रेड नहीं दिया गया था इसलिए इस कारण काफी लोग कोर्ट्स में गए, हाई कोर्ट में गए । एल0 पी0 ए0 नं0 136 जो 1986 में दायर किया गया था, उसका फैसला 15 जनवरी, 1990 को हुआ । मैं समझता हूं कि जब कोर्ट ने एक बार फैसला कर दिया कि टोटल पोस्टों पर, चाहे परमानैंट हों या टैम्पोरेरी हों, उनके आधार पर सिलैक्शन ग्रेड दिया जाएगा तो फिर जो बाकी बचे हुए केस थे, उनका भी उसी आधार पर फैसला होना चाहिए था । लेकिन ऐसा नहीं हुआ जिसकी वजह से पिछली सरकार के जमाने में टीचर्ज को केस दायर करना पड़ा था । अध्यापकों को बार-बार कोर्ट में जाना पड़ा । मैं समझता हूं कि जब एक बार निर्णय हो गया तो उसे सभी डिजर्विंग केसिज पर लागू कर देना चाहिए वरना काफी लोगों को कन्टैम्पट आफ कोर्ट के केस दायर करने पड़ेंगे । मैं एक और सुझाव देना चाहता हूं कि अगर प्राइमरी स्कूल की शिक्षा बेहतर बन पाएगी, तभी मिडल और हाई स्कूलों का रिजल्ट अच्छा होगा । हमने जो प्राइमरी स्कूलों के ब्रांच स्कूल खोल रखे हैं, इनके बारे में अगर ऐसा निर्णय लिया जा सके कि इन ब्रांच स्कूलों को पूरे प्राइमरी स्कूल्ज में कनवर्ट कर दिया जाए तो जिसका प्राइमरी स्कूल जहां अटैच्ड है, उसकी भी हालत सुधरेगी और जो ब्रांच स्कूल बने हुए हैं, उनको भी सुविधा होगी । एक बात मैं स्कूल शिक्षा बोर्ड के बारे कहना चाहता हूं । मैंने यह बात पिछली बार भी कहनी चाही थी कि वहां पर जो शिड्यूल कास्ट्स और बैकवर्ड क्लासिज के एम्पलाइज़ हैं, उनको रोस्टर प्वायंट पर सीनियारिटी नहीं दी गई । रोस्टर प्वायंट पर सीनियारिटी एक मान्यता प्राप्त विचार है । उसके मुताबिक उनको सीनियारिटी मिलनी चाहिए ।

कुरुक्षेत्र के बारे में कुछ बातें मैं इस नाते से भी निवेदन करना चाहूंगा कि

[डा० राम प्रकाश]

वहां पर बहुत जल्दी ही सूर्य ग्रहण का मेला आएगा उससे पहले अगर हम कुछ चीजों की तैयारी कर लें तो वह सभी के लिए फायदेमंद रहेंगी । सरकार ने एक निर्णय लिया है कि महाभारत पर पैनोरमा प्रोजैक्ट तैयार किया जाएगा । लाईट एंड साउंड के माध्यम से जो महाभारत के दृश्य हैं, वे प्रदर्शित किए जाएंगे । इस पर पहले काम शुरू किया जाए ताकि मेले के वक्त पर अगर वह पूरे मुकम्मल न हों तो कुछ हिस्सा जरूर लोगों को देखने के लिए मिले । ऐसा बहुत बेहतर होगा । ब्रह्म सरोवर के नए हिस्से की पेवमैंट शुरु की गई है, उसका काम क्वालिटी का काम नहीं है । अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि अगर आप वहां पर अधिकारियों की जिम्मेदारी लगाना चाहें तो लगाएं लेकिन वहां जो पत्थर बिछाए गए हैं, वे नीचे की जमीन समतल किए बिना बिछाए गए हैं जिसकी वजह से वहां पर टूट-फूट ज्यादा है । क्वालिटी वर्क न होना तो अच्छी बात नहीं होगी । एक बात मैं यह भी कहना चाहूंगा कि हिन्दुस्तान में अनेकता में एकता है । उस नाते हिन्दुस्तान की अलग-अलग जगहों पर कलात्मक ढंग से जो आर्कीटैक्चर का स्टाइल है, अगर ब्रह्म सरोवर के तीन साईड में जो कंस्ट्रक्शन करनी है, वह उस आधार पर की जाए और बाहर का ढांचा एक जैसा रखा जाए, दूसरी बात यह कि है कि राज्य सरकार को इस बात के लिए प्रेरित किया जा सके तो मैं समझता हूं कि जहां खर्चा बचेगा वहां दूसरे प्रान्तों की कला भी प्रदर्शित हो पाएगी । पीपली से यूनिवर्सिटी के थर्ड गेट तक सड़क को फोर लेनिंग करना बहुत ही जरूरी है । अम्बेडकर चौक तक या छठी बादशाही गुरुद्वारा के सामने का जो हिस्सा है, कम से कम वहां तक हर हालत में मेले से पहले फोर लेनिंग मुकम्मल होनी चाहिए क्योंकि वहां से सन्निहित सरोवर होता है । अगर बिड़ला चौक, जहां पर महाराणा प्रताप सिंह का बुत है, वहां तक उसको फोर लेनिंग कर दी जाए तो और भी बेहतर होगा । सरकार ने जी० टी० रोड के बारे में फैसला किया था । उस फैसले के तहत जी० टी० रोड जहां-जहां शहरों के बीच में से जाती है, वहां-वहां उसकी फोर लेनिंग की थी । इसी तरह से जो स्टेट हाईवे शहरों के बिल्कुल बीच में से निकलते हैं और जिनके दोनों तरफ आबादी है, अगर वहां पर जगह है तो उनकी फोर लेनिंग अवश्य की जानी चाहिए । मैं यह बात यह चीज मद्दे नजर रख कर कह रहा हूं कि पीपली से यमुनानगर जो सड़क जाती है, वह बहुत जरूरी सड़क है । उस सड़क पर बड़ा भारी यातायात है । अगर उस सड़क का कस्बा के बीच का हिस्सा फोर-लेन कर दिया जाए तो एक्सीडैंट्स से काफी छुटकारा मिल सकता है ।

यदि हमने कुरूक्षेत्र शहर को मेले के लिए तैयार करना है तो कोआप्रेटिव बैंक के पास और सुभाष मंडी के पीछे जो बहुत वर्षा में ज्यादा पानी खड़ा रहता है, उस पानी को निकालने का प्रबंध किया जाना चाहिए । बरसात के दिनों में वहां बहुत बुरा हाल होता है । उस पानी के निकालने का कोई प्रबंध करने के लिए म्यूनिसिपल कमेटी को अगर स्पैशल ग्रांट देनी पड़े तो वह दी जाए । वहां पर

इतना पानी खड़ा होता है कि जिसका अनुमान लगाना असम्भव है । किसी समय कुरुक्षेत्र में रेलवे लाईन पर ओवर ब्रिज बना था, वह उतना चौड़ा नहीं है जितना चौड़ा होना चाहिए । इस कारण मेले के दिनों में और भी ज्यादा दिक्कत आएगी । अध्यक्ष महोदय, सरकार से मेरा निवेदन है कि वहां पर रेलवे लाइन के नीचे यदि सब-वे बनाया जा सके या फाटक बना कर लाइट ट्रैफिक वहां से निकालने का साधन बनाया जा सके तो बहुत अच्छा रहेगा । वहां हर रोज मौतें होती हैं । अध्यक्ष महोदय, आप खुद वहां के रहने वाले हैं आपको तो पता है । वहां जो पुल बनाया गया है, वह एक खूनी पुल बना हुआ है । अध्यक्ष महोदय, जहां-जहां पर भी स्लम्ज हैं, उनको दूर करने के लिए सरकार ने बहुत अच्छे कदम उठाए हैं लेकिन जिस ढंग से पैसा उसके लिए लगाया जाता है, वह ठीक नहीं है ।

बैठक का समय बढ़ाना

श्री अध्यक्ष : अगर हाऊस की सैन्स हो तो हाऊस का समय पांच मिनट के लिए बढ़ा दिया जाए ।

आवाजें : ठीक है जी ।

श्री अध्यक्ष : हाउस का समय 5 मिनट के लिये और बढ़ाया जाता है ।

वर्ष 1995-96 के बजट पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)

डा० राम प्रकाश : मैं कह रहा था कि सलम्ज को दूर करने के लिए सरकार ने जितना पैसा लगाया है उससे सारी बात बनने वाली नहीं है । इसलिए हम कोई ऐसा प्रोग्राम बनाएं, क्रैश प्रोग्राम बनाएं जिससे हरियाणा में जो गंदी बस्तियां हैं, उनका सुधार हो सके । इसके लिए हमें कोई डैड लाईन निश्चित करनी चाहिए । जैसे सरकार ने पानी पहुंचाने के लिए, बिजली पहुंचाने के लिए सड़कों का जाल बिछाने के लिए किया था । ऐसी कोई योजना बना कर गंदी बस्तियों का सुधार हम निश्चित अवधि में पूरा कर पाएंगे । यह एक अच्छा कदम होगा । मैंने पिपली के बारे में यह निवेदन करना है कि पिपली रोड से एक सड़क पिपली के अन्दर की तरफ जाती है उसका बहुत बुरा हाल है । यह सड़क हाई स्कूल और पुरानी मण्डी के बीच में से निकलती हुई बाकी बस्तियों में से होकर श्मशान घाट की तरफ जाती है । वह सबसे मेन गली है । वहां पर इसका बहुत बुरा हाल है । क्योंकि यह मण्डी के बिल्कुल दरवाजे के पास से निकलती है, इसलिए मार्किट कमेटी से भी मदद ली जा सकती है क्योंकि वहां की मार्किट कमेटी मुनाफे में है । यदि इसे पक्का कर दिया जाता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं रहेगी ।

[डा0 राम प्रकाश]

एक बात मैं पशुपालन विभाग के बारे में कहना चाहता हूं । पशु पालन विभाग की 2,000 से ज्यादा संस्थाएं हैं जिसमें डिप्लोमा धारक भी काम करते हैं और डिग्री होल्डर्ज भी । सारी डिस्पेंसरीज में डिग्री होल्डर्ज नहीं लगे हुए हैं । ऐसी डिस्पैंसरीज हैं, जिनमें डिप्लोमा वाले भी हैं और डिग्री होल्डर्ज भी हैं । वहां पर एक डिग्री होल्डर होता है और बाकी डिप्लोमा वाले होते हैं । अगर उनको पशुओं का इलाज करने की स्वीकृति दे दी जाएगी तो अच्छा होगा । पिछले दिनों एक कानून लागू किया गया था । यह इण्डियन वैटर्नरी कौंसिल एक्ट 1983, है उसको लागू करना पड़ा जिसकी वजह से बहुत दिक्कत है । यह कर्मचारियों की भी एक मांग है कि अगर उनको इलाज करने की इजाजत दे दी जाए तो मैं समझता हूं कि यह फायदेमंद रहेगा । वैटर्नरी साईंस कालेज हिसार से लोग डिग्री लेते हैं वहीं से डिप्लोमा लेकर आते हैं । सम्बन्धित नियम में संशोधन कर देना चाहिए । मैं एक बात बैकवर्ड क्लासिज कमीशन के बारे में कहना चाहता हूं । मुझे नहीं पता कि उसकी क्या रिपोर्ट है लेकिन बैकवर्ड शब्द रिलेटिव टर्म है कि आदमी किस समूह विशेष के विद रिस्पैक्ट टू बैकवर्ड है । जो जाति किसी क्षेत्र में न्यूमैरिकली प्रोमिनेंट है संख्या की दृष्टि से सबल है, जिसके बड़े-बड़े अफसर हैं जिसके मिनिस्टर हैं, जिनके चीफ मिनिस्टर रह चुके हों, अगर उनको बैकवर्ड क्लासिज में घोषित कर दिया जाएगा तो जो असली बैकवर्ड लोग हैं, यह उनके हकों पर बहुत बड़ा डाका होगा । मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि 47 साल में मुल्क के आजाद होने के बाद से जो पहले बैकवर्ड रहे हों, उनमें से जो फार्वर्ड हुए हों, उनको लिस्ट में से निकाला जा सकता है । लेकिन 47 साल पहले जो बिरादरी फार्वर्ड थी, अगर उनको बैकवर्ड घोषित कर दिया जायेगा तो यह एक अजीब स्थिति होगी । वे लोग जो अपने हकों के लिए संघर्षरत हैं, जिनको आज हक मिला हुआ नहीं है, उनका हक दूसरे लोग ले लेंगे । उनके पास केवल रोने का हक है, शायद वह भी छिन्न जायेगा । अगर कोई यह कहे कि हम 27 प्रतिशत को अनैक्चर 'ए' और 'बी' में बांट देंगे तो ऐसा संभव नहीं है । आप प्रांत में तो यह कर सकते हैं लेकिन अखिल भारतीय स्तर पर जिन नौकरियों की नियुक्ति की जाती है उन नौकरियों में 'ए' और 'बी' का विधान नहीं है । वहां उनका हिस्सा दूसरी बिरादरियां ले जाएंगी । इस नाते एक अजीब हालत पैदा होगी । जिस वर्ग को सरकार राहत देना चाहती है, उनको राहत नहीं दी जा सकेगी । (विघ्न) अदर बी0 सीज0 हैं, केन्द्र में सेन्ट्रल सर्विसिज के लिहाज से एक ही लिस्ट होगी । उनकी दो लिस्टें नहीं होंगी या तो केन्द्र सरकार-उनकी दो लिस्ट करना मान ले । अगर केन्द्र सरकार उनकी दो लिस्ट करती है, तब तो और बात है अन्यथा कोई बात बनने वाली नहीं है ।

अंतिम बात मैं यह कहना चाहता हूं कि इस सदन में बहुत से सदस्य आरोप प्रत्यारोप की झड़ी लगाते हैं । अध्यक्ष महोदय, एक व्यक्ति दूसरे को बेईमान कहता है और दूसरा पहले को बेईमान बताता है लेकिन इस बात का कोई फैसला नहीं

होता कि सत्य और असत्य क्या है । इस बात को स्पष्ट करने के लिए मैं उम्मीद करूंगा कि यह सरकार एक बहुत ही अच्छा कार्य करेगी और यह लोकपाल बिल लाए । लोकपाल की नियुक्ति हो जाने के बाद अपनी बात कहने के लिए और अपनी बात सिद्ध करने के लिए एक जरिया हो जाएगा । अध्यक्ष महोदय, आज स्थिति यह है कि कोई भी बात हवा में उछाल दी जाती है और एक दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगाए जाते हैं । अगर लोकपाल की नियुक्ति हो जाएगी तो अरोप लगाने वाले को भी इस बात का ध्यान रहेगा कि उसकी बात जनता के सामने जाएगी और सच्चाई को जानकर जनता झूठे इल्ज़ाम लगाने वाले का साथ नहीं देगी ।

Mr. Speaker : Now the House stands adjourned till 9.30 A.M. tomorrow the 21st March, 1995.

***18.45 Hrs.** (The Sabha then adjourned till 9.30 A.M. on Tuesday, the 21st March, 1995).

26806—H.V.S.—H.G.P., Chd.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]